सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

18 फरवरी, 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना ।

अष्टादश विधान सभा — बुधवार, तिथि 18 फरवरी, 2026 ई0
द्वितीय सत्र — 29 माघ, 1947 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।
अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण और मार्गदर्शन दोनों चाहिए इस व्यवस्था और नियमन से संबंधित विषय के लिए । आपसे आग्रह है, एक मिनट का विषय है सर...

अध्यक्ष : शून्यकाल में उठा लीजिएगा, शून्यकाल में ।

श्री जिवेश कुमार : जी सर ।

अध्यक्ष : श्री आई0पी0 गुप्ता ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न सं0–48, श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या–75, सहरसा)

(मुद्रित उत्तर)

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अस्वीकारात्मक।

वस्तुस्थिति यह है कि आउटसोर्सिंग से नियुक्त किये गये कर्मचारी को प्रत्येक 6 दिन कार्य के पश्चात एक दिन का सवैतनिक अवकाश का प्रावधान है। न्यूनतम मजदूरी की दरें तद्नुसार ही निर्धारित की जाती हैं।

यदि किसी कर्मी से उसके साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य लिया जाता है तो दुगुने मजदूरी की दर से अधिकाल मजदूरी दिये जाने का प्रावधान है।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था कि आउटसोर्सिंग के थ्रू जो कर्मचारी दिए जाते हैं जिलों में...

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : जी अध्यक्ष महोदय, हम पूरक ही पूछ रहे हैं सर । सरकार का जवाब मिला है, जवाब से हम संतुष्ट भी हैं लेकिन इसमें मेरे दो पूरक सवाल हैं । पहला पूरक है, यह तो ठीक है कि सचिवालय में अगर काम करता है एक्स्ट्रा दिन तो उनको पेमेंट मिल जाता है, लेकिन जिले में, सहरसा में मैंने देखा है अन्य जिलों में, एम्बुलेंस चालक हैं, गार्ड हैं, उनसे 30 दिनों का काम लिया जाता है लेकिन पेमेंट जो सर्कुलर है, उसे 26 दिन

किया जाता है तो इसको कैसे व्यावहारिकता में लाते हुए सरकार इसमें क्या कर सकती है नंबर वन दूसरा पूछेंगे सर बाद में ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है कि 30 दिन काम लिया जाता है आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो कर्मचारी नियुक्त होते हैं और 26 दिन का ही मानदेय भुगतान किया जाता है । अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर में स्पष्ट किया है कि आउटसोर्सिंग से नियुक्त किए गए कर्मचारी को प्रत्येक 6 दिन के कार्य के पश्चात 1 दिन का सवैतनिक अवकाश का प्रावधान है और न्यूनतम मजदूरी की दरें तद्नुसार निर्धारित की जाती हैं । यदि कर्मी को उसके साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य लिया जाता है तो दुगुने मजदूरी की दर से अधिकाल मजदूरी दिए जाने का प्रावधान है लेकिन अगर कहीं इस प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है और इसकी शिकायत आती है तो उसके विरूद्ध कार्रवाई भी होती है और उनको भुगतान भी कराया जाता है ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, कम्प्लेन आता है तो होता है, मेरा सवाल है कि सरकार इसपर क्या कोई वॉचडॉग या ऐसा कुछ कर सकती है कि जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं, वे काम करवा कर पेमेंट नहीं देती हैं उस पर सरकार कुछ अल्टरनेटिव कर सकती है कि नहीं, मेरा सवाल यह था । दूसरा सवाल यह है कि धीरे–धीरे आउटसोर्सिंग ऐसा हो गया है कि सारे सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया और सरकार की जो नियत है काम करने की, उसपर प्रश्नचिन्ह् हो जा रहा है, इनइफेक्टिव हो जा रही है और मेरा इसमें दूसरा पूरक यह है कि यह ठीक है कि सरकार यहां से सेलेक्शन करे एजेंसी को लेकिन एकरारनामा, उस पर कंट्रोल नहीं होता है, जिले के एजेंसियों का उस पर कंट्रोल नहीं होता है, सारा चीज यहां से होता है तो सरकार यहां सेलेक्शन करे लेकिन एग्रीमेंट करने का अधिकार जिला को दे, जिला एग्रीमेंट करे और पेमेंट भी सरकार ही करे...

अध्यक्ष : आप सुझाव दे दीजिए ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : जी, वही पूछ रहे हैं सर, लेकिन एक रेकमेंडेशन वहां से ले पेमेंट का तो क्या इस तरह का जो सेलेक्शन आउटसोर्सिंग एजेंसियों का होता है, सेलेक्शन करके आगे में विचार करेगी सरकार कि जिस जिले के लिए मैन– पॉवर सप्लाई किया जाता है, उस जिले के साथ एग्रीमेंट उस एजेंसी का हो, इससे क्या होगा उससे कंट्रोलिंग अथॉरिटी जिला वाला हो जायेंगे और वे अपने अनुसार काम ले पायेंगे । आप सोचिए सर, रोगी कल्याण समिति भी सरकार ही यहां से भेज रही है...

अध्यक्ष : सुझाव बढ़िया आपका है ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : कैसे सरकार सोच सकती है कि नहीं, आप सेलेक्शन कीजिए लेकिन एकरारनामा जिला से करवाइए सो दैट कि एडमिनिस्ट्रेशन का उस पर होल्ड रहे और अपने अनुसार वह काम ले सके । इस पर क्या सरकार ऐसा अल्टरनेटिव सोच सकती है कि नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ा संवेदनशील मुद्दा उठाया है और सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित किया है और समय–समय पर इसका पुनरीक्षण भी होता है तो जो काम करने वाले कर्मी हैं, उनका न्यूनतम मजदूरी मिले और जितना घंटा काम निर्धारित है, उतना ही घंटा काम लिया जाए, यह सरकार चाहती है और माननीय सदस्य की जो भावना है तो हम देखेंगे कि उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है ।

अध्यक्ष : श्री मुरारी प्रसाद गौतम ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : सर, सर...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बैठ जाइए, आप ही का आगे भी है । सरकार ने बहुत स्पष्ट कहा है कि लगातार सरकार इन बातों को देख रही है । प्लीज आप बैठ जाइए ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : एक मिनट सर, सरकार की नियत...

अध्यक्ष : आपका सुझाव आ गया सरकार तक ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : सरकार क्या आगे के समय में सेलेक्शन के बाद एकरारनामा के लिए विचार करेगी कि नहीं इस पर मेरा सवाल है...

अध्यक्ष : सरकार विचार करेगी । माननीय सदस्य श्री मुरारी प्रसाद गौतम ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0–49, श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या–207, चेनारी (अ0जा0))</u>

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : पूछता हूं महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पर्यटन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है ।

अध्यक्ष : ठीक है, अगली बार मिल जाएगा । श्री आई0पी0 गुप्ता ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0–50, श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या–75, सहरसा)</u>

(मुद्रित उत्तर)

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड–1 –बिहार सरकार द्वारा अक्टूबर, 2025 से बीड़ी श्रमिकों के लिए 444 रूपया प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी

तय की गई है। न्यूतनम मजदूरी का भुगतान नहीं करने पर दोषी नियोजकों के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है।

जमुई जिला में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का अनुपालन नहीं करने वाले कुल–05 दोषी नियोजकों के विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर के न्यायालय में दावा पत्र दर्ज किया गया है उक्त दावा के विरूद्ध कुल–08 कामगारों को उनके बकाया मजदूरी का भुगतान कराया गया है ।

खंड–2 –अस्वीकारात्मक ।

भारत सरकार के ई–श्रम पोर्टल के अनुसार जमुई जिले में कुल–61,500 (इकसठ हजार पांच सौ), नालंदा जिले में कुल–4,947 (चार हजार नौ सौ सैंतालिस), सहरसा जिले में कुल–194 (एक सौ चौरानवे) और खगड़िया जिले में कुल–203 (दौ सौ तीन) सहित पूरे बिहार राज्य में कुल–1,25,453 (एक लाख पचीस हजार चार सौ तिरेपन) कामगारों ने स्वयं को तंबाकू श्रमिकों के रूप में निबंधित किया है।

बीड़ी श्रमिकों को संरक्षित करने के लिए बीड़ी एवं सिगार श्रमिक (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 का क्रियान्वयन किया जाता है। इसके अलावे राज्य सरकार द्वारा बीड़ी श्रमिकों सहित सभी असंगठित कामगारों के लिए बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 (यथा संशोधित) संचालित है।

इस योजना के तहत (क) श्रमिकों के आश्रितों को दुर्घटना मृत्यु में रू0–2,00,000/–(दो लाख रूपया), (ख) स्वाभाविक मृत्यु में रू0–50,000/–(पचास हजार रूपया), (ग) पूर्ण स्थायी निःशक्तता में रू0–1,00,000/–(एक लाख रूपया), (घ) स्थायी आंशिक निःशक्तता में रू0–50,000/–(पचास हजार रूपया), (ड़) असाध्य रोग के लिए चिकित्सा सहायता के रूप में रू0–15,000/–(पन्द्रह हजार रूपया) से रू0–60,000/–(साठ हजार रूपया), (च) दुर्घटना के दौरान चोट लगने की स्थिति में आर्थिक सहायता के रूप में रू0–10,000/–(दस हजार रूपया) एवं (छ) छात्रवृत्ति अनुदान के रूप में रू0–2,500/–(दो हजार पांच सौ रूपया) से रू0–10,000/–(दस हजार रूपया) दिया जाता है।

खंड–3 –उपर्युक्त खंडो में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : सर, मंत्री जी के नाम के पीछे टाईगर लगा हुआ है और जवाब भी एकदम टाईगर वाला ही दिया है इन्होंने, बड़ा विस्तृत जवाब है सर । मैं जमुई से आता हूं और वहां बीड़ी बनाने वाले से संबंधित क्वेश्चन है सर...

अध्यक्ष : पूरा उत्तर इसमें मुद्रित है ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : जमुई वाला नाम लेते हैं तो सहरसा वाला सब हमको पीछे से बोलता है कि विधायक बनाया, सहरसा का सवाल...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य सारा उत्तर मुद्रित है, आप पूरक पूछिए ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : जी, इसमें मेरा पूरक है कि बीड़ी का जो परिचय–पत्र बनाने की जो प्रक्रिया है वह बहुत जटिल है । जमुई में मैं पर्सनली जानता हूं कि 3 से 4 लाख बीड़ी बनाने वाले लोग हैं लेकिन अभी जो सरकार का जवाब आया है 61 हजार 500, सिर्फ इसलिए कि यह प्रक्रिया बहुत जटिल है सर, बीड़ी बनाने वाले इसलिए पहला पूरक हमारा यह है कि क्या सरकार कैंप लगाकर बीड़ी मजदूरों का परिचय–पत्र बना सकती है कि नहीं, मेरा पहला पूरक यह है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम इंद्रजीत है महोदय, इनको इंद्र को जीतने की क्षमता जिसके पास है महोदय और इनकी बौद्धिक क्षमता और तार्किक क्षमता से सदन परिचित है महोदय, बीच–बीच में अंग्रेजी भी बोलते हैं तो इसलिए जो इनका प्रश्न था, उसमें जो संभावित पूरक हो सकता था, चूंकि पूरक पूछेंगे ही, हमको अनुमान था, उसका भी उत्तर इसमें दे दिया गया है, मुझे लगता है कि जो उत्तर है, इससे उनको संतुष्ट हो जाना चाहिए लेकिन...

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : उत्तर में कहां लिखा हुआ है कि कैंप लगाकर हम करवायेंगे, मेरा क्वेश्चन है इस पर जवाब दीजिए न कि कैंप लगाकर जो जटिल प्रक्रिया है, आप 1 लाख 74 हजार बता रहे हैं, 4 लाख तो खाली जमुई में ही है । आप अगर इसको जटिल से आसान कर देंगे, आप यह सीधा बताइए कि क्या कैंप लगाकर इसका पंजीकरण हो सकता है कि नहीं, इस पर सरकार सोच सकती है कि नहीं, दैट इज माई फर्स्ट पूरक ।

अध्यक्ष : दूसरा है, दूसरा पूरक हुआ आपका । दूसरा हो गया पूरक ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये जो कामगार हैं, ये असंगठित कामगार शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत इनको कवर किया जाता है, इसका रजिस्ट्रेशन बिहार सरकार नहीं कराती है । बिहार सरकार जो रजिस्ट्रेशन जिन मजदूरों का कराती है, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार जो लोग हैं, जो बिल्डिंग निर्माण में लगे हुए हैं, उनका सूचीबद्ध है कि कौन–कौन उसमें आते हैं, उसका होता है । इसका, जिसका माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं, यह भारत सरकार का ई–पोर्टल है श्रम का, ई–श्रम पोर्टल, उस पर ये लोग रजिस्टर्ड होते हैं और उसको हमलोग यहां देख लेते हैं, उसी के अनुमान पर ये आंकड़ा दिया गया है, हो सकता है वास्तविक आंकड़ा इससे ज्यादा हो, लेकिन अभी हम इन क्षेत्रों में काम करने वालों का रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, लेकिन माननीय सदस्य का अगर सुझाव है इस पर सम्यक विचार किया जाएगा महोदय और भविष्य में विचार किया जा सकता है ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : सर, दूसरा पूरक । अभी एक ही पूरक पूछे हैं ।

अध्यक्ष : आप दो पूरक पूछ चुके हैं । लास्ट आपका है ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : सर, जमुई में इतनी सब व्यवस्था है इसमें, इतनी बढ़िया सरकार ने योजना चलाई, इतना लाभ है इसमें लेकिन जब रजिस्टर्ड ही नहीं होगा तो लाभ कैसे मिलेगा ? दूसरा, महिलाएं बीड़ी बनाती हैं और पीने लग जाती हैं तो उसको बीमारी हो जा रहा है और झाझा में एक जगह है...

अध्यक्ष : आप सुझाव दे दीजिए ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : हेलाजोत, उसमें 2 कमरे का इसके लिए स्पेशल बनाया हुआ है लेकिन 2 दिन डॉक्टर आता है, मंगलवार और शुक्रवार । क्या सरकार सोच सकती है कि हम वहां 25 या 50 बेड का बीड़ी मजदूरों के लिए अस्पताल बनाएं और इसको पी0एफ0 से जोड़ सकते हैं, नहीं तो जो पूछते हैं, मंत्री जी वही जवाब दीजिए, आप भूमिका बांधने लगते हैं । इस पर सिर्फ बोल दीजिए कि अस्पताल बनेगा, पी0एफ0 से जुड़ेगा ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : जिस गांव का आप जिक्र कर रहे हैं माननीय सदस्य, इस योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता ही नहीं है । हमने तो जिक्र किया कि ई–श्रम पोर्टल से हमको कुछ आंकड़ा मिलता है लेकिन जो उसमें रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनको भी बिहार शताब्दी असंगठित कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत, जिसको 2024 में उन्होंने संशोधित किया है, उसका लाभ ले सकते हैं, उसकी एक प्रक्रिया है, एक विहित प्रक्रिया है । माननीय सदस्य कहेंगे तो उसकी प्रक्रिया से भी हम अवगत करा देंगे ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : सर, सर...

अध्यक्ष : आपका तीन पूरक हो गया, सरकार का जवाब हो गया । श्री अविनाश मंगलम।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–''क''–614, श्री अविनाश मंगलम (क्षेत्र सं0–47, रानीगंज (अ0जा0))</u>

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ का सर्वे छूटे हुए बसावट अंतर्गत शरणार्थी टोला अरूण यादव के खेत से शांति नगर टोला संजय मेहता के घर तक लम्बाई–2.00 कि0मी0 के नाम से सर्वे किया गया है, जिसका सर्वे आई0डी0–76854 है ।

निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

श्री अविनाश मंगलम : पूछता हूं अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अविनाश मंगलम जी का क्वेश्चन लास्ट टाईम भी आया था, हमने जवाब भेजा है । इसका जवाब है, सप्लीमेंट्री पूछना है तो पूछ लीजिए ।

अध्यक्ष : पूछ लीजिए ।

श्री अविनाश मंगलम : फिर तो वही जवाब आया है सर ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, उसका हमारे पास पूरा फोटो और क्वेश्चन सब है, हमारा आंसर सही है, अगर आपको इसमें कुछ और सप्लीमेंट्री पूछना है तो पूछिए ।

श्री अविनाश मंगलम : हो सकता है सर, वहां दो सड़क है इसलिए आपका विभाग बार–बार उसी सड़क के बारे में दे रहा है ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास पूरा फोटो है, होमवर्क करके आए हैं पूरा फोटो है, अगर इसमें आपको और सप्लीमेंट्री कुछ पूछना है तो हमको आप बताइए।

अध्यक्ष : कोई बात पूरक पूछना हो तो...

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : माननीय सदस्य आप मिल लीजिएगा न, हम पदाधिकारियों के साथ बैठ जायेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लगता है ।

अध्यक्ष : श्री संजय कुमार सिंह ।

टर्न–2 / यानपति / 18.02.2026

तारांकित प्रश्न संख्या–1313, श्री संजय कुमार सिंह (क्षेत्र सं0–76, सिमरी बख्तियारपुर)

(लिखित उत्तर)

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–227J पर अवस्थित उच्चैठ को NH-527A से होकर महिषी तारा स्थान को जोड़ने वाले पथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(NHAI) के द्वारा 2 lane with paved shoulder पथ का निर्माण कराया जा रहा है।

वर्तमान में उक्त पथ को विस्तारित कर सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के संत बाबा कारू स्थान मंदिर से जोड़ने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री संजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर तो मुझे मिल गया है लेकिन मेरा इसमें यह कहना है कि, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह कहना चाहता हूं कि सिमरी बख्तियारपुर विधान सभा में तीन धार्मिक स्थल हैं जो महत्वपूर्ण हैं। महिषी का तारास्थान, बाबा कारू स्थान और मटेश्वर स्थान और महिषी के तारास्थान पर हमारे मुख्यमंत्री जी का भी बहुत ज्यादा ध्यान है, तो महिषी और बलवाहाट के बीच में पड़ता है कारू स्थान, मंत्री महोदय को यह कहना है बलवाहाट, सकरा, पहाड़पुर तक रोड है और महिषी तक ये वाला रोड

जो है मधुबनी के उपक्षेत्र में भगवती से आया हुआ है तो यह महिषी और सकरा पहाड़पुर एवं कारू स्थान को जोड़ने के लिए जो है हम आग्रह किए हुए हैं रोड से ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे उत्तर स्पष्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित उच्चैठ को एन0एच0 527 ए से होकर महिषी तारास्थान को जोड़नेवाले पथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(NHAI) के द्वारा 2 lane with paved shoulder का पथ निर्माण कराया जा रहा है । माननीय सदस्य का है कि बाबा कारूस्थान मंदिर भी एक पर्यटक स्थल है और वहां तक इस रोड को विस्तार के लिए माननीय सदस्य ने अनुरोध किया है, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे यहां विचाराधीन नहीं है, भविष्य में जरूरत होने पर हम देखेंगे इसको ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री दामोदर रावत ।

श्री संजय कुमार सिंह : यह बहुत जरूरी है । वह जो स्थान है बहुत ही फेमस है, बहुत श्रद्धालु वहां जुटते हैं और बहुत दूर नहीं है, मुझको लगता है कि मात्र 7–8 कि0मी0 है, उसको करके थोड़ा सा कर दिया जाय । आप वैसे भी बहुत दिलेर हैं और हमलोग इससे पहले भी जो है बात हो चुकी है ।

अध्यक्ष : श्री दामोदर रावत ।

श्री संजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत आवश्यक है ।

अध्यक्ष : आपका सुन लिया है माननीय मंत्री जी ने, सुन लिया है, जवाब आ चुका है।

श्री संजय कुमार सिंह : मंत्री जी, इसको देख लीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : इसको दिखवा लेते हैं, फिजिबिलिटी होगी तो हम करवायेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1314, श्री दामोदर रावत (क्षेत्र सं0–242, झाझा)</u>

श्री दामोदर रावत : अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं । उत्तर तो नहीं मिला है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिया हुआ है ।

श्री दामोदर रावत : उत्तर नहीं आया हुआ है, अभी भी हम देख रहे हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें बात यही है कि माननीय सदस्य जिन क्षेत्रों की चर्चा कर रहे हैं और जिस नहर से, नहर निकालकर वहां पानी देने की बात कर रहे हैं तो नहर तल से, ये सब इलाका जो है ऊंचे क्षेत्र पर अवस्थित है, तो ऊंचे क्षेत्र पर तो नहर से सिंचाई जाती नहीं है इसलिए इस प्रणाली से जो कुकरझप या जिसको आंजन जलाशय कहते हैं उससे इधर से पानी देना संभव नहीं है । लघु जल संसाधन विभाग की दूसरी योजना से उस क्षेत्र में जो वह पटवन का काम है वह किया जा रहा है बाकी अगर माननीय सदस्य उसका कोई दूसरा वैकल्पिक मतलब जो कार्य कर सकता हो वह प्रणाली बतायेंगे तो सरकार जरूर विचार करेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री जी को कुछ सुझाव देना हो तो ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1315, श्री विनय कुमार चौधरी (क्षेत्र सं0–80, बेनीपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, (1) स्वीकारात्मक है।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न में वर्णित पथ ''बहेड़ा PWD सड़क से गणेश बनौल बलनी''– यह पथ कल्याणपुर बहेड़ी Road से बलनी तक पथ (लंबाई–1.690 कि0मी0) MR योजना अन्तर्गत निर्मित पथ है एवं वर्तमान में यह पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि में है।

''धेरूख से नन्दापट्टी पथ''–यह पथ MR योजना अन्तर्गत निर्मित पथ है, (लंबाई–2.200 कि0मी0) पथ वर्तमान में पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि में है।

प्रश्न में वर्णित मधुबन से रजवाड़ा तक ''बहेड़ी बेनीपुर PWD रोड से रजवाड़ा''–यह पथ भीर्श MR.3054 (नई अनुरक्षण नीति–2018), (लंबाई–3.070 कि0मी0) अन्तर्गत किया गया है। वर्तमान में यह पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि में है। पथ के घनी आबादी वाले लगभग चार स्थानों पर लगभग 0.935 कि0मी0 पथांश में जल–जमाव के कारण कालीकृत भाग क्षतिग्रस्त है। जिसको Motorable करा दिया गया है।

''पोहद्दी दुर्गा मंदिर से डाक बाबू के घर होते हुए ग्राम धेरूख से अन्टौर तक पथ''–यह पथ नाबार्ड योजना अन्तर्गत निर्मित पथ है, (लंबाई–3.830 कि0मी0) पथ का पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि दिनांक–09.02.2025 को समाप्त हो गया है। वर्त्तमान में इस पथ में ग्रामीण पथ सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है।

(3) अंश 2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

(4) अंश 2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

श्री विनय कुमार चौधरी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया हुआ है । जरा हम आपसे पूरक में मैथिली में बोलेंगे इसलिए मैं परमिशन लेना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : ठीक है, बोलिए ।

श्री विनय कुमार चौधरी : मैथिली में मैं इसलिए बोलूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के प्रयास से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मैथिली को अष्टम अनुसूची में शामिल किया था इसलिए मैं मैथिली में बोलना चाहता हूं ।

(मैथिली भाषा का हिंदी रूपांतरण)

सबसे पहले हम माननीय मंत्री जी को कहना चाहते हैं कि पिछले साल चुनाव से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा–निर्देश में जितने कार्य की इन्होंने स्वीकृति दी, हमारे क्षेत्र में एक कहावत है कि गर्दा उड़ा दिए । गर्दा–गर्दा उड़ा

दिए, तो हमारे यहां एक कहावत में है कि गर्दा में कुछ संवेदक और कुछ इंजीनियर उसमें पानी डाल रहे हैं । उसी से यह परेशानी होती है अदरवाइज इनसे अच्छा मंत्री मिलना मुश्किल है । हम कहना चाहते हैं कि मधुवन से रजवारा हाट में ये बोले थे कि उसको मोटरेबल बनाया जायेगा । हम मंत्री जी से एक आग्रह करेंगे कि हमारे क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जितने निर्मित पथ हैं या जो इसमें लिखा हुआ पथ है उसे अपने विभागीय निगरानी से जांच कराने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं ? क्योंकि हम कह रहे हैं कुछ, विभाग कह रहा है कुछ । सर, मधुबन से रजवारा पथ में शत प्रतिशत वोट हमको आया है और वहां जाने में हमको देर होती है इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि वह जो कार्य किया गया है उसकी जांच निगरानी से करवा दीजिए ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : माननीय सदस्य को लगता है, उनका आग्रह है तो सरकार पूरी तरह से अपने माननीय सदस्य और अपने माननीय मतदाताओं के पक्ष में है इसीलिए जिस पदाधिकारी से कहेंगे हमारे विभाग से, उससे निगरानी जांच करवा देंगे ।

श्री विनय कुमार चौधरी : बहुत–बहुत धन्यवाद ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1316, श्री उमेश सिंह कुशवाहा (क्षेत्र सं0–129, महनार)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वैशाली जिलान्तर्गत महनार विधान सभा के अधीन जन्दाहा प्रखण्ड अन्तर्गत GTSNY योजना के अधीन कुल 53 पथों जिसकी लम्बाई–29.045 कि०मी० एवं महनार प्रखण्ड अन्तर्गत कुल 01 पथ जिसकी लम्बाई–0.50 कि०मी० है का निर्माण किया गया है।

उपरोक्त बसावटों के अलावा अन्य अनजुड़े बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष) अन्तर्गत स्मजि Habitation App के माध्यम से सर्वे किया गया है जिसमें जन्दाहा प्रखण्ड अन्तर्गत कुल 22 बसावट अनजुड़े पाए गए। महनार प्रखण्ड अन्तर्गत 16 अनजुड़े बसावट पाए गए जिसमें से 02 पथों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इन स्वीकृत 02 पथों में से एक पथ का कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि एक पथ निर्माणाधीन है।

शेष बचे पथों की निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

3. खण्ड–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : महोदय, उत्तर तो आया है लेकिन मेरा पूरक है माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग जी से, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी बिहार के वैसे टोला बसावट जहां किसी भी प्रकार से संपर्कता प्रदान नहीं है तो वैसे टोला को संपर्कता प्रदान करने का सरकार विचार रखती है, कब तक रखती है ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने शुरू किया था और जब पहले हमलोगों ने, योजनाओं को माननीय नेता ने शुरू किया अपने आने के बाद, इस प्रदेश में तो 500 हैविटेशन को टार्गेट किया गया था । उस 500 हैविटेशन को जब हमने कंप्लीट किया तो हमलोगों ने 250 हैविटेशन लिया और फिर नेता ने यह निर्णय किया कि वैसे टोले जहां पर 100 की आबादी है उसको भी हम कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा टार्गेट एरिया विभाग का धीरे–धीरे बढ़ता चला गया । तो हमलोगों के पास अब जो 100 के बसावट हैं उसमें भी दोहरी संपर्कता नहीं होनी चाहिए । बहुत से लोग चाहते हैं कि इधर से भी हो जाय, उधर से भी हो जाय । तो हमलोगों ने जियो टैगिंग करने के बाद निर्णय किया और अभी हमारे यहां 11020 बसावट जिसकी लंबाई 14 हजार कि0मी0 है असंपर्कित पाये गये हैं, 100 के हैविटेशन, 150 के हैविटेशन पर जिसे तीन वित्तीय वर्षों में कंप्लीट करने का निर्णय सरकार ने किया है । 2025–26 में हमलोगों ने बसावटों की संख्या ढाई हजार रखी थी जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में ढाई हजार के टार्गेट से ज्यादा हमलोगों ने 3279 टार्गेट को कंप्लीट किया । हम अपने टार्गेट से ज्यादा कंप्लीट किए हैं, इस वित्तीय वर्ष की निधि की उपलब्धता के बाद हमलोग डिसाइड करेंगे, लेकिन मोटा–मोटी हमें लगता है कि हम ढाई हजार, तीन हजार बसावटों को लेने का काम इस वित्तीय वर्ष में भी करेंगे । इसमें निधि की उपलब्धता पर हम विचार करने का काम करेंगे ।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : महोदय, जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है तो उसमें आंशिक रूप से जो है महनार का ही लीजिए या एक ही क्षेत्र का जो इनकी रिपोर्ट आई है तो उसमें जो सही रिपोर्ट नहीं आ पायी है । महोदय, जो बसावट अभी छूटी हुई है, जो उनका पुराना सर्वे हुआ है या नया सर्वे कराए हैं जिनकी बसावट संख्या भी चिन्हित कर ली गई है तो वैसे बसावट जो उनका दिया हुआ है, जो विभागीय नियमों के अनुसार से सर्वे किया गया है तो वैसे चिन्हित बसावट को कब तक पूरा करेंगे ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट जवाब दिये कि 11020 बसावट जो है पूरे बिहार में हमलोगों ने चिन्हित करके रखा है, जो 100, 150 के आसपास है। उसमें से हमलोगों ने ढाई हजार का टार्गेट पिछले वित्तीय वर्ष में रखा था । इस वित्तीय वर्ष में हमलोगों ने 3800 किया पिछले वित्तीय वर्ष में, इस वित्तीय वर्ष में हमलोगों ने रखा है टार्गेट लगभग साढ़े चार हजार का लेकिन क्योंकि

हमलोगों ने पिछले वित्तीय वर्ष में अपने टार्गेट से ज्यादा लिया है पैसे का व्यय ज्यादा हुआ है तो इस वित्तीय वर्ष में वित्तीय व्यवस्था को देखते हुए इस बार भी टार्गेट लेंगे । कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बसावट हमारे टार्गेट पर आएं लेकिन निधि की उपलब्धता के बाद ही यह निर्णय हो पायेगा ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, यह जी0टी0एस0एन0वाई0 योजना बहुत अच्छी योजना थी और पूरे बिहार में छोटे बसावटों को मुख्य सड़क से, किसी भी सड़क से एकल संपर्कता दिलाने के लिए हमलोग भी सरकार में थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसको सीरियसली लिया गया । कैबिनेट में भी यह बात उठी और उसपर उन्होंने विभाग को काफी इस संदर्भ में बताने का काम किया, मेरे ही बात को उठाने के बाद क्योंकि जो बसावटें हैं वह अधिकांश बसावटें उस तरह की हैं जिसमें सरकारी जमीन नहीं है, प्राइवेट लोगों की जमीन है ।

(क्रमशः)

टर्न–3 / मुकुल / 18.02.2026

क्रमशः

श्री आलोक कुमार मेहता : और उस पर कोई उपाय नहीं हो रहा है तो तय यह हुआ था कि सरकार जमीन खरीदेगी या सतत लीज पर लेकर उसका निर्माण करेगी । मुझे याद है हमारे विधान सभा क्षेत्र में 55 ऐसे क्षेत्र हैं....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, जिसका 3 साल पहले उनमें से कुछ सड़कों का सर्वे हो चुका है और अभी तक सरकार की तरफ से मैं समझता हूं कि कई बार इस बात को उठाया गया, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इसको संज्ञान में नहीं लिया गया । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अगले वित्तीय वर्ष में समस्तीपुर जिला खासकर उजियारपुर क्षेत्र में जितने बसावट हैं, जो एकल सम्पर्कता की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

एक मिनट । महोदय, ऐसा पूरे बिहार में है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका पूरक प्रश्न आ गया है । माननीय मंत्री ।

श्री आलोक कुमार मेहता : हजार–हजार लोगों की आबादी है, जो सम्पर्कता से दूर है ।

अध्यक्ष : आलोक बाबू, माननीय मंत्री जी की बात सुन लीजिए ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, नगरगामा पंचायत में 1300 की आबादी एकल सम्पर्कता से दूर है और उसका सर्वे 3 साल पहले हो चुका है, लेकिन अभी तक उसपर नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनके कार्यकाल में, आलोक मेहता जी के नेता के कार्यकाल में पूरे बिहार में मात्र 8 हजार कि0मी0 ग्रामीण सड़क थी और

प्रधानमंत्री सड़क योजना से आपके समय में काम होता था, आपके समय में न मुख्यमंत्री अवशेष योजना थी, न मुख्यमंत्री सम्पर्क योजना थी ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय....

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : एक सेकंड, Let me complete.

अध्यक्ष : मेहता जी, मंत्री जी की बात सुन लीजिए ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : आप अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि सरकार काम कर रही है । आप जिन बातों को कह रहे हैं उसपर सरकार ऑलरेडी लीज लिटी खासकर के ई0बी0सी0 और वैसे दलित टोले जहां पर सम्पर्कता प्राप्त नहीं है, उसपर लीज लिटी पर और खरीद करके काम कर रही है, लेकिन कहीं–कहीं क्योंकि यह सतत काम है, आज जहां हैबिटेशन है, कल हैबिटेशन कहीं और सिफ्ट कर जायेगा, परसों कहीं और सिफ्ट कर जायेगा चार साल बाद तो ये सतत काम है । नीतीश कुमार जी ने 500 पर शुरू किया था, फिर 250 पर आये, अभी 100 पर आये और 100 पर भी जो हैबिटेशन है, कल और भी हैबिटेशन.....

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय....

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : मुझे अपनी बात को कम्प्लीट करने दीजिए न, Let me finish.

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री जी की पूरी बात को सुनिए, पूरी बात सुननी चाहिए, आपने अपना विषय रख दिया है ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : माननीय सदस्य की जो चिंता है, उस चिंता पर सरकार पिछले जो वित्तीय वर्ष में काम किया है, उस पर ऑलरेडी लीज पर लेकर के हैबिटेशन को कनेक्टिविटी दिया है । यह चिंता सरकार ऑलरेडी कर रही है। अगर 15 साल पहले इस पर आप चिंता किये रहते तो अभी एक भी हैबिटेशन लेफ्ट आउट नहीं रहता ।

अध्यक्ष : श्रीमती संगीता कुमारी ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाइये, आपने अपनी बातों को रख दिया है । श्रीमती संगीता कुमारी ।

श्रीमती संगीता कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : आलोक बाबू, आपको मौका दिया गया था और आपने अपने विषय को रखा है। माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

(व्यवधान)

आलोक बाबू, कृपया अब आप बैठ जाए ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1317, श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र सं0–204, मोहनिया (अ0जा0))

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि कैमूर जिलान्तर्गत कुदरा प्रखंड के ग्राम चडुई के पास दुर्गावती नहर नहीं अपितु कुदरा वितरणी गुजरती है, जो सोन उच्चस्तरीय नहर के 51.31 कि0मी0 से निःसृत है ।

कुदरा प्रखंड के ग्राम चडुई के पास कुदरा वितरणी के 10.609 कि0मी0 पर पूर्व से पुल निर्मित है । साथ ही, इस बिन्दु के 1.796 कि0मी0 अपस्ट्रीम में एवं 0.970 कि0मी0 डाउनस्ट्रीम में पूर्व से पुल निर्मित है, जिसका उपयोग ग्रामीणों द्वारा आवागमन हेतु किया जाता है ।

उक्त पुल का सूक्ष्म निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मति कार्य कराने का निदेश मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी को दिया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्रीमती संगीता कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर प्राप्त हुआ है लेकिन मैं मांग करती हूं कि चडुई में जो पुल है वह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है तो मरम्मति की जगह नये पुल का निर्माण करा दिया जाए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उसको हमलोग करवा देंगे ।

श्रीमती संगीता कुमारी : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1318, श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र सं0–56, अमौर)

(लिखित उत्तर)

श्री संजय सिंह (टाईगर), मंत्री : अध्यक्ष महोदय, राज्य के बाहर अथवा विदेश में कार्य करने वाले असंगठित क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों की दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की दशा में पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास तक पहुंचाने पर हुए व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है ।

स्वाभाविक मृत्यु की दशा में मृत प्रवासी श्रमिकों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास तक पहुंचाने का कोई प्रावधान विभाग स्तर पर नहीं है ।

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न है मैं समझता हूं कि सदन का आज का सबसे गंभीर प्रश्न भी है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब मुद्रित है ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मैंने क्या कहा है कि बिहार के 70 फीसदी लोगों के बच्चे प्रवासी मजदूर हैं और मैं तत्कालीन मंत्री जिवेश मिश्रा साहब का शुक्रगुजार हूं कि मेरे प्रस्ताव पर उन्होंने विदेश में और देश के अन्य राज्यों में मरने वाले एक्सीडेंटल डेथ को घर लाने का आदेश प्राप्त कर लिया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मेरी साफ मांग है कि हमारे बिहार की आमदनी का स्रोत प्रवासी मजदूर हैं और सरकार को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रवासी जोड़ा है अभी मजदूर वाले मंत्रालय में तो प्रवासी मजदूर के कल्याण के ताल्लुक से कुछ तो कर नहीं पाते, कम से कम इतना कर दीजिए कि उनका जो एक्सीडेंटल डेथ होता है तो फौरी तौर पर उसमें भी दिक्कत होती है, लेकिन नेचुरल डेथ भी हो जाए अगर तो वह बेचारा कर्ज लेकर गया है परदेश ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना पूरक प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, मैं पूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूं कि उनकी लाश को उनके घर में पहुंचाये जाए, बीबी–बच्चे बिलखते हैं, 70 फीसदी परिवार बिहार के हैं जिनके प्रवासी मजदूरों पर घर चलता है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सुझाव दे दीजिए ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, उनकी लाश को घर पहुंचाया जाए, मैं यही बात कह रहा हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रावधान है उसके तहत राज्य के बाहर अथवा विदेश में कार्य करने वाले असंगठित क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों की दुर्घटना के फलस्वरूप अगर उनकी मृत्यु होती है तो उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान उनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा सरकार उठाती है महोदय । अब माननीय सदस्य का यह कहना है कि राज्य के अंदर भी और बाहर भी नेचुरल डेथ से अगर मरते हैं तो उनके डेड बॉडी को भी घर पहुंचाने का जिम्मा राज्य सरकार ले, अभी वैसा कोई प्रावधान नहीं है महोदय ।

अध्यक्ष : श्रीमती संगीता देवी ।

श्री अखतरूल ईमान : मंत्री महोदय, ऐसा कैसे हो जायेगा । महोदय, मजदूर कमाने के लिए परदेश गया है क्योंकि आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, उसके लाश को आप नहीं लाइयेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्रीमती संगीता देवी ।

श्री अखतरूल ईमान : उसकी बीबी तड़पती है, बच्चा तड़पता है, कैसे लाश आयेगी सर? अध्यक्ष महोदय, इस पर होना चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने अपनी बात को रखा है ।

(व्यवधान जारी)

श्री अखतरूल ईमान : नहीं महोदय । मंत्री जी, आप भी समझ जाइये कि अगर सरकार इस कानून को नहीं बनायेगी, वह भी बाहर मरेंगे तो उनकी लाश भी नहीं आयेगी, आप भी बाहर मरियेगा तो आपकी लाश भी नहीं आयेगी । आप मजदूरों के लिए यह काम क्यों नहीं कीजिएगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी राय दे दीजिए ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, यह मजदूरों का मामला है । नहीं सर, 70 फीसदी वोटर हैं मजदूर ।

अध्यक्ष : ईमान जी, आप अपनी राय दे दीजिए ।

श्री अखतरूल ईमान : नहीं सर, मजदूर का मामला है । मजदूर विरोधी जो लोग हैं उनका हम समर्थन नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : आप अपनी राय दे दीजिए ।

(व्यवधान जारी)

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, बिहार देख रहा है मजदूर विरोधी लोगों को कि मजदूर की लाश को नहीं लाइयेगा, बीबी रोती है, बच्चा रोता है । इसका मायने यह है कि लाभ लेने के लिए उसको कहीं गाड़ी के चक्के में दबना पड़ेगा, जो मजदूर बाहर में बीमार हैं वह समझेगा कि मरूंगा तो सरकार मेरी लाश नहीं ले जायेगी तो जाकर के वह कहीं अपना एक्सीडेंट करवा लेगा ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना सुझाव दीजिए । ईमान जी, मेरा आपसे आग्रह है कि आप बोलने के बजाए सरकार को सुझाव दे दीजिए ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, नहीं । सरकार को मजदूरों की लाश लानी पड़ेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोलने के बजाए सरकार को सुझाव दे दीजिए । आपका सुझाव क्या है ?

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, विदेश में या अन्य प्रदेशों में जो मजदूर हमारे कमाने के लिए गए हैं, अगर वे मरे तो उनके नेचुरल डेथ में भी.....

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति–शांति । सरकार का जवाब हो रहा है ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : महोदय, मैंने अभी मौजूदा क्या प्रावधान है उसका जिक्र किया, लेकिन भविष्य में इस पर विचार नहीं किया जा सकता, ऐसा तो मैंने नहीं कहा । विचार करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है महोदय, सम्यक विचार करेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्रीमती संगीता देवी । सरकार विचार करेगी, कृपया बैठ जाइये ।

(व्यवधान जारी)

सरकार आपके सुझाव पर विचार करेगी, कृपया बैठ जाइये ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि अगर प्रॉविजन नहीं है तब तो यह सवाल लाया गया है और प्रॉविजन लाने के लिए लाया गया है इसलिए सरकार से हम उम्मीद करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि आप इसके लिए प्रॉविजन बना दीजिए ।

अध्यक्ष : शांति–शांति ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, बड़ा स्पष्ट तौर पर माननीय मंत्री जी ने बताया विचार करेंगे, ये सरकार को सुझाव दें उस पर विचार करेगी सरकार ।

(व्यवधान)

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, इसमें विचार करने की बात कहां है, यह सिर्फ कह दें कि लायेंगे ।

अध्यक्ष : ईमान जी, इतना साफ । श्रीमती संगीता देवी । ईमान जी, अब आप बैठ जाइये, बात क्लियर हो गयी । सर्वजीत जी, आप सुझाव दे दीजिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि बाहर में जो मजदूर काम करते हैं, मर जाते हैं तो उसका प्रावधान है । हम आपके माध्यम से सिर्फ मंत्री जी से इतना जानना चाहते हैं कि अगर प्रावधान है तो अभी तक आपके विभाग ने जो बाहर से आये–गये मजदूरों को कितने मजदूरों को आपने पैसा दिया है, सिर्फ इसके बारे में सदन को बता दीजिए ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक मजदूर से संबंधित नहीं था, फिर भी माननीय सदस्य की जिज्ञासा है तो मैं बता देता हूं महोदय.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुनिये–सुनिये । सरकार खड़ी है, सुन तो लीजिए ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : अरे, मैं बता रहा हूं, आप बैठिए, मैं बता रहा हूं ।

अध्यक्ष : आपको सुनना चाहिए, आप प्लीज सुन लीजिए, कुमार सर्वजीत जी ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : मैं बता रहा हूं, अरे धैर्य रखिए । महोदय, मैं बता रहा हूं....

अध्यक्ष : कुमार सर्वजीत जी, आप बैठिए न, बैठिए तो ।

(व्यवधान)

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : महोदय, मैं उत्तर बता रहा हूं, आपलोग बैठिए ।

अध्यक्ष : शांति–शांति ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2025–26 में अब तक 2 लाख 58 हजार 547 रुपया इस मद पर खर्च किया जा चुका है और मेरे पास आंकड़ा भी है महोदय कि कौन–कौन से प्रवासी मजदूर थे जिनको यह पहुंचाया गया । महोदय, ये एक जो स्वर्गीय संतोष मराण्डी, पिता–लखन मराण्डी, ग्राम–पसौही, संथाली टोला, थाना–के नगर, जिला–पूर्णिया के रहने वाले थे ।

क्रमशः

टर्न–4 / सुरज / 18.02.2026

(क्रमशः)

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : दूसरा, स्वर्गीय कुणाल कुमार, पिता– बुद्धु ऋषि, ग्राम–परोरा, प्रखंड केनगर, जिला पूर्णिया के रहने वाले हैं । स्वर्गीय राजू लाल

इनका भी ग्राम पोस्ट– रोउंटा, जिला–पूर्णिया है । स्वर्गीय दिपू कुमार साह, पिता–ओम प्रकाश साह, ग्राम– मठगौतम, पोस्ट–छतिऔना, थाना–थावे, जिला–गोपालगंज । स्वर्गीय अंशु राम इनका भी ग्राम, पोस्ट–बंगड़ा पिठौरी, जिला– गोपालगंज है । तीसरा स्वर्गीय घनश्याम कुमार है ग्राम–बंगड़ा पिठौरी, जिला– गोपालगंज । जिनको दिया गया है उनका नाम, पता, पिता का नाम, कितनी राशि दी गयी, ये बताया मैंने महोदय।

अध्यक्ष : श्रीमती संगीता देवी ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय...

अध्यक्ष : अब कोई सवाल नहीं । श्रीमती संगीता देवी । माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग ।

(व्यवधान)

बोल चुके हैं, अब ज्यादा बोलने की जरूरत क्या है, सब बातें आ गयी है ।

(व्यवधान)

सरकार गंभीर है इस मामले में ।

तारांकित प्रश्न सं0–1319, श्रीमती संगीता देवी (क्षेत्र सं0–65, बलरामपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि खगड़िया–पूर्णियाँ फोरलेन का निर्माण एवं संधारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। कटिहार जिला के कोढ़ा प्रखण्ड स्थित गेड़ाबाड़ी बाजार चौक पर फ्लाई ओवर का निर्माण विस्तृत परियोजना परामर्शी (DPR Consultant) के तकनीकी संभाव्यता (Geotechnical Investigation एवं Detailed Study) के आधार पर प्रस्तावित किया गया है।

श्रीमती संगीता देवी : महोदय, पूछती हूं ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या के द्वारा जो खगड़िया–पूर्णियां फोरलेन सड़क परियोजना के अंतर्गत कटिहार जिला के कोढ़ा प्रखंड–गेड़ाबाड़ी बाजार के बारे में जो फ्लाईओवर निर्माण की स्वीकृति दी गयी है । माननीय सदस्या का कहना है कि दलदली, कमजोर प्रकृति के होने के कारण वहां पर गोलम्बर या राउंड अवाउट जो है, निर्माण प्रस्तावित था । तो इसके लिये माननीय सदस्या के द्वारा जो सवाल आया है । हमलोगों ने इसको जो डी0पी0आर0 कंसलटेंट मैसर्स कास्टा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड हैं, हमलोगों ने उनके पास भेजा है मैसर्स हेक्सा कंपनी को भी कि इसके लिये कोढ़ा प्रखंड स्थित गेड़ाबाड़ी बाजार चौक में तीन स्पैन का जो फ्लाईओवर अभी चिन्हित है । उक्त स्थान पर हमलोग जियो टेक्निकल इंवेस्टिगेशन और डिटेल स्टडी के आधार पर इनका देखेंगे कि क्या हो सकता है ।

तारांकित प्रश्न सं0–1320, श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र सं0–171, अस्थावां)

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, (1) आंशिक स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ अंतर्गत टेंडर आई०डी० 143364 का कार्य संवेदक श्री जितेन्द्र कुमार (Bid Id–624821) को आंवटित हुआ है।

(2) अस्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि बीड० आ०ई०डी०–624821 निविदाकर श्री जितेन्द्र कुमार का है, जो टेंडर आई0डी0 143364 (वित्तीय वर्ष 2025–26) से संबंधित है। निविदाकार जितेन्द्र कुमार द्वारा इस निविदा में वित्तीय वर्ष 2020–21 का अनुभव प्रमाण पत्र एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 का भुगतान प्रमाण पत्र कार्य प्रमंडल, मधेपुरा द्वारा निर्गत है को संलग्न किया गया है। इस निविदा में तीन निविदाकारों द्वारा भाग लिया गया। तीनों निविदाकारों को Substantially Responsiveness के आधार पर योग्य घोषित किया गया। निविदाकार जितेन्द्र कुमार (Bid Id–624821) के पथ कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र एवं भुगतान प्रमाण पत्र के विरूद्व दायर परिवाद की जाँच कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ द्वारा कार्य प्रमंडल, मधेपुरा से कराया गया, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि उनका पथ कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र एवं भुगतान प्रमाण पत्र सही है। निविदा निष्पादन तक उक्त निविदाकार का निबंधन काली सूची में दर्ज नहीं था।

श्री जितेंद्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों एवं अभियंताओं ने प्रश्न के परे होकर उत्तर दिया है और सच्चाई इससे कोसों दूर है । उक्त संवेदक के द्वारा कई बार जाली सर्टिफिकेट, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाकर इन्होंने निविदा प्राप्त किया है, काम प्राप्त किया है और विभाग ने भी इनके खिलाफ जाली प्रमाण पत्र या जो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र हैं, उनके लिये अखबार में भी निकाला है कि इनको ब्लैकलिस्टेड किया जाए । लेकिन आज तक अभियंताओं की मिलीभगत से आज भी इन्हें कार्य दिया जा रहा है...

अध्यक्ष : उत्तर है न, उत्तर मिला गया है न ?

श्री जितेंद्र कुमार : महोदय, तो क्या औचित्य है कि ऐसे संवेदक को बार–बार जब जाली सर्टिफिकेट है, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र है । फिर भी इन्हें निविदा दिया जा रहा है, यह हम सरकार से पूछना चाहते हैं ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस टेंडर के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उसके बारे में निविदा सं0–143364 के निष्पादन का मामला है । दिनांक–01.09.2025 को प्रथम बार तकनीकी बिड समिति की बैठक में सभी निवादाकारों यथा जिनके बारे में माननीय सदस्य आज पूछ रहे

हैं जितेन्द्र कुमार, राम प्रसाद सिंह और शिवशंकर प्रसाद को योग्य घोषित किया गया । महोदय, जब बिड होता है तो जो कंपीटीटर होते हैं वह अपना–अपना अभ्यावेदन लगाते हैं, तकनीकी वित्त समिति के निर्णय के उपरांत निविदाकार राम प्रसाद सिंह द्वारा जितेन्द्र कुमार के अनुभव प्रमाण पत्र, भुगतान प्रमाण पत्र गलत रहने और निबंधन को कार्य सूची में डालने का आग्रह किया गया । प्राप्त परिवाद के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया । जिसमें उल्लेख किया गया कि निविदाकार जितेन्द्र कुमार का अनुभव प्रमाण पत्र एवं भुगतान प्रमाण पत्र सही है । उक्त भुगतान प्रमाण पत्र में टंकण भूलवश संवेदक का पैन गलत अंकित हो गया है । साथ ही विभाग द्वारा निविदाकार जितेन्द्र कुमार के निबंधन को विषयांकित निविदा के निष्पादन तक कालीकृत नहीं किया गया, जो उनका डिमांड था । प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में तकनीकी बिड समिति की पुनः बैठक दिनांक–23.09.2025 को आहूत की गयी, जिसमें पूर्व के निर्णय को यथावत रखते हुये सभी निविदाकारों को योग्य घोषित किया गया । दिनांक–23.09.2025 को विषयांकित निविदा का वित्तीय बिड खोला गया जब टेक्निकल फाइनल हो गया तो वित्तीय बिड खोला गया एवं न्यूनतम करदाता जितेन्द्र कुमार को दिनांक–24.09.2025 को संपन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक के कार्यवाही के आलोक में अभियंता प्रमुख ने कार्य आदेश निर्गत किया । महोदय, ये दूसरा है । लेटरऑन एक अलग पुल का उनका काम था, जिसमें कि लोगों ने अलग से जानकारी दी कि यह पुल पर उन्होंने जो पेपर लगाया है, वह गलत है । फिर उनको उसमें हमलोगों ने ब्लैकलिस्ट किया । लेकिन ये निविदा जिसकी जितेंद्र जी जानकारी दे रहे हैं, ये पहले का मामला है । उसमें वह He was compitent उसमें हमलोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं, लोग कोर्ट जायेगा । दूसरे बार में उन्होंने दिया तो उनको गलत पाया गया तो उनको हमलोगों ने ब्लैकलिस्ट कर दिया ।

श्री जितेंद्र कुमार : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : कितना स्पष्ट जवाब है जितेंद्र जी ।

श्री जितेंद्र कुमार : अध्यक्ष महोदय हम यह कहना चाहते हैं कि इसके बावजूद भी नालंदा में बिहार शरीफ, प्रमंडल में इन्हें काम दिया गया । महोदय, विभाग के द्वारा इनको काली सूची में भी डाला गया और हमने विभागे को भी इसकी सूचना दिनांक– 26.09.2025 को दी थी और एक ही समस्या नहीं है । इसके अलावा इनका जो इनकम टैक्स रिटर्न है वह भी गलत है, दूसरे के नाम पर दिया गया है । इनका पेमेंट का सर्टिफिकेट भी गलत है । बार–बार ऐसी गलती हो रही है...

अध्यक्ष : इसलिये न विस्तृत जवाब दिया गया है, माननीय मंत्री जी ने कहा है ।

श्री जितेंद्र कुमार : तो क्या सभी निवादाओं को रद्द करने का विचार रखते हैं और अभियंता बार–बार गलती कर रहे हैं तो ऐसे दोषियों पर कार्रवाई करने का सरकार विचार रखती है ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर ब्लैकलिस्ट होने के बाद इनको काम मिला होगा तो निश्चित रूप से सदन में कह रहे हैं, उस अभियंता को न हम निलंबित करेंगे, उनको केबिनेट ले जाकर उनको बर्खास्त करने का रिकमंडेशन करेंगे लेकिन ब्लैकलिस्ट होने के बाद अगर काम मिला हो ।

अध्यक्ष : श्रीमती ज्योति देवी ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–1321, श्रीमती ज्योति देवी (क्षेत्र सं0–228, बाराचट्टी (अ0जा0))</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है किः–

प्रश्नगत योजना हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया था, जिसके तहत प्रस्तावित बायाँ मुख्य नहर का निर्माण कर उसके माध्यम से गोआत पईन एवं गोपालखेरा पईन में पानी दिया जाना था।

उक्त दोनो पईन का तल प्रस्तावित मुख्य नहर के तल से ऊँचा है। अतः प्रस्तावित मुख्य नहर से उक्त दोनों पईनों में जलश्राव दिया जाना तकनीकी रूप से संभव नहीं है।

इस क्रम में केन्द्रीय रूपांकण शोध एवं गुण नियंत्रण, पटना की तकनीकी टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात टीम के द्वारा सुझाव दिया गया कि मुहाने नदी से सिंचाई हेतु पानी को पम्प के माध्यम से लिफ्ट कर पाईप के द्वारा गोआत पईन एवं गोपालखेरा पईन में पानी दिया जा सकता है।

उक्त के आलोक में DPR तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है।

श्रीमती ज्योति देवी : महोदय, पूछती हूं ।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है ?

श्रीमती ज्योति देवी : महोदय, उत्तर मिला है लेकिन संतोषजनक नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, 2013 से मैं यह सवाल उठा रही हूं...

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्या को उत्तर से संतोष नहीं है तो सदस्या महोदया को संतोष दिलाने के लिये सरकार ने एक वैकल्पिक योजना बनाई है । चूंकि उनका जो सुझाव था वह तकनीकी रूप से संभाव्य नहीं था, न व्यवहार्य था । चूंकि इसमें भी वही बात है जहां से पानी ले जाने की बात है, जहां ले जाने की बात है वह जगह ऊंची है इसलिये नहर से तो पानी जा नहीं

सकता है । लेकिन माननीय सदस्या के संतुष्टि के लिये हमलोगों ने एक वैकल्पिक योजना बनायी है कि पानी को लिफ्ट करके और अलग स्टोर करके वहां से पाईप के माध्यम से पानी इन इलाकों में पहुंचाया जायेगा । हमलोग उस पर काम कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : श्री संदीप सौरभ ।

श्रीमती ज्योति देवी : महोदय...

अध्यक्ष : इतना बढ़िया जवाब है । आपके समस्या का समाधान कर दिया गया । धन्यवाद दे दीजिये सरकार को ।

श्रीमती ज्योति देवी : महोदय, इसमें हम कहना चाह रहे हैं कि 2013 से जब भी सवाल उठाते हैं, हम यहां 2013 से सवाल उठा रहे हैं...

अध्यक्ष : अब समाधान निकल गया ।

श्रीमती ज्योति देवी : लेकिन जवाब में दिया गया है कि प्रक्रिया चल ही रही है...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने स्वंय कहा है ।

श्रीमती जयोति देवी : महोदय, 13 वर्ष हो गया अगर कुछ भी विकल्प इन्होंने सोचा है तो तत्काल वह, चूंकि हमारा क्षेत्र पठारी एरिया है, वर्षा आधारित खेती होती है । इसलिये अतिआवश्यक है जो भी निर्णय हो, तुरंत किया जाए । यह आश्वासन...

अध्यक्ष : श्री संदीप सौरभ ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय...

अध्यक्ष : आप कहां से आ गये । ये उनके क्षेत्र का विषय है ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं...

श्रमती ज्योति देवी : महोदय, मंत्री जी आश्वासन दे देते...

अध्यक्ष : हो जायेगा, जल्दी किया जायेगा ।

श्रीमती मनोरमा देवी : महोदय, मेरे जिला में भी...

अध्यक्ष : ठीक है, आप भी लिखकर अलग से दे दीजियेगा ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–1322, श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र सं0–190, पालीगंजं)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पटना जिला के ग्राम गौसगंज में प्रश्नगत कब्रिस्तान लुआई नदी के दायें किनारे से लगभग 100 मी० की दूरी पर अवस्थित है । लुआई नदी एक बरसाती नदी है । वर्ष 2025 में नदी में अधिक जलश्राव होने पर ग्राम–गौसगंज में नदी तट का आंशिक क्षरण हुआ है, परन्तु स्थल सुरक्षित है ।

प्रश्नगत ग्राम समदा एवं डुमरी पुनपुन नदी के बायें किनारे पर तथा ग्राम चिक्सी नटटोला एवं देवरीया पुनपुन नदी के दायें किनारे पर अवस्थित है।

ग्राम–समदा एवं देवरीया में पूर्व में कटाव निरोधक कार्य कराया गया है, जो प्रभावी है एवं स्थल सुरक्षित है ।

ग्राम–डुमरी एवं चिक्सी नटटोला में बाढ़ अवधि 2025 में कटाव परिलक्षित नहीं हुआ एवं नदी से वर्तमान में कटाव नहीं हो रहा है ।

बाढ़ अवधि में प्रश्नगत क्षेत्रों में कटाव परिलक्षित होने पर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थलों को सुरक्षित रखा जायेगा।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय उत्तर मिला हुआ है । पालीगंज विधान सभा से संबंधित मामला हमने माननीय मंत्री जी से पूछा था । भूमि के कटाव का सवाल है और गौसगंज एक अल्पसंख्यक बहुल गांव है, वहां का कब्रिस्तान लुआई नदी से कट रहा है । हमने उसको कटाव रोधक कार्य करवाने के लिये लिखा था लेकिन जो जवाब मिला हुआ है उसके अलावा दो–तीन और गांव हैं । जवाब जो मिला है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं । सरकार कह रही है कि वह 100 मीटर की दूरी पर अवस्थित है । एक तो उस कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं है, 100 मीटर से काफी कम है और 2025 में, जो जवाब में भी स्वीकार किया गया है कटाव हुआ है । जब कब्रिस्तान बरसाती नदी के कटाव से लगातार टूट रहा है तो माननीय मंत्री जी को उसका ठीक से जांच करवाकर उसका कटाव रोधक कार्य वहां पर करवाना चाहिये।

दूसरा महोदय, समदा पुल अभी 17 करोड़ की योजना से वहां समदा पुल बना रहा है, बहुत ऐतिहासिक जगह है ।

(क्रमशः)

टर्न–5 / धिरेन्द्र / 18.02.2026

...क्रमशः...

श्री संदीप सौरभ : महोदय, पुनपुन नदी से करीब–करीब 50 मीटर पश्चिम चला गया है, पुनपुन पदी कटाव कर के जो स्पेस था, जहाँ पर मेला लगता था समदा का, वह धीरे–धीरे खत्म हो रहा है, उसका भी जवाब माननीय मंत्री जी का है कि पूर्व में बगल साईड में कराये हैं तो वहां नहीं करायेंगे । महोदय, उसी तरह से डुमरी प्राथमिक विद्यालय है, नदी से मुश्किल से 10 फीट बचा हुआ है तो वहां पर कटाव रोधक कार्य कराने के लिए है तो पहला पूरक मेरा मंत्री महोदय से है कि जिस गांव का हमने लिस्ट दिया था इसमें...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तीन पूरक पूछ लिये हैं ।

श्री संदीप सौरभ : नहीं महोदय, वह एक ही प्रश्न में है । महोदय, इसका सरकार जल्द–से–जल्द करवाना चाहेगी ? एक प्रश्न यह है । दूसरा प्रश्न है कि भूमि कटाव रोकने के लिए जो सरकार कटाव रोधक कार्य कराती है, उसकी कोई वेलेडिटी नहीं है कि वह कितने साल चलेगा । क्या सरकार उसको पांच साल या कुछ साल अनुरक्षण नीति उसमें लागू करना चाहती है ? यह मेरा दो प्रश्न है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, हम तो आपके प्रश्न की सत्यता को माने हैं कि उस इलाके में कटाव की संभावना होती है । उन्होंने अलग–अलग स्थलों का जिक्र किया था, उनके संबंध में भी हमने बताया है चूंकि कब्रिस्तान की बात है तो हमने कहा था कि 100 मीटर पर है वह तो सही है लेकिन हमने यह भी कहा है कि अगर बाढ़ अवधि में उस कब्रिस्तान पर कोई इस तरह का खतरा आता है तो सरकार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य करा कर कब्रिस्तान की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, हमने यह भी कहा है । समदा गांव के बारे में कह रहे हैं, हमलोगों ने वर्ष 2025 के बाढ़ के पूर्व भी उस स्थल पर काम कराया था लगभग एक किलोमीटर के दायरे में लेकिन महोदय, जब नदियों की प्रवृति होती है धारा, दिशा बदलते रहने की, उसके कारण हर वर्ष उसका आकलन होता है कि आक्रामयता कहां पर है और कहां पर घटी है, उसके हिसाब से हमलोग इस बार भी करा रहे हैं । आप जिस–जिस स्थल की बात किये हैं हम अलग से भी उसको दिखवा कर, उसको सुरक्षित रखने के लिए जो भी व्यवस्था होगी, विभाग और सरकार करेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती कविता देवी ।

(व्यवधान)

कितना स्पष्ट जवाब आया है, सरकार तैयार है ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, कटाव रोधक कार्य आज हो रहा है, अगले साल फिर से कटाव होने लगेगा तो इसलिए कोई अनुरक्षण नीति सरकार बनाना चाहती है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका सारा विषय आ गया है । माननीय सदस्या श्रीमती कविता देवी ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1323, श्रीमती कविता देवी (क्षेत्र संख्या–69, कोढ़ा (अ॰जा॰))</u>

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नाधीन पथ कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखण्ड में एन0एच0–81 से एन0एच0–31 होते हुए पंचायत भवन, बासगाढ़ा तक जाने वाली सड़क का सर्वे एन0एच0–31 पंचायत भवन, बासगाढ़ा के नाम से Left Habitation App के माध्यम से किया गया है, जिसका सर्वे आई0डी0 – 94820 है एवं लम्बाई 1.5 कि0मी0 है।

निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपको उत्तर मिला है ?

श्रीमती कविता देवी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है, सकारात्मक भी है लेकिन माननीय मंत्री जी से यही कहेंगे कि जल्द–से–जल्द काम चालू करा दें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने कहा है, यह Left Habitation का मामला है और Left Habitation में हमने पहले के प्रश्न के उत्तर में कहा है कि हमारी नीति प्रायोरिटी पर है लेकिन माननीय सदस्या को बता दें कि इनके विधान सभा में पिछले वित्तीय वर्ष में 185.4 किलोमीटर सड़क लिये हैं और 196 करोड़ रुपये इनके सिर्फ विधान सभा में खर्च हुआ है । इसलिए इनके विधान सभा के लिए सरकार हमेशा चिंतित रहती है । नेता चिंतित रहते हैं तो भविष्य में भी इनके विधान सभा में काम होगा ।

श्रीमती कविता देवी : महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1324, श्री सुरेंद्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या–01, वाल्मीकिनगर)

श्री सुरेंद्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, हमको उत्तर नहीं मिला है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वह प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय भवन के निर्माण से संबंधित है । हमने कल ही सदन में विस्तार से जवाब दिया था कि राज्य में हम 473 प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय का निर्माण करा रहे हैं और माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वह प्रक्रियाधीन है । जल्द–से–जल्द इसकी समीक्षा कर इसका निष्पादन करायेंगे ।

श्री सुरेंद्र प्रसाद : महोदय, जल्द–से–जल्द करा दिया जाय । इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद होगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि करा देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1325, श्री शम्भू नाथ यादव (क्षेत्र संख्या–199, ब्रहमपुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–1326, श्री सतीश कुमार सिंह यादव (क्षेत्र संख्या–203, रामगढ़)

(मुद्रित उत्तर)

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि एन0एच0–19 (जी0टी0 रोड) का निर्माण एवं संधारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। प्रश्नगत स्थल ग्राम डहला, वाराणसी–औरंगाबाद खंड के एन0एच0–19 के दुर्गावती नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। वर्तमान में उक्त खंड के 6 लेन परियोजना का निर्माण कार्य DBFOT (Toll) Mode पर

प्रगति पर है। एकरारनामा के अनुसार एन0एच0–19 के कि0मी0 854+700 पर दुर्गावती नदी पर एक अतिरिक्त पुल का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त, दुर्गावती नदी के पश्चिमी भाग में लगभग 900 मीटर की दूरी के अन्दर 03 पुल का निर्माण कार्य पूर्ण है।

ग्राम–डहला/दुर्गावती नदी के पूर्वी भाग लगभग 200 मीटर की दूरी के अन्दर 02 अंडर पास उपलब्ध हैं। यह खंड वर्तमान में चार लेन मानक का है।

वर्तमान में उक्त स्थल पर यातायात का आवागमन सूचारू रूप से चल रहा है। अतिरिक्त अंडरपास निर्माण के मांग के संबंध में परियोजना के स्वतंत्र अभियंता (Independent Engineer) को तकनीकी अध्ययन हेतु निर्देशित किया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर मुद्रित है ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक पूछ लीजिये ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था कि एन॰एच॰–19 जी॰टी॰ रोड पर अंडरपास के लिए । जिस जगह पर हमने अंडरपास की बात की है, वहां वर्ष 2011 से एन॰एच॰–19 का निर्माण कार्य शुरू हुआ छः लेन के लिए....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सीधे पूरक पूछ लीजिये ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, वहां पर ग्रामीण कार्य विभाग की तीन सड़क है जो सीधे एन॰एच॰–19 से जुड़ती है लेकिन उन तीनों सड़कों के लिए रामगढ़–दुर्गावती पथ है, दूसरी तरफ चैनपुर–हाटा पथ है और दुर्गावती–चैनपुर है तथा दुर्गावती–हाटा पथ है लेकिन वहां अंडरपास नहीं होने से हर साल सैंकड़ों लोगों की मृत्यु होती है, लोग धरना प्रदर्शन करते हैं । प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि अंडरपास बनेगा, फिर भी नहीं बनता है । महोदय, पिछले साल वहीं पर सड़क दुर्घटना में हमारे यहां करारी के तीन लोग गाड़ी से जा रहे थे....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी के जवाब को हमने देखा है, उन्होंने कहा है।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, नवघरा हमलोगों के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी के गांव की शादी में जा रहे थे, तीन लोग ऑन स्पॉट डेथ कर गए, अभी पिछले अगस्त में दो लोग मर गए....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने पूरक पूछ लिया, अब जवाब सुन लीजिये ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि आश्वासन न हो, वहां अंडरपास जरूरी है उसका निर्माण कराया जाय । सरकार इस पर क्या विचार करती है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और अभी तक वहां.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने विषय को रख दिया, अब सरकार का उत्तर ले लीजिये। माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्नगत मामला है यह राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है और एन॰एच॰–19 के दुर्गावती नदी के पश्चिमी तट पर जो स्थित है औरंगाबाद के, उस पर छः लेन परियोजना निर्माण कार्य प्रगति पर है । एक अतिरिक्त पुल का भी इस पर प्रावधान है । एक पुल भी एन॰एच॰–19 पर दुर्गावती नदी पर बनने वाला है। इसके साथ–साथ 900 मीटर की दूरी पर पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और जो अंडरपास है, जहां माननीय सदस्य चाहते हैं उसके 200 मीटर की दूरी पर अंडरपास उपलब्ध है जो चार लेन पर है । उसके बाद भी जब यह पत्र आपका मिला है तो हमलोगों ने इसको राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि अतिरिक्त अंडरपास निर्माण के मांग के संबंध में परियोजना के स्वतंत्र अभियंता (Independent Engineer) को तकनीकी अध्ययन हेतु निर्देशित किया जाय और उनकी रिपोर्ट आने के उपरांत तद्नुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब क्या है ?

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, वर्ष 2011 से आज 15 साल हो गए....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उस पर मत जाइये । अभी माननीय मंत्री जी ने साफ कहा है कि इस संदर्भ में...

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, लोगों के जिंदगी का सवाल है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसीलिए तो सरकार जवाब दी है ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, वहां के लोगों के जिंदगी का सवाल है । यहां माननीय हमलोगों के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बैठे हुए हैं...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार गंभीर है ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, इनके इलाके की भी सड़क वहां जुड़ती है, उनसे पूछ लिया जाय । जिस अंडरपास का माननीय मंत्री जिक्र कर रहे हैं, उस अंडरपास पर पहुँचने के लिए इन पथ निर्माण की सड़कों से कोई सर्विस लेन है ही नहीं, सीधे वह एन॰एच॰–19 से जुड़ती है । माननीय मंत्री जी जिसका जिक्र कर रहे हैं जो 900 मीटर की दूरी पर है तो दुर्गावती–रामगढ़ सड़क से वहां पहुँचने के लिए कोई सड़क ही नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट कहा कि अतिरिक्त अंडरपास के निर्माण के संबंध में Independent Engineer, परियोजना के स्वतंत्र अभियंता को तकनीकी अध्ययन हेतु निर्देशित कर दिया गया है और वह देख लेंगे ,तब हम इस पर बना देंगे ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब बैठिये । सरकार का इतना स्पष्ट जवाब है । माननीय सदस्य श्री जनक सिंह ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1327, श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या–116, तरैया)

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नाधीन तारांकित प्रश्न दो अलग–अलग पथों के आरेखन से संबंधित हैः–

पानापुर थाना एस0एच0–104 से प्रखण्ड मुख्यालय, पानापुर होते हुए सतजोड़ा मुख्य पथः– इस पथ का शीर्ष MR-3054 अन्तर्गत पानापुर से सतजोड़ा के नाम से मरम्मति कार्य कराया गया है, जिसकी लं0.7.00 कि0मी0 है। पथ के कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि 25.06.2021 है। पथ अनुरक्षण अवधि के पाँचवे वर्ष में है।

एस0एच0 104 तुर्की (पानापुर) से राजकीय बुनियादी विद्यालय मोरिया, कोंध भगवानपुर उच्च विघालय तिनमुहानी होते हुए पर्यटन स्थल मथुरा धाम नारायणी नदी तक पथः– उक्त पथ चार पथों से संबंधित हैः–

(i) एस0एच0–104 तुर्की (पानापुर) से जिपुरा राजपुत टोला पथः– यह पथ पानापुर से जिपुरा भाया रामदासपुर मोरिया PMGSY पथ का पथांश है। इस पथ का सर्वे Upgradation App के द्वारा किया गया है, जिसका सर्वे आई0डी0–5884 है। समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता तथा प्राथमिकता के आधार पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

(ii) जिवपुरा राजपुत टोला से भोरहा यादव टोला पथः– इस पथ का पानापुर से जिवपुरा रामदासपुर (अवशेष भाग) पथ के नाम से RRSMP अन्तर्गत निर्माणाधीन है।

(iii) भोरहा यादव टोला से भगवानपुर खिरी राजपुत टोला पथः– यह पथ टी05 भगवानपुर बाजार से क्वार्टर बाजार तक PMGSY-III (FDR) अन्तर्गत निमार्णाधीन पथांश है।

(iv) भगवानपुर खिरी राजपुत टोला से मथुरा धाम पथः– यह पथ उच्च विघालय कोंध भगवानपुर से मथुरा धाम पथ, लं0.1.65 कि0मी0 के नाम से बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण निति-2018 अंतर्गत दि0-20.02.2024 को पूर्ण किया गया है। पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के द्वितीय वर्ष में है।

श्री जनक सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्राप्त है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछ लीजिये ।

श्री जनक सिंह : महोदय, हमने अपने विधान सभा के पानापुर प्रखंड अंतर्गत पानापुर थाना से वाया प्रखंड मुख्यालय होते हुए, हमारे नारायणी नदी पर जो बंगड़ा घाट पुल बना हुआ है, उसी को जोड़ने के लिए है जो 07 किलोमीटर है। जिसका कार्य

25.06.2021 को शुरू हुआ और 25.06.2026 को पूरा हो रहा है, पथ अनुरक्षण अवधि समाप्त हो रहा है । यह तो पहला हुआ कि जून में समाप्त हो रहा है और यह थाना से लेकर प्रखंड मुख्यालय होते हुए बंगड़ा घाट जो नारायणी नदी पर पुल बना, उससे जुड़ा हुआ मुख्य पथ है । दूसरा है कि वहीं से बगल में तुर्की एस॰एच॰–104 से नारायणी नदी...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सप्लीमेंट्री पूछ लीजिये ।

श्री जनक सिंह : महोदय, वही पूछ रहे हैं । इसमें चार पार्ट में जवाब आया हुआ है इसलिए इसको दो रोड पर, एक तो आपका जून, 2026 में पूरा हो रहा है और दूसरा जो है तुर्की एस॰एच॰–104 से मोरिया बेसिक स्कूल – एच॰एस॰ कोंध भगवानपुर होते हुए पर्यटन स्थल नारायणी नदी के तट पर मथुरा धाम तक, तो इसका चार पार्ट में उत्तर आया हुआ है । एक तो अनुरक्षण नीति समाप्त हो गया है जिसका इन्होंने कहा है कि हम उसका डी॰पी॰आर॰ वगैरह बना दिये हैं, सब कुछ हो गया है लेकिन उसका तीन पार्ट जो है और यह पथ बड़ा महत्वपूर्ण है तो...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब जवाब सुन लीजिये ।

श्री जनक सिंह : महोदय, एक में उन्होंने कहा है कि आपको, प्रथम में उन्होंने जवाब तीन पार्ट में दिया....

अध्यक्ष : जनक बाबू, आप पूरक पूछ लीजिये ।

श्री जनक सिंह : महोदय, मेरा यह कहना है कि दो जो है, एक तो है दूसरे पथ में, आपको एस॰एच॰–104 से तुर्की से मोरिया चौक जा रही है और दूसरा, जो जून में समाप्त हो रहा है तो क्या माननीय मंत्री जी इन दोनों का चौड़ीकरण यानी दो लेन में कराने का विचार रखते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

टर्न–6 / अंजली / 18.02.2026

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये जिन सड़कों का प्रश्न कर रहे हैं, वह स्टेजवाइज बना है, डिफरेंट–डिफरेंट योजनाओं से बना है, कुछ पी0एम0जी0एस0वाई से बनी है, कुछ हमारी अनुरक्षण नीति के अंदर है, जो अनुरक्षण नीति के अंदर खत्म हो रहा है, उसका मैंने स्पष्ट रूप से जवाब दिया है कि जो नई अनुरक्षण नीति है, उसमें हम उसको लेने का काम करेंगे । जून में खत्म हो रहा है, उसको हम लेने का काम करेंगे । इनकी इच्छा है कि उस पूरी सड़क को हम एक बार डबल लेन करने का काम करें, जो इनका है एस. एच.–104 से मथुरा धाम तक उसकी पूरी कनेक्टिविटी डबल लेन करने की, तो आलरेडी सरकार की नीति है सात निश्चय–3 में हमने निर्णय किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया है कि सरकार ने कि जो हमारी प्रमुख सड़कें हैं उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट और ट्रैफिक सर्वे आने के बाद उस पर हम समुचित

निर्णय करेंगे । अब है कि हमारे यहां हरेक विधान सभा में एक–एक सौ सड़क डबल करने के लिए आ रहा है और पैसा कम है तो जो परिस्थिति होगी और हम समझते हैं कि वहां की संचालन समिति से जो ट्रैफिक सर्वे रिपोर्ट और फिजिबिलिटी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद प्रायोरिटी पर निर्णय करेंगे और इसको भी बना देंगे, लेकिन यह है कि आज बनेगा कि अगले साल बनेगा यह तो निर्णय आपलोगों को जिला संचालन समिति में करना है और उसके बाद आएगा तो बना देंगे, सरकार की नीयत है बनाना ।

तारांकित प्रश्न सं॰–1328, श्री राजेश कुमार मंडल (क्षेत्र सं॰–82, दरभंगा ग्रामीण)

(लिखित उत्तर)

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिला के मनिगाछी रेलवे स्टेशन पर अंडरपास के निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक–1026 (ई०) डब्लू०ई०, दिनांक–11.02.2026 द्वारा पूर्व मध्य रेलवे से अनुरोध किया गया है ।

श्री राजेश कुमार मंडल : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया है लेकिन मैं उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं । हम अंडरपास की बात किए थे । अध्यक्ष महोदय, आपको बता दें, हम दरभंगा ग्रामीण विधान सभा से आते हैं, आजादी के बाद एन0डी0ए0 के, आपलोगों के आशीर्वाद से पहला विधायक हुए हैं, तो हम तो माननीय मंत्रीजी सभी विभाग से आग्रह करेंगे कि दरभंगा ग्रामीण विधान सभा के आग्रह पत्र पर कोई विचार नहीं, स्वतः स्वीकार करके काम को आगे बढ़ाइए चूंकि आजादी के बाद वहां कुछ काम ही नहीं हुआ है, चूंकि अपने लोग नहीं थे ।

अध्यक्ष : बैठ जाइए । माननीय मंत्री ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की भावना को देखते हुए दरभंगा जिला के मनिगाछी रेलवे स्टेशन पर अंडरपास के निर्माण के लिए बिहार सरकार ने मुख्य अभियंता सड़क सुरक्षा कार्य पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर को अनुशंसा कर दी है और उक्त अंडरपास के निर्माण हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाए, इसका भी हमलोगों ने अनुरोध कर दिया है आपके प्रश्न मिलने के बाद ।

श्री राजेश कुमार मंडल : बहुत–बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं॰–1329, श्री कृष्णनंदन पासवान (क्षेत्र सं॰–13, हरसिद्धि)

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि क्षतिग्रस्त लोहा पुल पंचायत द्वारा निर्मित पी०सी०सी० पथ के आरेखन पर है । यह ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर नहीं है । पुल के एक तरफ अवस्थित धवही टोला बसावट को कार्य प्रमंडल, अरेराज द्वारा निर्मित मुशहर टोला L024 पथ से संपर्कता प्राप्त है एवं दूसरी तरफ अवस्थित जय सिंह गोखला बसावट को कार्य प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा निर्मित L029 से भैंसडा पथ से संपर्कता प्राप्त है ।

अतः पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : महोदय, उत्तर प्राप्त है । माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर नहीं है, इसलिए पुल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । मेरा पूरक प्रश्न है माननीय मंत्री जी से कि दो प्रखंडों को जोड़ने वाली 8 पंचायत उससे प्रभावित होती है और पुल के दोनों तरफ महादलित बस्ती है, ऐसी स्थिति में एक तरफ सरकार विकास की गंगा बहा रही है, तो माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर जोड़कर उक्त पुल बनाने का प्रस्ताव रखेंगे या बनाने का काम करेंगे, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, क्योंकि माननीय विधायक और माननीय नेता ने आग्रह किया है कि दोनों ओर महादलित की बसावट है, इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगा लेते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगाकर देख लेते हैं संभव होगा तो कराने का प्रयास करेंगे ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : बहुत–बहुत धन्यवाद ।

<u>तारांकित प्रश्न सं॰–1330, श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल (क्षेत्र सं॰–153, गोपालपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत जहान्वी चौक से बिन्दटोली तटबंध का उपयोग बाढ़ संघर्षात्मक सामाग्रियों की ढुलाई एवं निरीक्षण के लिए किया जाता है, जिसके लिए तटबंध को आवश्यकतानुसार मोटेरेबल रखा जाता है ।

केंद्रीय जल आयोग/गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा तटबंध शीर्ष पर कालीकरण कार्य/मानक के अतिरिक्त तटबंध चौड़ीकरण हेतु योजनाओं की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है ।

तटबंध पर पक्कीकरण कार्य पथ निर्माण विभाग या ग्रामीण कार्य विभाग से कराया जा सकता है । इस हेतु विभाग द्वारा अनापत्ति पत्र दी जा सकती है ।

श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल : महोदय, प्रश्न का सही जवाब भी है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से चूंकि उनका सैदपुर से एक अलग रिश्ता है, तो मैं चाहूंगा कि उक्त तटबंध पर या तो...

श्री भाई बिरेन्द्र : महोदय, कौन–सा रिश्ता है, जरा बता दीजिए ।

श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल : नहीं वह अंदर की बात है रहने दीजिए ।

अध्यक्ष : अंदर की बात है । बोलिए ।

श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल : महोदय, मैं सिर्फ इतना ही चाहूंगा, मंत्री जी से अनुरोध है कि वे नाबार्ड से या किसी अन्य योजना से इसको करवाने का आदेश दे दें कि उस पर पक्कीकरण सड़क बन जाए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, बुलो मंडल जी ने बात तो ठीक ही कही है, रिश्ता भी है और हमारी सरकार की खासियत भी रही है कि सरकार के कामकाज का तरीका रिश्तों से प्रभावित नहीं होता है । इसलिए महोदय, हमने जो इसमें कहा है, बुलो मंडल जी ने जो बात कही है, विभाग भी आवश्यक महसूस करता है, क्योंकि जब कोई आकस्मिक स्थिति आती है, तो उस रीच में उस जगह पर बांध के उस अंश पर आवागमन भी बहुत बाधित होता है, एक चर्चा जिसकी इन्होंने नहीं की है वह समस्या भी वहां पर रहती है अतिक्रमण की, लेकिन हमलोगों के विभाग का जो अध्यादेश, यानी मैंडेट है उसमें है कि हमलोग बांध को सिर्फ मोटरेबल बनाकर अपने काम के लिए रखते हैं, कोई उस पर चौड़ी सड़क या तो ग्रामीण कार्य विभाग या उससे भी चौड़ी सड़क हो तो पथ निर्माण विभाग बनाती है, इसलिए हमने इसमें इंगित भी किया है कि अगर कोई दूसरा विभाग इस पर काम करना चाहेगा तो हमलोग भी पहल करके, माननीय सदस्य का कहना बिल्कुल सही है कि उस पर अगर चौड़ी और पक्कीकृत सड़क बन जाती है, तो हमलोगों के विभाग को भी आसानी होगी, लेकिन चूंकि यह काम हमलोगों के विभाग के मैंडेट में नहीं है इसलिए हमें दिक्कत हो रही है, वरना सदस्य की भावना से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं ।

<u>तारांकित प्रश्न सं०–1331, श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र सं०–67, मनिहारी, अ०ज०जा०)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि वाणीपुर को MR अंतर्गत निर्मित Nawabganj Mansahi REO Road to Santhali tola (Banipur) पथ से संपर्कता प्राप्त है ।

वाणीपुर वार्ड संख्या–03 में तेतर मण्डल के घर बघवा पुल तक पथ का सर्वे छुटे हुए बसावट अन्तर्गत 'RWD Road To Tetar Mandal Ke Ghar To Bhaghwa Pul Banipur Colony' (लम्बाई 0.760 कि०मी०) के नाम से विभागीय App के माध्यम से सर्वे कर लिया गया है जिसका सर्वे आई.डी.–109909 है ।

निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है, इसमें कहा गया है कि इसका सर्वे कर लिया गया है । महोदय, जिस सड़क का मैंने प्रश्न किया है वहां अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के लोग उसमें रहते हैं और अभी तक

वहां सड़क से संपर्कता है ही नहीं और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में निधि उपलब्ध रहती है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इसी वित्तीय वर्ष में उसको बनाने का प्रश्न उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने कहा है कि इस वर्ष का हमलोगों ने लगभग 3 हजार बसावटों की संपर्कता का टारगेट रखा है, निधि की उपलब्धता क्या रहती है, हमलोग उसको प्रायोरिटी पर देखकर कराने का प्रयास करेंगे । आपका अनुसूचित जाति/जनजाति और सबसे निचले पायदान के लोगों का है, प्रयास होगा कि इसी वित्तीय वर्ष में लेने का प्रयास करें ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : महोदय, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि इसी वित्तीय वर्ष में होगा या नहीं ? वहां सड़क है ही नहीं, सड़क चलने लायक नहीं है ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, हमलोग की ही पार्टी के थे, कांग्रेस में मेरे चलते चले गए, वापस आ ही नहीं रहे हैं, नहीं तो बना देंगे ।

अध्यक्ष : श्री उदय कुमार सिंह ।

<u>तारांकित प्रश्न सं॰–1332, श्री उदय कुमार सिंह (क्षेत्र सं॰–226, शेरघाटी)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन प्रश्न में अंकित बसावटों को ग्रामीण कार्य विभाग के अलग–अलग पथों से एकल सम्पर्कता प्राप्त है ।

पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के किसी कोर नेटवर्क से संबंधित नहीं है । पुल स्थल के एक तरफ अवस्थित बसावट शेरपुर को ''RRSMP पथ L032–T01 से शेरपुर पथ'' से सम्पर्कता प्राप्त है तथा इमामगंज एवं डुमरिया को RCD पथ से सम्पर्कता प्राप्त है ।

शेरपुर से ''NH2 इमामगंज डुमरिया RCD पथ'' ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन में नहीं है । अतः शेरपुर से NH2 इमामगंज डुमरिया RCD पथ के बीच मोरहर नदी पर पुल निर्माण हेतु विभाग द्वारा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री उदय कुमार सिंह : महोदय, उत्तर प्राप्त है । माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इसको फिर से एक बार दिखवा लिया जाए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग । एक बार दिखवा लीजिए । इनको उत्तर मिला है ।

(व्यवधान)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न है वह एकल संपर्कता से संबंधित है । ऑलरेडी इस गांव को एकल संपर्कता प्राप्त है और इन्होंने मोरहर नदी पर पुल बनाने का आग्रह किया है, अभी हमलोगों के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

तारांकित प्रश्न सं॰–1333, श्री सियाराम सिंह (क्षेत्र सं॰–179, बाढ़)

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन बिल्लौर ग्राम को बाढ़ शहरी सरमेरा पथ से संम्पर्कता प्राप्त है ।

सम्प्रति प्रश्नाधीन पथ निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री सियाराम सिंह : महोदय, जवाब मिला है उससे मैं असंतुष्ट हूं । मैं यह पूछना चाहता हूं कि पहले से जो दिया गया है बाढ़ शहरी सरमेरा पथ का संपर्कता है वह काफी संकीर्ण रास्ता है और उससे गांव वालों को काफी परेशानी होती है और उस रास्ते से दूसरे जिला का भी है नालन्दा जिला का है, बेगूसराय का है, तो इस रास्ते का जो किया गया है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, इसको एक बार दिखवा लिया जाए क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने आपको गुमराह किया है । उसको दिखवा लिया जाए ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ऐसा गुमराह कोई नहीं करेगा, ऐसा नहीं है । मेरा पूरा होमवर्क किया हुआ है । आप यहां से संपर्कता मांग रहे हैं, ऑलरेडी दो तरफ से संपर्कता इसको प्राप्त है, हमने पूरा फोटो मंगाया है फिर भी आपकी इच्छा है इसको प्रयास करेंगे कि हो जाए ।

तारांकित प्रश्न सं॰–1334, श्री केदार प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र सं॰–93, कुढ़नी)

(मुद्रित उत्तर)

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत प्रश्नगत पथ, बलिया चौक से रामचन्द्रा भाया कुढ़नी रेलवे स्टेशन तक की लम्बाई 7.25 कि0मी0 एवं चौड़ाई 3.75 मी0 है, पथ की स्थिति अच्छी है ।

तकनीकी संभाव्यता, संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप पथ के चौड़ीकरण एवं नाला निर्माण पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : उत्तर मुदित है, पूरक पूछ लीजिए । समय समाप्त हो रहा है ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कुढ़नी प्रखंड में पटना मुजफ्फरपुर के बीच बलिया फोर लेन से कुढ़नी स्टेशन होते हुए केशोपुर तक जो सड़क है वह क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़क है, जिसमें कुढ़नी रेलवे स्टेशन, कुढ़नी स्वास्थ्य समुदाय केंद्र, कुढ़नी बाजार...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए । समय समाप्त हो रहा है ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : सड़क की चौड़ाई कम होने से हमेशा दुर्घटना होती रहती है, महीना में एक–दो मृत्यु भी हो जाती है ।

अध्यक्ष : आप अपना सुझाव दे दीजिए ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : निवेदन है कि नाला और सड़क बनवा देंगे, तो जनहित में बड़ी कृपा होगी ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रश्न किया गया है, निश्चित रूप से इस रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए, अभी 3.75 मीटर चौड़ी है यह, लेकिन पथ की स्थिति बहुत अच्छी है और हमलोग प्राथमिकता के आधार पर इस रोड का चौड़ीकरण भविष्य में कराएंगे ।

टर्न–7 / अभिनीत / 18.02.2026

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जायं । अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 18 फरवरी, 2026 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । श्री रणविजय साहू, स0वि0स0, श्री अजय कुमार, स0वि0स0, श्री संदीप सौरभ, स0वि0स0, श्री अरूण सिंह, स0वि0स0, श्री सुरेन्द्र प्रसाद, स0वि0स0 ।

आज दिनांक 18 फरवरी, 2026 को सदन में वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद–विवाद एवं मतदान निर्धारित है ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 172(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, बिहार की महागठबंधन सरकार ने राज्य की 13.7 करोड़ जनता की जाति आधारित गणना के आंकड़ों के आधार पर वंचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु 9 नवम्बर, 2023 को विधानमंडल के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65 परसेंट कर दिया था । विदित हो कि पिछले 35 वर्षों से तमिलनाडु में आरक्षण की सीमा 69 परसेंट है जिसे तत्कालीन केंद्र सरकार ने संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल कर कानूनी सुरक्षा प्रदान की थी । दुर्भाग्यवश बिहार के इस कानून को न्यायिक प्रक्रियाओं के कारण वर्तमान में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसे केंद्र द्वारा नौंवी अनुसूची का संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ।

अतः दिनांक 18.02.2026 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को स्थगित कर राज्य के करोड़ों वंचितों के हितों की रक्षा हेतु सरकार एक सशक्त कमेटी का गठन करे जो समयबद्ध सीमा के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार पुनः नया विधेयक लाकर उसे पारित करे । साथ ही, केंद्र सरकार पर यह दबाव बनाये कि उसे अविलंब संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल किया जाय ताकि इसे स्थायी कानून कवच प्राप्त हो सके जैसे अति लोक महत्व के विषय पर विर्मश हो ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य जिवेश जी ।

श्री रणविजय साहू : महोदय..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने पढ़ लिया ।

(व्यवधान)

श्री रणविजय साहू : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है । आरक्षण का सवाल है...

अध्यक्ष : आपको पढ़ने की अनुमति दी गयी और आपने पढ़ लिया । सरकार ने इन बातों को सुन लिया है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

श्री जिवेश कुमार : महोदय, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आपका संरक्षण भी चाहता हूं । बैठ जाइये आपके हित की ही बात कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, आपका तो बड़ा लंबा अनुभव रहा है इस सदन में और आपने कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है । लालू जी, राबड़ी जी, जीतन राम मांझी जी और वर्तमान में बिहार के सर्वप्रिय, मानवप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के साथ आपने काम किया है....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं । माननीय सदस्यगण, कृपया वेल से अपने आसन पर बैठ जायं । आपको पढ़ने की अनुमति दी गयी थी ।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय मुख्यमंत्रीजी, माननीय उप मुख्यमंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी के द्वारा दिये गये आश्वासन को क्या कोई अधिकारी या अधिकारी का समूह पलट सकता है ? मैं यह नियमावली लेकर खड़ा हूं । अगर इस सदन की गरिमा ही नहीं रहेगी तो फिर सदन चलाने का मतलब क्या होगा ? यह राजकीय आश्वासन समिति का मैटर बनता है और नियम 285 स्पष्ट कहता है कि समिति मंत्रियों द्वारा....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जायं । आपने अपनी बातों को रखा न । आपने अपनी बातों को रख दिया है ।

श्री जिवेश कुमार : सदन में समय–समय पर दिये गये आश्वासनों, प्रतिज्ञानों और वचनों आदि की जांच करेगी और स्पष्ट रूप से किस हद तक ऐसे आश्वासनों, प्रतिज्ञानों और वचन आदि कार्यान्वित किये गये हैं इसकी समीक्षा करेगी । यदि कार्यान्वित किये गये हैं तो यह कार्यान्वयन इस प्रयोजन के लिए आवश्यक कम–से–कम कितने समय के भीतर हुआ है । अध्यक्ष महोदय, यह सदन के विशेषाधिकार का हनन है कि सदन में मंत्री के द्वारा दिये गये उत्तर को कोई अधिकारी या अधिकारी का समूह पलट दे, इस सदन के विशेषाधिकार का हनन है...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : यह सब देख लेते हैं । माननीय सदस्य श्री बिजय सिंह ।

श्री जिवेश कुमार : हुजूर, इस पर विचार होना चाहिए ।

अध्यक्ष : विचार किया जायेगा ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जायं । आपकी बात सुन ली गयी ।

श्री बिजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कटिहार जिलांतर्गत बरारी विधान सभा के कुरसेला प्रखंड के कुरसेला बाजार में दिनांक– 15.02.2026 को भीषण आग से लगभग 25 करोड़ की क्षति हुई है, जिसमें 500 दुकान भी जलकर राख हो गये ।

अतः मैं सदन के माध्यम से अग्निपीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री सहायता राशि योजना से 10–10 लाख रुपये देने की मांग सरकार से करता हूं।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे । माननीय सदस्य श्री ललन राम ।

शून्यकाल

श्री ललन राम : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य अंतर्गत शिक्षा सेवक (टोला सेवक), विकास मित्र एवं तालिम मरकज को राज्यकर्मी का दर्जा, मानदेय बढ़ोतरी एवं आवास योजना (कॉलोनी) का लाभ देने की मांग सरकार से करता हूं ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष : बोलिए ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज है विश्वास, इसीलिए जनता इन लोगों को 25 सीट पर पहुंचा दी कि जनता के ऊपर इनको विश्वास ही नहीं है और आज यहां पर जातीय गणना की लड़ाई लड रहे रहे हैं कि 85 परसेंट दो । जब इनकी सरकार थी तो अतिपिछड़ों के, कर्पूरी जी का जो आरक्षण था उसको भी खत्म करने की कोशिश कर रहे थे । जबतक जनता पर विश्वास नहीं होगा और लोकतंत्र में संख्या नहीं होगी, तबतक वेल में आकर हल्ला करने से क्या फायदा है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती बिनिता मेहता ।

श्रीमती बिनिता मेहता : महोदय, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार केशरी श्री कृष्ण सिंह जी की जन्मस्थली नवादा जिला के खनवा को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाय । साथ ही, भारत सरकार से बिहार केशरी श्रीकृष्ण बाबू को भारतरत्न देने के लिए बिहार सरकार से अनुशंसा की मांग करती हूं ।

श्री प्रमोद कुमार सिंह : महोदय, औरंगाबाद जिलांतर्गत रफीगंज नगर पंचायत में धावा नदी के किनारे डाकबंगला के पास स्थित 2 एकड़ भूमि जिसका खाता नं0–212, प्लॉट नं0–967, 968, मौजा–चकावॉ महमूद है, पर नगरवासियों के स्वास्थ्यवर्द्धन हेतु आधुनिक सुविधायुक्त पार्क का निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री उदय कुमार सिंह : महोदय, गयाजी जिलांतर्गत अनुमंडलीय अस्पताल, शेरघाटी में अल्ट्रासाउण्ड चलाने हेतु टेक्नीशियन पद रिक्त है । गंभीर मरीजों के लिए डायलिसिस सेंटर एवं आई0सी0यू0 बेड की भी अति आवश्यकता है ।

अतः मैं सरकार से जनहित में अनुमंडलीय अस्पताल शेरघाटी में अल्ट्रासाउण्ड टेक्नीशियन, डायलिसिस सेंटर एवं आई0सी0यू0 बेड की व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग करता हूं ।

श्रीमती सोनम कुमारी : महोदय, बिहार के सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णियां जिलों के अपराध कर्मियों ने त्रिवेणीगंज में वर्ष 2006 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी की मौजूदगी में आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में आये ।

अतः सरकार से आत्मसमर्पणकारियों को उचित बास भूमि, पेंशन एवं अन्य सुविधाएं मुहैया करवाने की मांग करती हूं ।

टर्न–8 / पुलकित / 18.02.2026

श्री राज कुमार राय : माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत हसनपुर प्रखंड के ग्राम–मंगलगढ़ स्थित मंगलेश्वर महादेव स्थान तथा शासन ग्राम स्थित माता सती स्थान दोनों मंदिर प्राचीन काल से स्थापित है ।

अतः लोकहित में दोनों मंदिरों को धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कराने की मांग करता हूं ।

श्रीमती कविता देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोढ़ा एवं फलका प्रखंड में एक भी शवदाह गृह नहीं है, जिससे आमजनों को अंतिम संस्कार के समय अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

अतः सरकार से मांग करती हूं कि दोनों प्रखंडों के प्रत्येक पंचायत में शवदाह गृह निर्माण सुनिश्चित कराया जाए ।

श्रीमती निशा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला के प्राणपुर विधान सभा क्षेत्र में लगातार भीषण आगलगी को देखते हुए, हर छः पंचायत के मध्य एक बड़े दमकल तथा अग्निशमन कर्मियों की पर्याप्त नियुक्ति की मांग मैं सरकार से करती हूं ।

श्री रजनीश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला अंतर्गत राजकीयकृत मध्य विद्यालय, बीहट में कक्षा 6 से 8 में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी एवं संस्कृत के शिक्षक नहीं हैं । जबकि जिले के कई विद्यालयों में शिक्षक–छात्र अनुपात से अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं ।

अतः उक्त विद्यालय में शिक्षकों का शीघ्र पदस्थापन करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिलाधिकारी, गोपालगंज द्वारा गठित संयुक्त जांच टीम की रिपोर्ट और कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य प्रमंडल गोपालगंज–2 के

फिजीबिलिटी प्रतिवेदन के आधार पर गोपालगंज के मांझा थाना के पास सारण मुख्य नहर बिंदु दूरी 125.40 (38.23 किलोमीटर) पर पुराने पुल के समानांतर नए उच्चस्तरीय पुल निर्माण की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत नारायणपुर प्रखंड के शहजादपुर एवं बैकटपुर दूधैला पंचायत के लोगों को 75 किलोमीटर भागलपुर–विक्रमशिला सेतु होते हुए प्रखंड कार्यालय जाना पड़ता है ।

अतः सरकार से उक्त दोनों पंचायतों को नाथनगर प्रखंड में जोड़ने की मांग करता हूं ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के मेरे विधानसभा में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के समय पीड़ितों को बांधों पर आश्रय लेना पड़ता है। इसलिए केसरिया प्रखंड के ढेकहा, संग्रामपुर प्रखंड के भवानीपुर, मलाही टोला तथा डुमरिया में स्थायी बाढ़ राहत केंद्र तथा रैन बसेरा बनाने की मांग सरकार से करती हूं ।

प्रो0 नागेन्द्र राउत : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत चोरौत प्रखंड के ग्राम–बलसा में मुसहरी टोल के निकट धौस नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं ।

श्री शुभानंद मुकेश : अध्यक्ष महोदय, कहलगांव में एन0टी0पी0सी0 के भारी वाहनों और एन0एच0–80 पर अत्यधिक दबाव के कारण 24 घंटे जाम की स्थिति बनी रहती है।

अतः विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात के सुचारु संचालन हेतु कहलगांव में एक समर्पित ट्रैफिक थाना की स्थापना करने के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री विनय बिहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज विभाग अंतर्गत ग्राम कचहरी सचिव, कचहरी के सफल संचालन में अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करते आ रहे हैं । प्राप्त मानदेय 9000/– बहुत ही कम राशि है । मैं ग्राम कचहरी सचिव के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी हो एवं सेवा स्थायी की जाए, सदन से इसकी मांग करता हूं ।

श्री रोमित कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, अतरी के गहलौर, जेठियन और तपोवन में इको–टूरिज्म की अपरा संभावनाएं हैं । यहां रॉक–क्लाइम्बिंग, पैरा–ग्लाइडिंग एवं थर्मल वाटॅर टूरिज्म हेतु ढांचा विकसित किया जाए । सरकार इन ऐतिहासिक स्थलों को 'एकीकृत इको–सर्किट' बनाकर स्थानीय रोजगार हेतु ठोस योजना अविलंब लागू करने की कृपा करें ।

श्रीमती श्वेता गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिवहर को पूर्वी चम्पारण से जोड़ने वाली पिपराही–जिहुली पथ वर्षों से जर्जर अवस्था में है । जिससे आमजन को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा बरसात में स्थिति और गंभीर हो

जाती है । सरकार से इस महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग के शीघ्र मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु कार्रवाई की मांग करती हूं ।

श्रीमती संगीता कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार के कैमूर जिला अन्तर्गत मोहनियाँ और कुदरा अंचल में खरबार जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है । जबकि बिहार के और जिलों में प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है ।

अतः मैं मोहनियाँ एवं कुदरा में खरबार जाति का प्रमाण पत्र की मांग करती हूँ ।

श्रीमती गायत्री देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत भेड़रहिया पंचायत के भगवतीपुर गांव होकर अधवारा समूह की हरदी नदी नेपाल से आती है । नेपाल में दोनों किनारे तटबंध हैं लेकिन भारत में नहीं ।

अतः परिहार प्रखंड के भगवतीपुर में नदी के दोनों ओर तटबंध निर्माण की मांग सरकार से करती हूं ।

श्रीमती छोटी कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, छपरा शहर में भिखारी चौक से बस स्टैंड तक निर्माणाधीन डबल डेकर फ्लाईओवर विगत आठ वर्षों से अधूरा पड़ा है । इसके कारण प्रतिदिन भीषण जाम, धूल, प्रदूषण, दुर्घटनाएं एवं जल–जमाव की समस्या बनी रहती है । स्थानीय व्यापारियों का व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है और वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं ।

श्री मो0 सरवर आलम : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज के कोचाधामन प्रखंड की 24 पंचायतों में बड़ी दमकल गाड़ी न होने और जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी और जाम के कारण आगजनी में भारी क्षति होती है ।

अतः कोचाधामन थाना हेतु एक बड़ा अग्निशमन वाहन और डेरामारी पंचायत के धनपुरा ओ0पी0 में छोटी अग्निशमन वाहन की मांग करता हूं ।

श्री ललित नारायण मंडल : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिले के शाहकुण्ड प्रखंड के जर्जर अंचल सह प्रखंड कार्यालय का यथाशीघ्र पुनर्निर्माण की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं ।

श्री सुजीत कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला के अंधराठाढ़ी में झंझारपुर–लौकहा रेलखंड के कर्णपुर पंचायत, वार्ड संख्या–7 के समीप रेल पटरी नवीनीकरण से सड़क मार्ग अवरुद्ध है । दैनिक आवागमन में दुर्घटना की आशंका है ।

अतः यहां शीघ्र रेल ओवरब्रिज निर्माण आवश्यक है ।

श्रीमती संगीता देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बलरामपुर विधान सभा क्षेत्र के बिजली विभाग की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं । गर्मी के मौसम में बार–बार बिजली कटौती, फीडर खराबी एवं 11,000 वोल्ट जर्जर तारों से जनता अत्यधिक परेशान है।

अतः सभी आवश्यक मेंटेनेंस कार्य गर्मी शुरू होने से पूर्व पूर्ण कराने की मांग करती हूं ।

श्री भरत बिंद : माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला अंतर्गत भभुआ में अवस्थित हवाई अड्डे के विस्तारीकरण तथा जीर्णोद्धार की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं ।

श्री राकेश रंजन : अध्यक्ष महोदय, शाहपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत दोनों प्रखण्ड में कई हाई स्कूल है, जिनके पास अपना खेल मैदान है, लेकिन चहारदीवारी नहीं होने से कई खेल मैदानों पर अतिक्रमण है तथा शेष पर खतरा बना हुआ है ।

अतः खेल मैदानों को बचाने हेतु चहारदीवारी निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जाएंगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जाएंगी । अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जाएंगी ।

टर्न–9 / हेमन्त / 18.02.2026

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी, सतीश कुमार साह एवं अन्य छः सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी जी, अपनी सूचना को पढ़ें।

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय ध्यानाकर्षण की आपने स्वीकृति दी है।

''अध्यक्ष महोदय, बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भू–जल स्रोतों में आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन, नाइट्रेट, बैक्टीरियल प्रदूषण, लेड (शीशा) आदि की मौजूदगी की सूचना है। जिससे खतरनाक बीमारियां जैसे त्वाचा रोग, अस्थि फ्लोरोसिस, एनीमिया, ब्लू बेबी सिंड्रोम, पेट संबंधी बीमारी, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, कैंसर आदि तेजी से लोगों में फैल रहा है। इससे ग्रामीण एवं शहरी आमजन प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि सरकार के स्तर से नल–जल योजना, जल गुणवत्ता परीक्षण एवं शुद्धिकरण से पेयजल समस्या समाधान का प्रयास हो रहा है, जो नाकाफी है।

अतएव जल स्रोतों को प्रदूषण रहित करने के उद्देश्य से भू–जल स्रोतों का निरंतर वैज्ञानिक परीक्षण, जल शुद्धिकरण तकनीक विकसित करने, जल प्रदूषण नियंत्रण का उपाय करने और बच्चों, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण की विशेष योजनाएं लागू करने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, सात निश्चय योजना अन्तर्गत बिहार राज्य के सभी परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की शुरूआत वर्ष 2016 में की गयी थी। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में हर घर नल, हर घर शुद्ध जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य नगर विकास एवं आवास विभाग को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल, हर घर शुद्ध जल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं पंचायती राज विभाग को दी गयी थी।

महोदय, उक्त निर्णय के आलोक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा राज्य के 56,447 वार्डों में 50,081 योजना एवं पंचायती राज विभाग द्वारा 58,003 ग्रामीण वार्डों में 70,157 योजनाओं का निर्माण कार्य कराया गया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा निविदा के माध्यम से चयनित संवेदकों द्वारा निर्माण कार्य एवं पाँच साल का रख–रखाव कार्य कराया जा रहा है। पंचायती राज विभाग द्वारा योजनाओं का निर्माण कार्य वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (डब्ल्यू0आई0एम0सी0) के द्वारा कराया गया एवं वर्ष 2023 में पंचायती राज विभाग की जलापूर्ति योजनाओं के बेहतर प्रबंधन एवं रख–रखाव हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित किया गया।

अध्यक्ष महोदय, उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य के 14 जिलों के भू–जल स्रोतों में आर्सेनिक, 11 जिलों में फ्लोराइड तथा 12 जिलों में आयरन पाया गया है। आर्सेनिक मुख्यतः गंगा नदी के किनारे के जिलों में, फ्लोराइड मुख्यतः दक्षिण बिहार के जिलों में तथा आयरन उत्तर पूर्व के जिलों के भूगर्भीय जल में पाया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, भूगर्भीय जल में संदूषण की समस्या के मद्देनजर गुणवत्ता प्रभावित जिलों में 'हर घर नल का जल' योजना के तहत एडजोरबसन तकनीक (Adsorption Technic) आधारित शुद्धिकरण संयंत्र युक्त जलापूर्ति योजनाएं अधिष्ठापित की गयी है। साथ ही, बैक्टीरियल संदूषण से बचाव के लिए विभाग द्वारा स्थापित सभी जलापूर्ति योजनाओं में क्लोरिनेशन यूनिट का अधिष्ठापन किया गया है। आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में कुल 4709 वार्डों के लक्ष्य के विरुद्ध सभी 4709 वार्डों में आर्सेनिक शोधन संयंत्र के साथ जलापूर्ति योजनाएं स्थापित की गयी हैं, फ्लोराइड प्रभावित 3789 वार्डों के लक्ष्य के विरुद्ध 3784 वार्डों में फ्लोराइड शोधन संयंत्र के साथ जलापूर्ति योजनाएं स्थापित की गयी हैं तथा आयरन प्रभावित 21709 वार्डों के लक्ष्य के विरुद्ध 21471 वार्डों में आयरन शोधन संयंत्रों के साथ जलापूर्ति योजनाएं स्थापित की गयी हैं एवं शुद्ध जलापूर्ति की जा रही है। शेष योजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति में है जिसे मई, 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में अधिष्ठापित सभी योजनाओं का संचालन एवं रख–रखाव संवेदकों के द्वारा निर्धारित मापदंड के तहत किया जा रहा है।

महोदय, इन योजनाओं से ग्रामीण उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जा रही जल के नमूनों की जांच विभाग द्वारा राज्य/जिला/अवर प्रमण्डल स्तर पर स्थापित प्रयोगशालाओं के द्वारा विभागीय प्रोटोकॉल के अनुरूप की जाती है। विभाग द्वारा राज्य स्तर पर NABL प्रत्यायित 1 राज्य स्तरीय जल जांच प्रयोगशाला, जिला स्तर पर NABL प्रत्यायित 38 जिला स्तरीय जल जांच प्रयोगशाला तथा 75 अवर प्रमण्डलीय जल जांच प्रयोगशाला स्थापित हैं। महोदय, पंचायत स्तर पर फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं से आपूर्ति की जा रही जल नमूनों की जांच की जाती है। पंचायत स्तर पर जल नमूनों में बैक्टीरियल जांच H_2S Vials से भी की जा रही है। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज (NABL) सुनिश्चित करता है कि लैब अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों (ISO 17025) का पालन करती है, जिससे रिपोर्ट 100 प्रतिशत सटीक और विश्वसनीय होती है।

महोदय, जलापूर्ति योजनाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान हेतु सुदृढ़ केन्द्रीय शिकायत निवारण व्यवस्था (CGRC) कार्यरत है। जिसको पूरे राज्य में टोल–फ्री नंबर के द्वारा, व्हाट्सएप नंबर के द्वारा, ई–मेल के द्वारा तथा वेबसाईट के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। दर्ज शिकायतों की सूचना संबंधित संवेदक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता को SMS के माध्यम से स्वतः अग्रसारित हो जाता है। शिकायतों का समाधान तत्परता से किया जाता है तथा शिकायत कर्ता के संतुष्टि के पश्चात् ही शिकायत को बन्द किया जाता है। इस प्रक्रिया से शिकायत निवारण में उत्तरोत्तर प्रगति सर्वविदित है। अबतक CGRC के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में 1,11,682 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें 1,08,832 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है तथा पंचायती राज विभाग के योजनाओं का सुदृढ़ीकरण का कार्य जारी है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग योजनाओं का सुदृढ़ीकरण एवं प्रभावी अनुरक्षण हेतु कृत संकल्पित है।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में राज्य के भूगर्भीय जल में मुख्यतः आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं आयरन की समस्या ही पाई जाती है। अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं में नाइट्रेट (Nitrate) एवं लेड (Lead) कहीं भी मानक से अधिक नहीं पाई गयी है। कतिपय चापाकलों के जल में नाइट्रेट की मात्रा मानक से अधिक पाई गयी है, उन्हें पेयजल के रूप में उपयोग नहीं करने हेतु प्रचारित किया गया है एवं चापाकल के Spout को लाल रंग से रंगा जाता है।

महोदय, माननीय सदस्यों को भू–जल स्रोतों के निरंतर वैज्ञानिक परीक्षण संबंधित चिंता के आलोक में कहना है कि राज्य स्तरीय जल जांच प्रयोगशाला में भारी धातु (जैसे आर्सेनिक, निकेल, कैडमियम, लेड इत्यादि) के जांच हेतु तकनीकी रूप से आधुनिक मशीन यथा–Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES) एवं Atomic

Absorption Spectrophotometer (AAS) का अधिष्ठापन किया गया है, जिससे जल में पाए जा रहे संदूषण की जांच की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, उल्लेखनीय है कि भूगर्भीय जल में आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं आयरन संदूषण भूजनित (Geogenic) है। भूगर्भीय जल में रसायनिक संदूषण मुख्यतः भू–गर्भ के चट्टानों में रसायन की उपलब्धता के कारण होता है। मानव उपयोग हेतु भू–गर्भीय जल के अत्यधिक दोहन के कारण जल में रसायन की सांद्रता (Concentration) बढ़ जाती है। इससे बचाव के लिए भूगर्भीय जल के उपयोग के स्थान पर सतही जल आधारित योजनाओं का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जिसके तहत सतही जल आधारित 09 बहुग्रामीय जलापूर्ति योजनाएँ यथा– बिदुपुर बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना, कहलगाँव बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना, भागलपुर, मौजमपुर, भोजपुर, रजौली, नवादा,..

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, ठीक है, आपने सारी बातों को रखा है।

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी विस्तार से जवाब दिए हैं। मुझे सरकार की मंशा में और माननीय मंत्री की सोच में कहीं कोई शक नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन सवाल यह है कि इतने सारे खतरनाक तत्व, जो जल में प्राप्त हो रहे हैं और हम जल शुद्धिकरण, नल–जल से ही केवल जल शुद्धिकरण करके दे रहे हैं, लेकिन जल के आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोतों में ये जो तत्व पाए जा रहे हैं, जिससे खतरनाक असाध्य रोग हो रहा है। ठीक है, माननीय मंत्री जी ने कहा नल का जल को हम विशेष रूप से कर रहे हैं। लेकिन दो चीज के बारे में, माननीय मंत्री जी, मैं इस सदन को कहना चाहूंगा, एक शीशा (लेड) और एक नाइट्रेट, लेड और नाइट्रेट अभी तेजी से फैल रहा है, यह बाह्य वातावरण में भी फैल रहा है। जैसे दीवार में पेंटिंग है, हम लोग जो पाइपलाइन से नल लगाते हैं, उसमें जो छेद करते हैं या उसका तार बदलते हैं या आई0एस0ओ0 प्रमाणिक पाइप नहीं लगता है, ऐसे पाइप लंबी अवधि के बाद लेड छोड़ता है, जिसके कारण बच्चों में मस्तिष्क रोग, बच्चों का वृद्धि रुकना, गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक होता है। हम इसलिए इस प्रश्न को ध्यानाकर्षण के माध्यम से लाए कि हमको ध्यानाकर्षण देना है।

(क्रमशः)

टर्न–10 / संगीता / 18.02.2026

...क्रमशः...

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी : अध्यक्ष महोदय, जो इससे असाध्य रोग फैल रहे हैं, आपकी अनुमति हो तो हम सदन में पढ़ दें, पढ़ने से हम तो जागृति के लिए लाए हैं, जागरण के लिए लाए हैं और 12 करोड़ से अधिक आबादी है । हम नल का जल कितने लोगों को दे पा रहे हैं और गांवों में लोग तो नल का जल से अच्छा चापाकल से पी रहे हैं...

अध्यक्ष : सदन पटल पर रख दिया जाए ।

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी : जैसे आर्सेनिक से जो बीमारियां होती हैं, अगर सदन की अनुमति हो तो हम पढ़ देते हैं । आर्सेनिक से...

अध्यक्ष : सदन पटल पर रख दिया जाए ।

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी : पटल पर, लेकिन दो का पढ़ने दिया जाए । ये जो दो नया आया है जैसे–लेड, जिसे शीशा कहते हैं, जो आ रहा है, जिसका अभी वैज्ञानिक शोध और पानी के यांत्रिक स्रोतों में भी मिल रहा है । लेड से विशेषकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं का मस्तिष्क और तंत्रिका–तंत्र के विकास में बाधा, एनीमिया, किडनी रोग, हृदय रोग और ये सबसे ज्यादा गया में, पटना में, वैशाली में, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में फैल रहा है इसीलिए...

अध्यक्ष : आपका पूरक क्या है, पूछ लीजिए ।

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी : ये जो तत्व निकल रहे हैं नए, क्या इसको आधुनिक वैज्ञानिक शोध कराकर करना चाहते हैं ? दूसरा चीज, यह पर्यावरण से जुड़ा हुआ है क्योंकि इन तत्वों से कैंसर की बीमारी, खासकर मेरे प्रमंडल में, ये जो सीमांचल, कोसी और पूर्णिया है, फैल रहा है तो ये तीन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पी0एच0ई0डी0 और वन एवं पर्यावरण विभाग को एकीकृत करके क्या सरकार इस पर विशेष शोध करके सतही पानी और आंतरिक पानी और पर्यावरण पर कुछ अच्छा करने का मंत्रिमंडल का एक तीन सदस्यीय कमिटी बनाकर इस पर कुछ करने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, संक्षेप में बता दीजिए ।

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, राज्य जल स्तरीय प्रयोगशाला हमारे पूरे बिहार में 2 हजार है और जिला स्तरीय जल जांच प्रयोगशाला 300 है, अवर प्रमंडल स्तरीय जल जांच प्रयोगशाला ढ़ाई सौ है और हरेक चीज का हमलोग जांच करते हैं । वर्ष 2025–26 में जलस्रोतों की जांच की गई है, जिसका 1 लाख 14 हजार 675 है और माननीय सदस्य ने जो सदन में उठाया है, नाइट्रेट का अनुमान्य सीमा 45 मिलीग्राम प्रति लीटर है, इसकी अधिकता से बच्चों में ब्लू–बेबी रोग होता है । फ्लोराइड की अनुमान्य सीमा 1.0 मिलीग्राम प्रति लीटर है, इसकी अधिकता से अस्थि फ्लोराइसिस एवं दांतों का क्षय होता है । आर्सेनिक की अनुमान्य सीमा 0.01 मिलीग्राम...

अध्यक्ष : इसके समाधान के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : समाधान के लिए हमलोग जो जांच प्रयोगशाला में जांच कर रहे हैं और इसमें जहां भी अगर कोई भी कमियां पायी जाती है और जहां भी फ्लोराइड का या जो माननीय सदस्य ने लेड शीशा का जिक्र किया है, आयरन का जिक्र किया है, इसके लिए हमलोग जहां भी जांच प्रयोगशाला है, उसमें जांच करते हैं और जिस जिला में, जिसमें हमलोगों का 14 जिला आर्सेनिक प्रभावित है और 11 जिला फ्लोराइड प्रभावित है और आयरन प्रभावित 12 जिला

है । जहां भी है, इसके समाधान के लिए हमलोग वहां पर, हमारा जो इसको प्यूरिफाई के लिए जो मशीन लगा हुआ है, उसके द्वारा हमलोग इसको करके और जहां भी पानी में जो भी गुणवत्ता पायी जाती है, उसको हमलोग तुरंत दूर करने का काम करते हैं ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : मुरारी जी पूछ लीजिए ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य...

अध्यक्ष : उत्तर बड़ा है, प्रश्न भी बड़ा हो गया है इसमें ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारी हर जगह जांच प्रयोगशालाएं हैं, हर जिले में, कई जिलों में इन्होंने बताया भी है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो जांच प्रयोगशाला है, उसमें जांचकर्ता कितने हैं, पी0एच0ई0डी0 विभाग के द्वारा वहां जांचकर्ता रखे गए हैं कि नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : हम माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि एक बार ये हमारे जो बिहार राज्य में, पटना में और इनके जिला में भी है, एक बार ये जाकर खुद से देख लें, संतुष्ट हो जायेंगे तो मुझे लगता है कि आगे के लिए अच्छा रहेगा ।

अध्यक्ष : श्री तारकिशोर प्रसाद जी, अपनी सूचना को पढ़े ।

सर्वश्री तारकिशोर प्रसाद, मंजीत कुमार सिंह एवं अन्य पांच सभासदों से प्राप्त <u>ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) की ओर से वक्तव्य ।</u>

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों को पूर्व से देय नियत मासिक भत्ता में 01 जुलाई, 2025 के प्रभाव से डेढ़ गुना वृद्धि की गयी है । जबकि उस अनुपात में स्थानीय नगर निकाय के वार्ड पार्षद का नियत भत्ता क्रमशः नगर निगम के वार्ड पार्षद को 2500/– रुपये, नगर परिषद के वार्ड पार्षद को 1500/– रुपये तथा नगर पंचायत के वार्ड पार्षद को 1000/– रुपये वित्तीय वर्ष 2015–16 से यथावत है, जो न्यायोचित नहीं है । इस प्रकार इस अंतराल में महंगाई काफी बढ़ी है ।

अतएव निर्वाचित वार्ड पार्षदों को भी पंचायती राज के आधार पर नियम भत्ता में सम्मानजनक वृद्धि करने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के ध्यानाकर्षण के संबंध में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–19 में मुख्य पार्षद सशक्त स्थायी समिति के अन्य सदस्य तथा अन्य पार्षद राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा विहित पारिश्रमिक एवं भत्ते प्राप्त कर सकेंगे, का उल्लेख है । विभागीय संकल्प संख्या–2523, दिनांक–19.05.2015 द्वारा राज्य के तीनों श्रेणियों के नगर निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए नित्य मासिक भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है । राज्य के तीनों श्रेणियों के नगर निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए भी मासिक भत्ता वृद्धि का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सरकार काफी संवेदनशील है । विगत 10 वर्ष का एक अंतराल काफी बड़ा अंतराल होता है एवं इस बीच में महंगाई एवं मुद्रास्फीति भी बढ़ी है एवं नगर के जितने भी निगम पार्षद हैं, उनको भी पूरा दिन पंचायती राज की तर्ज पर उन्हें भी पूरा दिन अपने क्षेत्र के नागरिकों की सेवा के लिए काफी दौड़–धूप करना पड़ता है । उन्हें बार–बार निगम कार्यालय एवं स्थानीय नगर निकाय के कार्यालयों में भी जाना पड़ता है । हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे कि जिस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था में 2025 में यह वृद्धि की गई है, उस आधार पर स्थानीय नगर निकाय की जो जिम्मेदारी बढ़ी है और खास करके सरकार का भी है कि अधिक से अधिक हम नगरीय क्षेत्र को विस्तारित करें, जिससे कि बिहार तेजी से आगे बढ़ सके तो उस आलोक में सरकार से निश्चित तौर पर हम आग्रह करेंगे कि उनके नियत भत्ता में, कोई नियत भत्ता है, कोई वेतनमान या इस प्रकार के अन्य ऐसे खर्च नहीं हैं जो काफी बजटीय प्रावधान को प्रभावित करता हो । अतः सरकार से आग्रह और निवेदन है कि निश्चित तौर पर विचार करके इनका जो नियत भत्ता है, उसमें वृद्धि करना चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य काफी वरिष्ठ हैं और माननीय सदस्य को इस राज्य में वित्तमंत्री रहने का भी अवसर प्राप्त हुआ है और नगर विकास मंत्री के रूप में भी कार्य करने का अवसर मिला है । जब माननीय सदस्य वित्तमंत्री और नगर विकास मंत्री थे तो उस समय उनकी चिन्ता नहीं थी लेकिन अब इनकी चिन्ता बढ़ी है, इनकी चिन्ता से सरकार भी चिन्तित है महोदय और माननीय सदस्य की जो चिन्ता है, इस पर जरूर सरकार विचार करेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, सुश्री मैथिली ठाकुर ।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : पूछ लीजिए ।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को, माननीय मंत्री जी ग्रामीण विकास विभाग को लगातार देख रहे हैं और ग्रामीण विकास विभाग के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके...

अध्यक्ष : आप भी नगर विकास में रहे हैं ।

श्री जिवेश कुमार : और ग्रामीण विकास के जनप्रतिनिधियों के प्रति इन्होंने बड़ा दिल दिखाया है और वर्ष 2025 में चुनाव के पहले उनके मानदेय को बढ़ा करके डेढ़ गुना किया गया और नगर विकास में मैं उस समय मंत्री था, पूरी तैयारी नगर विकास में भी की गई थी, वह फाईल भी तैयारी की दिशा में थी, चूंकि कैबिनेट का नोट जब तक नहीं आ जाता है तब तक उसको कहीं बताना उचित नहीं होता है ।

...क्रमशः...

टर्न–11 / यानपति / 18.02.2026

(क्रमशः)

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, तैयारी पूरी थी, जो तैयारी की गई थी, हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि थोड़ा दिल बड़ा दिखाएं और दोनों आपके ही हैं, नगर भी आपका है, यह तो अलग बात, सरकार के मंत्री हैं, आप तो संकटमोचन हैं और सचेतक भी हैं हमलोगों के ।

अध्यक्ष : सरकार ने कहा है विचार करेगी ।

श्री जिवेश कुमार : इसलिए इस पर विचार करें यही तो मैं आग्रह कर रहा हूं ।

सुश्री मैथिली ठाकुर, श्री आनन्द मिश्र एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त <u>ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (स्वास्थ्य विभाग) की ओर से वक्तव्य।</u>

सुश्री मैथिली ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद । आपने मुझे ध्यानाकर्षण का यह प्रश्न पढ़ने का मौका दिया ।

बिहार के विभिन्न जिलों खासकर उत्तर बिहार यथा अलीनगर विधान सभा क्षेत्र में अर्जुन वृक्ष (औषधीय वृक्ष) की बहुतायत संख्या एक बड़ी आर्थिक और आयुर्वेदिक संपत्ति है, जिसका सही तरीके से उपयोग न केवल रोजगार बल्कि बिहार को हर्बल मेडिसिन का केन्द्र भी बना सकता है । अर्जुन वृक्ष की छाल में बीटा साइटोस्टेरॉल, अर्जुनिक अम्ल तथा फ्रीडेलीन की मात्रा होने के कारण छाल से बने अर्जुन घृत, क्षयकाश तथा अर्जुनरिष्ठ दवा के उपयोग से हृदय रोग, क्षय रोग, सुगर जैसी गंभीर बीमारी में मरीजों को लाभ हो रहा है, जिस पर शोधकर्ता भी सहमत हैं ।

बिहार में अधिकतर छाल कच्चे माल के रूप में दूसरे राज्यों में भेजने के बजाय जिला स्तर पर छोटे प्लांट लगाकर छाल से बनी टैबलेट, काढ़ा

और हार्ट–केयर सप्लीमेंट्स की ब्रांडिंग सरकार के पोर्टल के माध्यम से मेक इन बिहार के तहत की जानी चाहिए ।

अतः उत्तर बिहार में अर्जुन छाल में रक्षित घटक के आधार पर योजना के तहत कच्चे माल का एकत्रीकरण, प्रोसेसिंग यूनिट तथा सरकारी सहायता एवं रजिस्ट्रेशन के माध्यम से खेती कराकर होम्योपैथी एवं आयुर्वेद पद्धति के तहत हर्बल मेडिसिन का केन्द्र बनाने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराती हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, समय चाहिए ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अख्तरूल ईमान साहब जो ए0आई0एम0आई0एम0 के नेता हैं उन्होंने पसमांदा मुस्लिम समाज के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की है और मैं अनुरोध करता हूं कि सदन की कार्यवाही से उसे निकाल दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है । हटा दिया जायेगा ।

<u>शेष शून्यकाल की सूचना</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बब्लू कुमार जी, आपका शब्द 70 है, सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि 50 शब्दों में शून्यकाल लिये जाते हैं, आगे से कृपया ध्यान रखेंगे।

श्री बबलू कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान अपने विधान सभा के भदास उत्तरी गांव की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जहां थाना नहीं होने से लोगों को 18 कि0मी0 दूर गंगौर थाना जाना पड़ता है । भदास उत्तरी में थाना स्थापित होने से धुसमुरी बिशनपुर, कासिमपुर, कोठिया सहित आसपास की बड़ी आबादी को सुरक्षा सुविधा मिलेगी । मैं सरकार से वहां बने थाना भवन में थाना संचालन के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की मांग करता हूं ।

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला अंतर्गत कदवा प्रखंड के कुम्हरी एवं भेलागंज में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हैं, किंतु भवन नहीं होने के कारण स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन उनके स्वीकृत स्थल पर प्रारंभ नहीं हो सका है ।

अतः स्वीकृत स्वास्थ्य केंद्रों के भवन का निर्माण कराया जाय ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, छपरा का ऐतिहासिक भूमिगत खनुआ नाला का निर्माण कार्य नगर–निगम क्षेत्र के अंतर्गत बुडको के द्वारा गुणवत्तापूर्ण एवं ससमय नहीं होने के कारण हर साल बरसात में शहरवासियों को जल–जमाव और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । सरकार इसकी जांच कराते हुए निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करावें ।

श्री विमल राजवंशी : अध्यक्ष महोदय, रजौली थाना अंतर्गत मैसकौर प्रखंड में पेयजल संकट की गंभीर समस्या है । अधूरी टंकियां व खराब पाइपलाइन से शुद्ध पानी नहीं मिल रहा । जिम्मेदार एजेंसी पर कार्रवाई और पेयजल की समस्या की निराकरण की समय–सीमा तय कर समस्या का समाधान सरकार से मांग करता हूं ।

श्री राजेश कुमार मंडल उर्फ ईश्वर मंडल : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सदर प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण गरीब एवं लाचार विद्यार्थियों को अध्ययन में कठिनाइयां हो रही हैं जिससे आर्थिक अभावग्रस्त विद्यार्थी बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं ।

सदर प्रखंड के अतिहर पंचायत में एक डिग्री कॉलेज खोलने की मांग करता हूं ।

श्री गुलाम सरवर : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिलान्तर्गत बायसी प्रखंड के एन0एच0–31 चरेयाघुसकीटोला से मड़वा जाने वाली सड़क को संवेदक द्वारा निर्माण हेतु तोड़ फोर कर छोड़ दिया गया है । लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है ।

उक्त सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए ससमय निर्माण की मांग करता हूं ।

श्रीमती देवंती यादव : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला के नरपतगंज विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पंचायत फुलकाहा के लोगों को लगभग 32 कि0मी0 की दूरी तय कर नरपतगंज प्रखंड कार्यालय जाना पड़ता है । अतः जनहित में फुलकाहा को प्रखंड का दर्जा देने हेतु मैं सरकार से मांग करती हूं ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिलान्तर्गत प्रखंड रामगढ़ में अवस्थित रामदयाल सिंह यादव स्टेडियम महुअर के कैम्पस में समाज सेवी स्व0 रामदयाल सिंह यादव की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की सरकार से मांग करता हूं।

श्री बीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के विस्तारीकरण, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य के लिए दरभंगा जिला अंतर्गत कुल 16 प्रखंडों एवं मधुबनी के 20 प्रखंडों को लिया गया है । समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर, वारिसनगर, खानपुर, शिवाजीनगर, रोसड़ा एवं सिंघिया को भी इस योजना में शामिल करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिलान्तर्गत प्रखंड–बगहा–2 में वाल्मीकिनगर टंकी बाजार, रामपुर चेक पोस्ट, हरनाटाड़ बाजार, सेमरा बाजार के पास, बांसी के प्रमुख चौक–चौराहे, पर हाई–मास्ट लाईट नहीं रहने से अंधेरे में चोरी–चकारी का भय बना रहता है, सरकार से चौक–चौराहे पर हाई–मास्ट लाईट लगाने की मांग करता हूं ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, राज्य में वित्त रहित सभी अनुदानित विद्यालय एवं महाविद्यालय में कार्यरत कर्मियों को नियमित वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है । अधिगृहित कर सभी कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों को नियमित वेतनमान देने की सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं ।

श्री कलाधर मंडल : अध्यक्ष महोदय, राज्य की 80 प्रतिशत ग्रामीण आबादी अग्नि आपदा से निजात हेतु सरकार द्वारा जिला मुख्यालय से दूरस्थ क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराये गए छोटे दमकलों से आपदा पर ससमय नियंत्रण नहीं होने से भारी जान–माल की हानि होती है ।

प्रखंड स्तर पर जनहित में छोटे एवं बड़े दमकलों की शीघ्र व्यवस्था कराने की मांग करता हूं ।

टर्न–12 / मुकुल / 18.02.2026

श्री रामचन्द्र प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में यू0जी0सी0 के मापदण्ड के अनुरूप नियुक्त एवं कई वर्षों से कार्यरत अतिथि सहायक प्राध्यापकों की सेवा 65 वर्षों तक सुनिश्चित करने की, सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : श्री सदीप सौरभ ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री रणविजय साहू ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री मुरारी पासवान ।

श्री मुरारी पासवान : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगांव प्रखण्ड के पंचायत–ओरियप के ग्राम–कासड़ी मध्य विद्यालय में वर्ग 08 तक 780 छात्र / छात्राओं के लिए मात्र 06 कमरा है जिसमें 02 कमरा जर्जर है जिससे पठन–पाठन में कठिनाई को देखते हुए अतिरिक्त 06 कमरा का निर्माण हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री आनन्द मिश्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, बक्सर नगर परिषद् में होल्डिंग टैक्स घोटाले की जांच रिपोर्ट आने एवं कमिश्नर, पटना द्वारा जिलाधिकारी को कार्रवाई हेतु निर्देशित करने के बावजूद दोषी कर्मचारियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है । मैं सरकार से दोषियों पर अविलंब कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की मांग करता हूं ।

मोहम्मद मुर्शिद आलम : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के प्लस–2 उच्च विद्यालयों में वर्ष–2018 में 4257 तथा वर्ष 2023 में 1113 पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गयी थी, उक्त सभी शिक्षकों को मार्च, 2024 में हटा दिया गया है जबकि उक्त शिक्षक पुनर्नियुक्ति की प्रत्याशा में आज तक किसी नौकरी

में नहीं गये हैं । अतः उक्त शिक्षकों को पुनः बहाल करने की मांग करता हूं।

श्री मिथुन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत नाथनगर विधान सभा क्षेत्र के नाथ नगर प्रखण्ड अंतर्गत गोराचक्की पंचायत स्थित किशनपुर चौक के नजदीक बाईपास हाईवे पार करने में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । अतः किशनपुर चौक के समीप अंडर बाईपास का निर्माण कराने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री नागेन्द्र चन्द्रवंशी : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला अंतर्गत 211–नोखा विधान सभा के प्रखंड राजपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक पक्की सड़क नहीं रहने के कारण आने–जाने में कठिनाई होती है । नोखा राजपुर मुख्य पथ से मध्य ग्रामीण बैंक के पास से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक सड़क बनवाने की मांग करता हूं ।

श्री पप्पु कुमार वर्मा : अध्यक्ष महोदय, अरवल जिला के कुर्था विधानसभा अंतर्गत कई माध्यमिक तथा उच्च विद्यालयों में अपना भवन नहीं है और अगर है भी तो जर्जर स्थिति में है तथा शिक्षकों का अभाव है । अतः इन विद्यालयों में भवन तथा शिक्षकों की उपलब्धता की मांग करता हूं ।

श्री नंद किशोर राम : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चंपारण जिलान्तर्गत रामनगर प्रखंड के गोबर्धना में सोमेश्वर धाम पर्यटन स्थल है । यहां सुंदर वन क्षेत्र एवं पहाड़ी है, नवरात्र में हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं । अतः इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री राम सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, बगहा विधान सभा अंतर्गत एन0एच0–727 छोटकीपट्टी से प्रसा, देउरवा, नड्डा होते हुए कपरधिका आर0सी0डी0 रोड तक सड़क को चौड़ीकरण के साथ मजबूतीकरण कराने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्रीमती ज्योति देवी : अध्यक्ष महोदय, गयाजी जिला अन्तर्गत प्रखण्ड–बोधगया के पंचायतनामा में चेरकी–शेरघाटी मुख्य सड़क से कजरैली तक, वायरलेस राजाहरि तक, भुसिया सरफराजगंज कॉलेज तक, सड़क का निर्माण हुआ है, जिसमें गुणवत्ता की घोर अनदेखी की गयी है । समुचित जांच कर अभियंता एवं संवेदक पर कार्रवाई हेतु सदन से मांग करती हूं ।

अध्यक्ष : श्री अजय कुमार ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री शंकर प्रसाद ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री अरूण सिंह ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत रीगा अंचल के भवदेपुर गुमती से अम्बेडकर चौक होते हुए रमनगरा शंकर चौक तक की ग्रामीण सड़क को 5.5 मीटर (साढ़े पांच मीटर) चौड़ी नाला सहित सड़क का निर्माण कराने हेतु सरकार प्राथमिकता से कार्रवाई करे ।

अध्यक्ष : श्री महेश पासवान ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया सहित प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो भूमिगत रहकर स्वतंत्रता आंदोलन में शरीक हुए उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा एवं पेंशन देने तथा पेंशन प्राप्त कर रहे स्वतंत्रता सेनानी को गृह मंत्रालय से पहचान पत्र देने की मांग मैं सरकार से करता हूं ।

अध्यक्ष : श्रीमती अनीता ।

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

श्री पुरन लाल टुडू : अध्यक्ष महोदय, बांका जिला, कटोरिया विधानसभा अन्तर्गत बौंसी प्रखंड में 1967 में चांदन जलाशय के निर्माण के समय रोशनियां ग्राम के आदिवासियों को विस्थापित कर गहराजोर ग्राम में बसाया गया था । आज तक जमीन पर मालिकाना हक नहीं मिला है, सरकार से विस्थापित आदिवासी परिवार को जमीन पर मालिकाना हक दिलाने की मांग करता हूं।

श्री कुमार प्रणय : अध्यक्ष महोदय, मुंगेर विधान सभा अंतर्गत सदर प्रखंड के बेकापुर स्थित रानी सरस्वती सनातन धर्म संस्कृत उच्च विद्यालय, जो 100 वर्ष पुराना है, का विद्यालय भवन काफी जर्जर है, जिससे कभी भी दुर्घटना की स्थिति बन सकती है । अतः उक्त विद्यालय का जीर्णोद्धार कराने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं।

अध्यक्ष : श्री उपेन्द्र प्रसाद ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–13 / सुरज / 18.02.2026

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, आज ग्रामीण कार्य विभाग के अनुदान की मांग पर वाद–विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा :–

भारतीय जनता पार्टी	– 66 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	– 63 मिनट
राष्ट्रीय जनता दल	– 18 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)	– 14 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	– 04 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	– 04 मिनट
ए॰आई॰एम॰आई॰एम॰	– 04 मिनट
राष्ट्रीय लोक मोर्चा	– 03 मिनट
सी॰पी॰आई॰ (एम॰एल॰)(एल॰)	– 01 मिनट
सी॰पी॰आई॰ (एम॰)	– 01 मिनट
बहुजन समाजवादी पार्टी	– 01 मिनट
इंडियन इंक्लूसिव पार्टी	– 01 मिनट

.....

कुल – 180 मिनट

.....

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, मैं एक सूचना पढ़ूंगा...

अध्यक्ष : वित्तीय कार्य हो जाने दीजिये। माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 11312,17,99,000 / – (ग्यारह हजार तीन सौ बारह करोड़ सत्रह लाख निन्यानवे हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री मो0 कमरूल होदा, श्री अखतरूल ईमान एवं श्री सतीश कुमार सिंह यादव से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये सभी व्यापक हैं, जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार–विमर्श कर सकते हैं। माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार का प्रस्ताव प्रथम है।

अतएव, माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री राहुल कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत 20–21 वर्षों के सरकार के बाद आज भी दलित टोले, महादलित टोले तथा अन्य टोले सड़क से विहीन हैं । हम जानते हैं कि ग्रामीण सड़कें किसी भी जगह के विकास के लिये मूल आधार होता है लेकिन आज भी सड़कें जुड़ी नहीं है । सड़कों की स्थिति खराब है । इनके कार्य प्रमंडल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं । साथ ही साथ बिहार में इस वर्ष धान का अत्याधिक प्रोडक्शन हुआ है उसके बावजूद जो सरकार का रवैया है धान अधिप्राप्ति को लेकर इसके लिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''इस शीर्षक की मांग 10/– रूपये से घटायी जाय।''

अध्यक्ष : श्री अमरेन्द्र कुमार ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, एक सूचना है । बिहार सरकार के माननीय मंत्री ने बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों पर जो टिप्पणी की है कि बिहार के सभी विधान सभा सदस्य शराब पीते हैं, यह माननीय सदस्यों के प्रति अपमान भरा शब्द है । बिना किसी ऑथेंसिटी के, बिना किसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के एक जिम्मेवार मंत्री के द्वारा इस तरह का बयान दिया जाना, बहुत खेदजनक है । इसलिये मैं मांग करता हूं कि सरकार उस माननीय मंत्री को पद से बाहर करे ।

अध्यक्ष : श्री अमरेन्द्र कुमार ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात उठायी है सही बात है कि ये किसी भी नागरिक के द्वारा माननीय सदस्यों की बात तो छोड़ दीजिये । कोई अगर सरकार के, जो सरकार में शामिल हैं या इस सदन के सदस्य हैं, उनके द्वारा यह कहा जाए कि सदन के सभी सदस्य शराब पीते हैं ऐसा तो यह सदन कल्पना भी नहीं कर सकता है । क्योंकि महोदय यह सदन साक्षी है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में शराबबंदी की नीति अपनायी गयी है और इस सदन के सभी दल के माननीय सदस्यों ने एक स्वर से न सिर्फ उस विधेयक या कानून का समर्थन किया था बल्कि आपको भी स्मरण होगा कि सभी माननीय सदस्यों ने अपने सीट पर खड़े होकर, सबने एक तरह से प्रतिज्ञान किया था कि हमलोग तो खुद भी नहीं पीयेंगे और दूसरों को भी नहीं पीने के लिये प्रेरित करेंगे । महोदय, यह तो इस सदन के कार्यवाही में अंकित है इसलिये सरकार कभी नहीं मानती है कि किसी भी जिम्मेदार नागरिक को

और माननीय सदस्य या मंत्री हैं ऐसा बिल्कुल ही शोभनीय नहीं है । पता नहीं किसने कहा है, हमलोगों के संज्ञान में नहीं है महोदय ।

अध्यक्ष : श्री अमरेन्द्र कुमार ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय...

अध्यक्ष : बात आ गयी है, अब क्या बात है ?

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, पूरे देश के चैनलों में यह प्राथमिकता से दिखायी जा रही है कि बिहार सरकार के माननीय मंत्री ने कहा है कि सदन के सभी चाहे वह मंत्री हों, चाहे विधायक हों ये शराब पीते हैं, जिनका ब्लड टेस्ट करा दिया जाए तो सारे के सारे विधायक की शराब पीने की पुष्टि हो जायेगी । मैं चाहता हूं कि महोदय से कि अगर इस तरह की बात इस सदन के माननीय सदस्यों के प्रति, अगर इस तरह के भाषा का प्रयोग किया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि यह निंदनीय है...

अध्यक्ष : सरकार आपकी भावना से सहमत है ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, इसलिये हम आग्रह करेंगे कि इस तरह के भाषा बोलने वाले जो माननीय सदस्य हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है...

श्री कुमार सर्वजीत : एक सेकेंड महोदय । राजू जी ने कहा हमारे बारे में जो सदन और सदन के बाहर कह रहे हैं । इनको यह मालूम नहीं है कि जिस व्यक्ति की चर्चा मैंने सदन में किया, मूर्ति के लिये उनके राजनीति जीवन को ऊंचाई पर ले जाने के लिये मैं अपने परिवार के 10 लोगों को खोया । हमारे पिता की हत्या हुई । मेरे पिता के साथ 10 लोग मारे गये...

अध्यक्ष : श्री अमरेन्द्र कुमार ।

श्री कुमार सर्वजीत : स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को ऊंचाई तक ले जाने के लिसे...

अध्यक्ष : हो गयी बात । अब आप लोग डायवर्ट हो गए । श्री अमरेन्द्र कुमार ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये । कुमार सर्वजीत जी बैठ जाइये ।

श्री कुमार सर्वजीत : जिस व्यक्ति ने कुर्बानी दिया रामविलास पासवान जी के लिये । मेरे पिता की हत्या हो गयी...

अध्यक्ष : आ गयी बात, अब बैठिये ।

श्री कुमार सर्वजीत : उनको यह अपमानित करते हैं, ये दलितों को अपमानित करते हैं । जो कुर्बानी दिया है अपने परिवार की, उनको यह संस्कार सिखाते हैं...

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री राजू तिवारी : महोदय, एक मिनट । मैं इनको इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप इतने बड़े महापुरूष को...

अध्यक्ष : श्री अमरेन्द्र कुमार ।

श्री राजू तिवारी : श्रद्धेय पुरूष रामविलास पासवान जी को पहले अपमानित करते हैं बार–बार...

अध्यक्ष : सारी बात आ गयी है ।

श्री राजू तिवारी : और फिर आप रंग बदल लेते हैं । पहले माफी मांगें, मूर्ति की बात करते हैं मैं स्वागत करता हूं । लेकिन ये पहले माफी तो मांगें अपनी गलती पर...

अध्यक्ष : कृपया उन बातों को समाप्त करें ।

श्री राजू तिवारी : पश्चाताप ये नहीं करने वाले लोग हैं...

अध्यक्ष : श्री अमरेन्द्र कुमार ।

(व्यवधान)

कृपया आपस में चर्चा न करें । बिना आसन के अनुमति के आपस में चर्चा न करें ।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जाएं । कुमार सर्वजीत जी बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

हो गयी बात, बात आ गयी । कल भी आया है, परसों भी आया है ।

श्री अमरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आज ग्रामीण कार्य विभाग के लिये लाये गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन में कटौती प्रस्ताव पर पहली बार बोलने का अवसर मिला है । इसके लिये अपने नेता गरीबों के मसीहा आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बिहार के भविष्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय सचेतक कुमार सर्वजीत जी और गोह विधान सभा क्षेत्र के देवतुल्य सम्मानित जनता के साथ–साथ मैं माननीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग में भ्रष्टाचार और कार्य के प्रति लापरवाही नीचे से ऊपर तक है । निर्माण कार्य के गुणवत्ता की निगरानी करना विभागीय पदाधिकारियों की पहली जिम्मेदारी है जो ढंग से नहीं हो पा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, विभाग के इंजीनियर के यहां छापा पड़ता है तो उनके घर में लाखों–करोड़ों रुपये का नोट जला दिया जता है । आखिर इतना पैसा पदाधिकारियों के पास कैसे आता है ? क्या सरकार इस पर ध्यान देती है?

महोदय, राज्य में ग्रामीण कार्य विभाग में ग्लोबल टेंडर करने की योजना बनायी गयी है । इससे राज्य के छोटे–छोटे संवेदक बेरोजगार हो जायेंगे । ग्लोबल टेंडर में भारी गोलमाल किया जा रहा है और निर्धारित दर से अधिक दर बढ़ाकर टेंडर होता है ।

महोदय, राज्य के संवेदकों के हित में ग्लोबल टेंडर की योजना समाप्त करने की जरूरत है ।

अध्यक्ष महोदय, 100 या उससे अधिक की आबादी के 13 हजार 815 बसावटों में भी अभी तक मात्र छः हजार की राशि बसावटों के सड़क निर्माण की स्वीकृति विभाग द्वारा दी गयी है ।

महोदय, 8 हजार 95 किलोमीटर पथों के निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध अभी तक मात्र 01 हजार 983 किलोमीटर सड़कों का ही निर्माण कराया गया है।

महोदय, औरंगाबाद जिला के गोह विधान सभा क्षेत्र सहित पूरे राज्य में लगभग एक चौथाई सड़कों की स्थिति खराब है ।

अध्यक्ष महोदय, मेरे गोह विधान सभा क्षेत्र में एक सौ या उससे अधिक बसावटों वाले क्षेत्र से मुख्य सड़क तक बारहमासी सड़क बनाने के लिए पुनः सर्वे कराने की जरूरत है ।

(क्रमशः)

टर्न–14 / धिरेन्द्र / 18.02.2026

....क्रमशः....

श्री अमरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारे क्षेत्र में काफी संख्या में सड़कें नहीं बनी हैं । मेरे गोह विधान सभा क्षेत्र में एस॰एच॰–68 शिवगंज बैदरावाद रोड से अकौना मोड़ पिपराही होते हुए महदीपुर जाने वाली सड़क । एस॰एच॰–68 के अरण्डा मोड़ से भगवतीपुर माईनर होते हुए बख्तियारपुर गांव तक सड़क । एस॰एच॰–68 झिकटिया मोड़ से झिकटिया गांव तक जाने वाली सड़क । एस॰एच॰–68 रूकुन्दी मोड़ से रामडीह मोथा तक सड़क । तिनेरी मोड़ लट्टा पथ के खैरा मोड़ से खैरागांव तक सड़क । बाला बिगहा मोड़ से भुजहण्ड गांव होते हुए कैथी तक सड़कों का निर्माण जनहित में कराना अति आवश्यक है । अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त कई सड़कें हैं जिनका सर्वे कराकर निर्माण कराना जरूरी है । अध्यक्ष महोदय, गोह विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुल निर्माण योजना के अधीन गोह प्रखण्ड के माईनर में असामपुर गांव के सामने पुल तथा अमारी सूर्य मंदिर और कैथी के बीच पुल का निर्माण कराना आवश्यक है । अध्यक्ष महोदय, मेरे गोह विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण तथा अनुरक्षण योजना के अधीन पथों के अनुरक्षण में विभाग के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है । पथों का अनुरक्षण समय पर पूरा नहीं किया जा रहा है, इसकी जाँच करायी जानी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार में एक पॉलिसी आई थी जिसमें ठेकेदारी में आरक्षण का प्रावधान किया गया था । आपके द्वारा जानबूझ कर आरक्षण पॉलिसी को लागू नहीं किया गया । महोदय, आज ये तमाम जैसे गांव जहाँ दबे–कुचलों की आबादी ज्यादा है वहां संपर्क पथ नहीं बना है लेकिन सम्पन्न लोगों के गांवों की सारी सड़कें बनी हैं। बिहार में हजारों ऐसे दलित शोषित आदिवासी के गांव हैं जहां आपके द्वारा जानबूझ कर सड़कों का निर्माण नहीं कराया गया । अध्यक्ष महोदय, हाल ही में विभाग

द्वारा ग्लोबल टेंडर किया गया, जिसमें एक ही ठेकेदार को 20 से 50 सड़कों का निर्माण कार्य दिया गया । यह जाहिर करता है कि आपके मन में राज्य के छोटे–छोटे संवेदकों के प्रति कितनी सहानुभूति है । महोदय, राज्य की ऐसी सड़कें जो मेंटेनेंस के अधीन है उसका मेंटेनेंस नहीं किया गया और मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपये का बंदरबाट कर लिया गया । अध्यक्ष महोदय, आखिर क्या बात है कि मंत्री महोदय जिस–जिस विभाग में रहें, उस विभाग के अभियंताओं के यहां निगरानी का छापा पड़ता है और घर से लाखों रुपये मिलते हैं या जला दिये जाते हैं । अध्यक्ष महोदय, बाबा साहेब द्वारा भारत के संविधान के किस छंद, उपछंद या पेज में यह लिखा है कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हों और आपको संरक्षण मिलता रहे । महोदय, हद तो तब हो गयी जब नोट पकड़ाया तो कुछ नहीं, नोट जलाया तो कुछ नहीं और करप्शन की बात आई तो मंत्री महोदय आग–बबूला हो जाते हैं । मंत्री महोदय की मेहरबानी भ्रष्ट अफसरों पर ज्यादा रहती है । समस्तीपुर, हाजीपुर के अभियंता इसके उदाहरण हैं । महोदय, आज बिहार के सारे ठेकेदार काम करने के बाद अपने पैसे के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं और आपकी मुस्कुराट में चार चांद लगा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक सशक्त माध्यम है । सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्य में सहकारी समितियों के गठन के लिए ग्रामीण जनता को उत्प्रेरित करे । अध्यक्ष महोदय, बार–बार यह जिक्र होता है कि वर्ष 2005 के पहले क्या था, कुछ नहीं था ? अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005 के पहले सामाजिक न्याय का दौर था । गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद जी के द्वारा उस समय समाज में ऊँच–नीच, छुआछूत के खाई को समाप्त किया गया । गरीबों, दलितों, शोषितों को आवाज दी गयी । उन्हें बाबा साहेब डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो अधिकार प्रदान किया गया था, जो जगदेव बाबू का सपना था, उसके लिए जागृत किया गया । अध्यक्ष महोदय, आज राज्य में 26,306 सहकारी समितियां अस्तित्व में है जबकि वर्ष 2004 में 31,681 सहकारी समितियां कार्य कर रही थी । अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2004 में 590 मत्स्यजीवी सहकारी समितियां थी जो आज घटकर 501 हो गयी है । वर्ष 2004 में 1,091 बुनकर समितियां थी जो आज घटकर 621 हो गयी है । वर्ष 2004 में 1,874 सहकारी उपभोक्ता भंडारण था जो आज घटकर 821 हो गया है । अध्यक्ष महोदय, राज्य में भंडारण एवं विपणन की समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण प्रत्येक वर्ष लगभग दस हजार करोड़ की सब्जी बर्बाद हो जाती है । अध्यक्ष महोदय, इसको रोकने के लिए वर्ष 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो तत्कालीन सहकारिता मंत्री जी के द्वारा तरकारी ब्राण्ड के नाम से सब्जी सहकारी योजना की शुरूआत की गयी थी, जिसका उद्देश्य राज्य के सब्जी उत्पादक किसानों को आर्थिक लाभ पहुँचाना

और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सब्जी आपूर्ति किया जाना । अध्यक्ष महोदय, गठबंधन की सरकार बदल जाने के बाद इस योजना पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया और आज भी यह योजना राज्य के 150 प्रखण्डों में ही चल रहा है, इसका विस्तार किया जाना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, मैं गोह विधान सभा क्षेत्र के गोह हसपुरा प्रखंड और रफीगंज प्रखण्ड में इस योजना को लागू कराने की मांग करता हूँ । अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सब्जी उत्पादक किसानों की सुविधा के लिए गोह, हसपुरा में सब्जी विक्रय प्रांगण बनाने की मांग करता हूँ जहां सब्जी के भंडारण, संरक्षण और बिक्री की समुचित व्यवस्था हो । अध्यक्ष महोदय, राज्य में पोषणयुक्त चावल, मतलब एफ॰आर॰के॰ की कमी के कारण पैक्सों और किसानों को काफी परेशानी हो रही है महोदय, यह जनहित का मामला है और धान अधिप्राप्ति में कठिनाई आ रही है । अध्यक्ष महोदय, राज्य के पैक्सों को धान अधिप्राप्ति के लिए छः माह तक ब्याज मुक्त राशि मिलनी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सहकारिता विभाग के लिए आने वाले वित्तीय वर्ष में बजट की राशि में स्वयं कटौती कर दी है । अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2025–26 के वित्तीय वर्ष में सहकारिता विभाग के लिए 1231.92 करोड़ रुपये की बजट राशि रखी गयी थी, जिसे घटाकर वर्ष 2026–27 के बजट में 1201.41 करोड़ रुपया कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, विश्व की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल पत्रिका 'द लैसेन्ट' की जनवरी, 2026 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की हवा को साइलेंट किलर बताया गया है । अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य की 100 प्रतिशत आबादी ऐसी हवा में सांस लेने को मजबूर है जो डब्ल्यू॰एच॰ओ॰ की मानको से कई गुणा ज्यादा जहरीली है और साइलेंट किलर का काम कर रही है । महोदय, यह न केवल पर्यावरण का मामला है वरन् मेडिकल इमरजेंसी का भी मामला है । सरकार को इस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है ।

महोदय, राज्य के प्रत्येक पंचायत में सुधा डेयरी का आउटलेट खोलने की योजना बनायी गयी है । मैं गोह विधान सभा क्षेत्र के सभी पंचायतों में सुधा डेयरी के आउटलेट खोलने की मांग करता हूँ । यह व्यवस्था की जाय कि क्षेत्र के सभी पैक्सों में सुधा डेयरी का आउटलेट खोला जाय । महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आपका समय समाप्त चुका है । कृपया बैठ जाएं ।

श्री अमरेन्द्र कुमार : महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि–

तुम्हारी फाइलों में गांवों का मौसम गुलाबी है,
मगर ये आंकड़े झूठे हैं ये दावा किताबी है ।

अध्यक्ष महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार ।

टर्न–15 / अंजली / 18.02.2026

श्री प्रमोद कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके प्रति आभार है कि आपने बोलने का अवसर दिया । मैं ग्रामीण कार्य विभाग के बजट के समर्थन में बोलने के लिए भाग ले रहा हूं । महोदय, बजट पर चर्चा करने से पहले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को याद करना आवश्यक है । अटल बिहारी वाजपेयी जी अगर बजट से पैसा नहीं दिए रहते, तो आज गांव में प्रधानमंत्री सड़क और ढलवा सड़क देखने को नहीं मिलती । महोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि समाज के अंतिम व्यक्ति का जब तक उदय नहीं होगा, तब तक भारत और बिहार उदयमान भारत नहीं बनेगा, उन्हीं के सपने को साकार करने के लिए मान्यवर अटल बिहारी वाजपेयी ने, एन0डी0ए0 सरकार ने गांव, गली और उच्च पथ सभी पथों को विकसित करने का काम किया । महोदय, पहले क्या था ? पहले गांव में कोई बड़े लोग थे, उनके दरवाजा पर दो सौ फीट, पांच सौ फीट सोलिंग था, तो लोग कहते थे कि ये गांव के बड़े लोग हैं, आज जो बड़े लोग हैं वे खास लोग थे, खास लोग के दरवाजा पर जाइए तो सोलिंग, जो पहले खास थे वे आज आम हो गए हैं, यह है एन0डी0ए0 सरकार की देन ।

(व्यवधान)

सुनिए भाई । महोदय, जब हमलोग वर्ष 2005 में जीतकर आए, तो उसके बाद अटल जी के बाद यू0पी0ए0 सरकार दिल्ली में आ गई और मान्यवर रघुवंश बाबू उस समय मंत्री हुए, यूपी0ए0 सरकार के और यू0पी0ए0 सरकार में ये ग्रामीण विकास की सड़कों को भारत सरकार की एजेंसी, एन0एच0पी0सी0, एन0टी0पी0सी0, सी0पी0डब्लू0डी0 और इरकॉन ऐसी एजेंसियों को यू0पी0ए0 सरकार ने ग्लोबल टेंडर दे दिया था और वह ग्लोबल टेंडर ऐसा दिया था कि हम सभी माननीय विधायक जब क्षेत्र में जाते थे, तो बड़ी–बड़ी कंपनी को वे टेंडर दिए थे और वह कंपनी पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर, लोकल कॉन्ट्रैक्टर को खोज कर मिट्टी का काम करा दिया, गिट्टी का काम बाकी रहा । कहीं गिट्टी का काम करा दिया, अलकतरा का काम बाकी रहा और महोदय, आप पुराने सदस्य हैं आप स्वयं जानते हैं कि वर्ष 2005 के बाद ऐसी छः–सात की स्थिति हो गई कि सभी माननीय सदस्य मान्यवर मुख्यमंत्री जी को कहा कि भारत सरकार ने जो ग्लोबल टेंडर दिया है अपनी एजेंसी को, उससे मुक्त कराया जाए और मान्यवर मुख्यमंत्री जी गए और उस समय तत्कालीन डिप्टी सी0एम0 सुशील कुमार मोदी और भारत सरकार को कहे कि नहीं यह काम जब करेगी तो बिहार की ही एजेंसी करेगी और बिहार के उन एजेंसियों से छीनकर और बिहार सरकार के अधिकारी बैठे हुए हैं, दुबारा टेंडर कराकर और ग्लोबल टेंडर तोड़कर और पार्ट–बाई–पार्ट टेंडर करके और उन जर्जर सड़कों का विकास करने का काम मान्यवर मुख्यमंत्री एन0डी0ए0 सरकार ने किया ।

हमलोग चुनाव में थे, माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये प्रोफेसर, मंत्री के बाद प्रोफेसर, ये पहले हैं, इसके लिए इनको धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा और इन्होंने काम बहुत अच्छा किया, एका–एक ग्लोबल टेंडर दिया । हमारे क्षेत्र में 102 रोड सात एजेंसी को मिल गई, पब्लिक में चारों बगल बोर्ड लगा, लोगों में खुशहाली जगी कि अब यह रोड बनेगा, वह रोड बनेगा, हमलोग कॉन्ट्रैक्टर को कहते रहे कि भाई उधर करो, उधर कुछ गिराओ, उधर गिराओ परंतु अभी तक वह ग्लोबल टेंडर का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, अधिकारी सुन रहे हैं, महोदय, संवेदक की जो निविदा होती है, निविदा में वर्क प्लान होता है, वर्क प्लान में लिखा जाता है कि डे–बाई–डे क्या काम हो रहा है, मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, अधिकारी सुन रहे हैं, उनके पास कोई वर्क प्लान का चार्ट नहीं है, अगर वर्क प्लान का चार्ट रहता तो जितना ग्लोबल टेंडर हुआ है सभी ठेकेदार आज कटघरा के अंदर रहते, मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं लेकिन महोदय, हम सरकार हैं, हमने अनुसूचित वर्ग को आरक्षण दिया संवेदक के रूप में, अनुसूचित वर्ग के संवेदक को आरक्षण दिया, पिछड़े वर्ग के संवेदक को आरक्षण दिया, समान वर्ग के संवेदक को आरक्षण दिया, नीति बनाई कि इतना रुपया, इतना रुपया, ये सभी संवेदक पेटी कॉन्ट्रैक्टर के फेर में धूल फांक रहे हैं, सही बात मैं कह रहा हूं...

(व्यवधान)

सुनिए । मेरा मंत्री जी से आग्रह होगा कि अपने संबोधन में जो संवेदक निर्धारित नियमानुसार काम नहीं किए, वर्क प्लान के अनुसार उस पर एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ तो आखिर इसके जिम्मेवार कौन हैं, उसकी जिम्मेवारी निर्धारित कर और जनता ने जो विश्वास दिया है, उस जनता के सड़कों के निर्माण का काम शीघ्र से अतिशीघ्र होना चाहिए ऐसा मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं । महोदय, काम तो बहुत हुआ, वित्तीय वर्ष 2026–27 में 13815 बसावट, 16652 किलोमीटर सड़क और अब तक 6083 बसावट और लंबाई 8095 किलोमीटर, इस प्रकार प्रधानमंत्री सड़क, पहले प्रधानमंत्री सड़क जहां 500 थे उसको किए, धन्यवाद है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, कहा कि नहीं, जहां एक सौ की भी आबादी होगी उसे भी बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाएगा और आज देन है कि सड़कों का जाल बिछा है लेकिन उन सड़कों की मरम्मत करने की जो नीति है जिसको ग्लोबल किया गया है उसको अगर पार्ट–बाई–पार्ट में किया रहता, तो अब तक ये सभी काम पूरे हो जाते और ठेकेदार से हर आदमी, एक आदमी, दो आदमी और 45 रोड का मेरे यहां टेंडर डाल दिया है और 15 परसेंट बिलो पर डाला है...

(व्यवधान)

और सुनिए, इसी तरह पौने दस बिलो पर 22 रोड का डाल दिया है, ठेकेदार भागे फिर रहा है, कह रहा है घाटा लगेगा, घाटा लगे, नफा लगे बनाओ तो सही, कोई अधिकारी पूछने के लिए तैयार नहीं है । महोदय, अधिकारी बैठे हुए हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं आखिर इसकी जिम्मेवारी निर्धारित करना जनहित में आवश्यक है । महोदय, काम तो प्रधानमंत्री सड़क का फेज–1 हुआ, फेज–2 हुआ और फेज–3, फेज–3 में भी गांव में अब सड़क बन गया है लेकिन अब गांव के लोग पक्का घर बना रहे हैं, अब बालू का ट्रक दस चक्का वाला जा रहा है, गांव के सड़क का मानक है 9 टन का और 100 टन की गाड़ी जा रही है, तो ऐसे रोडों को चिन्हित करके उसके मानक के हिसाब से काम होना चाहिए ताकि गांव की जो सड़क है वह जल्दी ध्वस्त नहीं हो, जो मानक है उस मानक में और अधिक सुधार कर फेज–3 में जो प्रधानमंत्री सड़क है, अभी सरकार का सिस्टम है कि पी0डब्लू0डी0 ग्रामीण पथ है ।

(क्रमशः)

टर्न–16 / पुलकित / 18.02.2026

(क्रमशः)

श्री प्रमोद कुमार : जो इस पार से उस पार पी0डब्ल्यू0डी0 रोड को जोड़ने वाली है । वैसे पथों को, जो लंबे–लंबे पथ हैं, उनको चिन्हित करके स्टेट हाईवे में बनाने का जो संकल्प हुआ है, इसके लिए धन्यवाद है । लेकिन उन पथों को शीघ्र ही चिन्हित करना चाहिए । माननीय सदस्य से राय लेनी चाहिए और उसको चयनित करके भारत सरकार ने जो निर्देश दिया है, उस निर्देश के मानक के अनुसार उसे भी आर0डब्ल्यू0डी0 को बनाना है, तो बनाने का काम हों ।

महोदय, इसी प्रकार आर0डब्ल्यू0डी0 के पुल के लिए, प्रधानमंत्री द्वारा जो लगभग 1163 पुल का निर्माण का काम चल रहा है और 157 किलोमीटर चौड़ी सड़क का भी काम चल रहा है । प्रधानमंत्री फेज–2 में काम चल रहा है, इस प्रकार फेज–2 में 2456.47 किलोमीटर पथ, जिसमें 2442 किलोमीटर का कार्य अभी प्रगति पर है । 102 पुल का भी काम प्रगति पर है । काम तो बहुत चल रहा है । बहुत काम चल रहा है । भूतोः न भविष्यति ।

(व्यवधान)

नहीं, कभी नहीं गिरा, सुन लीजिए । यह आपके समय का जो पुल था, आपके समय में बजट क्या था ? सुन लीजिये । आपके समय का जो बजट था, 346 करोड़ । मात्र 346 करोड़ का बजट था 2003–04 में और 2004–05 में 891 करोड़ का बजट हुआ । यह बात समझ लीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति । बैठे–बैठे मत बोलिये । प्रमोद बाबू आप अपनी बात रखिये ।

श्री प्रमोद कुमार : सुन लीजिए । ये आपके समय का जो पुल निर्माण का था, अब तो जो सड़क बन रही है, सात साल की गारंटी के आधार पर सड़क बन रही है। सड़क में गड्ढा बताओ, ईनाम पाओ । इस नीति से सड़क बन रही है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त होने जा रहा है । कृपया संक्षिप्त करें ।

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, इस नीति से सड़क बन रही है और फेज–2 में, इस प्रकार महोदय मुख्यमंत्री संपर्क योजना में 835.92 करोड़ रुपये से 616 पथों का काम चल रहा है । 181 किलोमीटर मुख्यमंत्री अनुरक्षण समिति, महोदय यह मैं नहीं कह रहा हूं, अखबार भी छाप रहा है कि सरकार का काम कितना अच्छा हो रहा है, अखबार में भी 181 किलोमीटर की पक्की सड़क । राज्य में 36,800 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का और सी0एम0 ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना 2100 किलोमीटर ।

अध्यक्ष : प्रमोद बाबू, आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, सड़कों का जाल बिछा हुआ है । अब थोड़ा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो ग्लोबल किये हैं, उसको अब तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसके वर्क प्लान की समीक्षा कर, एक तिथि निर्धारित कर और गुणवत्तापूर्वक काम को पूरा करें, ताकि हम सभी विधायक जब क्षेत्र में जाएं, तो जनता जय–जयकार करें । ठीक है न जी ? ठीक है न ?

(व्यवधान)

यह मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है और भविष्य में जो भी निविदा करें, वह मंत्री महोदय हैं...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नचिकेता जी ।

श्री प्रमोद कुमार : अब वह भविष्य में जो निविदा करें, वह पार्ट बाई पार्ट करें, ग्लोबल नहीं करें । ग्लोबल हम लोग का बहुत खतरे की चीज है । आप महोदय अवसर दिये, आपको और अपने क्षेत्र की जनता को कोटि–कोटि धन्यवाद है ।

अध्यक्ष : ठीक है, अब बैठ जाइये । अब नचिकेता जी आप बोलिये ।

श्री नचिकेता : बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग की इस अनुपूरक मांग पर आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया है । साथ ही साथ मैं अपनी पार्टी और पार्टी के सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी का, जमालपुर की जनता का बहुत–बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि लोकतंत्र के इस मंदिर में मुझे आने का अवसर प्रदान किया और अपनी बात को आपके बीच रखने का हमें मौका दिया है । अध्यक्ष महोदय, मैं एक नया मेंबर हूं और जब से इस बजट सत्र को सुन रहा हूं, जब कभी भी किसी विभाग के अनुदान की मांग आ रही है, विपक्ष उसमें 10/– रुपये का कटौती प्रस्ताव लेकर के आता है । साथ ही साथ...

(व्यवधान)

हम नियम तो सीख ही रहे हैं आप लोगों से, थोड़ा सुनिए आप लोग भी । कटौती प्रस्ताव तो ले आते हैं और साथ में लगातार आप लोग अपने क्षेत्रवार काम की मांग भी करते हैं । काम की मांग भी करते हैं और कटौती का प्रस्ताव भी लाते हैं । यह लगता है कि अंतर्विरोध आपके अंदर है। इस बढ़ते हुए, बदलते हुए बिहार के साथ आप खड़े तो जरूर हैं, लेकिन अपने मन के अंदर सिर्फ विरोधी होने की भावना के लिए आप यह कटौती का प्रस्ताव लेकर के आते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग वह विभाग है जो बिहार के ग्रामीण इलाकों के अंदर हुए बदलाव का ध्वजवाहक है । वह बिहार, जो बदहाल बिहार था, जो गड्ढों में पड़ा बिहार था, जिस बिहार की चर्चा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होती थी, जहां जाने के लिए, जिस ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए कितने ही कष्ट उठाने पड़ते थे । आज 20 वर्षों के शासन में श्री नीतीश कुमार जी ने ऐसे बिहार का निर्माण किया है कि दिन–रात और बारहों महीने आप किसी से भी, किसी स्थान पर पहुंच सकते हैं। सुदूर से सुदूर किसी भी गांव के अंदर, किसी भी बसावट के अंदर, 50 घर की बसावट भी है तो वहां भी आप चार चक्का गाड़ी से जा सकते हैं । इस बिहार का निर्माण श्री नीतीश कुमार जी ने और ग्रामीण कार्य विभाग ने बिहार के अंदर किया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, ये लोग बार–बार प्रश्न उठाते हैं कार्यशैली के ऊपर, हमारी कार्यशैली के ऊपर प्रश्न उठाते हैं ।

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

एक लाइन अर्ज है इनके लिए– जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना ।

साथियों, 15 वर्ष आपको भी मिले थे और क्या बिहार आपने बनाया था, इसकी गवाही सदन में आपकी आज की संख्या भी बता रही है । बिहार की जनता को आज भी आपके नाम पर वह डर है कि उसके मन में कभी भी लगता है अंश मात्र भी, कि आप आने वाले हैं, तो आप लोगों के खिलाफ एकजुट होकर के नीतीश कुमार जी के विकास के साथ जनता खड़ी होती है।

आपके पूरे कार्यकाल के अंदर, आपने 15 सालों के अंदर बिहार में मात्र 835 किलोमीटर की ग्रामीण सड़क दी । जिसको 20 वर्षों के अंदर नीतीश कुमार जी ने बढ़ा कर के 1.17 लाख किलोमीटर करने का काम किया है 20 वर्षों के अंदर । यह बदलता हुआ बिहार है ।

आप सवाल खड़ा करते हैं । 15 साल तक आपको मौका मिला । अभी यह कह रहे थे कि सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रही थी । यह सामाजिक न्याय था कि पारिवारिक न्याय को दिलाने के लिए रास्ता तैयार

करने का था, यह बिहार की जनता समझ चुकी है । आपकी सामाजिक न्याय के अंदर भय, भ्रष्टाचार और आतंक हुआ । कोई भी सड़क, कोई भी योजना, अब लोग यहां कहते हैं बिहार के अंदर अलकतरा पी गए लोग । अजीबो–गरीब किस्म की बातों को सुनना पड़ता था बिहार के लोगों को । अलकतरा पी गए, चारा खा गए । इस प्रकार की आइडेंटिटी आप लोगों ने बिहार की क्रिएट की । लेकिन बिहार की आइडेंटिटी को चमकाने का काम किसी ने किया, तो वह नीतीश कुमार जी ने किया है । और...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति बनाये रखें ।

श्री नचिकेता : केंद्र में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और बिहार की सरकार ने मिलकर बिहार को एक बेहतर बिहार बनाया और आप लोगों ने जिस बिहार को बदनुमा दाग दिया था, उस दाग से निकाल कर चमकाने वाला बिहार बनाया है ।

(व्यवधान)

साथियों, आज के बिहार के अंदर, पहले यह तय किया गया था ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं ।

श्री नचिकेता : कि 500 बसावटों का जहां भी कहीं टोला होगा, उस टोले तक संपर्क करके साधन को बनाया जाएगा । फिर 250 बसावटों पर आया, आज 100 घर का भी टोला है, तो वहां पक्की सड़कों की व्यवस्था इस सरकार ने की है । यह विकास का हमारा मानक है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : कृपया शांति बनाए रखें ।

श्री नचिकेता : साथियों आज हमारा काम करने की नियत पर सवाल उठाने वाले लोगों को मैं यह कहना चाहता हूं कि...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य शांति बनाए रखें ।

टर्न–17 / हेमन्त / 18.02.2026

श्री नचिकेता : उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम बारामासी सड़कों की बात करें, तो बिहार के जितने अनजुड़े गांव थे, और बसावटे थीं

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, शांति बनायें।

श्री नचिकेता : उसमें 53,594.09 किलोमीटर तक की सड़क बसावटों में पहुंचाने का काम कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भारत सरकार द्वारा 2426. 47 किलोमीटर का जो लक्ष्य रखा गया था और 102 पुलों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि उसमें भी 2456.47 में से 2442.33 किलोमीटर लंबाई की सड़क बना ली गयी और

जितने भी पुल थे, 102 पुलों में 98 पुलों को तैयार कर दिया गया और बाकी में काम जारी है। सात निश्चय भाग तीन में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–तीन में 6162.71 कि0मी0 पथ का उन्नयन और 709 पुलों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें से 5383.09 किलोमीटर पथ का निर्माण हो चुका है, 383 पुल पूरे किए जा चुके हैं और 685 कि0मी0 सड़क का निर्माण और 326 पुलों का निर्माण अभी जारी है तो यह हमारा काम करने का तरीका है। आपकी तरह कागजों पर पैसा निकालने का काम बिहार में अब नहीं होता है, इसकी तकलीफ आप लोगों को है।

उपाध्यक्ष : बैठे–बैठे नहीं बोलें। माननीय सदस्य, शांति बनाएं।

श्री नचिकेता : उपाध्यक्ष महोदय, अब इनका बोलना भी स्वाभाविक है।

उपाध्यक्ष : आप अपना भाषण जारी रखें। माननीय सदस्य, आसन की ओर मुखातिब हों, आपका समय बीतता जा रहा है।

श्री नचिकेता : महोदय, इनकी परेशानी भी वाजिब है, लाजमी है। इनके नेता तो अपने शपथ ग्रहण की तारीख भी घोषित कर चुके थे। इनमें से कई लोग होंगे, जो मंत्रिमंडल में जाकर इस विभाग का भी बजट पेश करने की इच्छा रखते होंगे।

उपाध्यक्ष : विषय वस्तु पर अपना विचार रखें।

श्री नचिकेता : नहीं मिलने पर तकलीफ तो होना स्वाभाविक है, इनकी बेचैनी भी स्वाभाविक है। खैर, ये बदलता हुआ बिहार है, ये बढ़ता हुआ बिहार है। इसमें इतना कुलबुलाहट मत रखिए। हम आग्रह करेंगे कि साथ मिल कर चलिए, सहयोग कीजिए और मिल कर, जैसे यहां लिखा हुआ है कि विपक्ष भी सरकार का भाग होता है। तो आइए, मिलकर बेहतर बिहार बनाने के लिए साथ दीजिए, कटौती प्रस्ताव को वापस लीजिए, सरकार का सहयोग कीजिए और जहां कहीं भी काम की जरूरत है, सरकार के साथ मिलकर बेहतर बिहार बनाने का काम कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, बिहार की सड़कों के हालात को कौन नहीं जानता ? बिहार में जब कोई आदमी बाहर से आता था, तो चाहे यहां की मुख्य सड़कें हों, पीडब्ल्यूडी की सड़कें हों, या ग्रामीण पथ हों, बिहार की सूरत को बताने का काम यह सड़कें करती थीं। आज जो लोग यह सवाल उठाते हैं कि किसी बसावट तक जाने का रास्ता नहीं है, तो आप बिहार से बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि आज बिहार कैसा बना है ? आज वह लोग जब सुदूर इलाकों से भी छठ पर्व के अंदर आते हैं, अपनी चार चक्का गाड़ी से ही दिल्ली से चले आते हैं। आज वह लोग जो दिल्ली के अंदर चले गए, वह लोग अपने सुदूर–से–सुदूर गांव आने के लिए भी चार चक्का वाहन का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि सुदूर से सुदूर गांव तक भी चकचकाती हुई सड़कें हैं। इतना ही नहीं, मैं इस विभाग के धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो दलित बस्तियां हैं, जो महादलित बस्तियां हैं, ऐसी बसावटें हैं, जिस पर जाने के लिए रास्ते के लिए जमीन उपलब्ध नहीं थी, उसके लिए भी योजना इन्होंने बनाई और कहा कि हमारा विभाग भूमि अधिग्रहण करके भी,

उसका भुगतान करके भी महादलित और दलित बस्तियों के अंदर सड़क पहुंचाने का काम कर रहा है और यह काम जारी है। यह है सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय के प्रणेता ऐसे लोग होते हैं। सामाजिक न्याय की थोथली बातें कर के भ्रष्टाचार और आतंक फैलाना सामाजिक न्याय नहीं है । न ही लोहिया, न ही जयप्रकाश जी जैसे लोग इस प्रकार की चीजों की वकालत करते हैं, जिसका नाम लेकर आप लोग आज भी सामाजिक न्याय का नारा देते हैं।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपने क्षेत्र की समस्या रखें। एक मिनट का वक्त है आपके पास।

श्री नचिकेता : जमालपुर विधानसभा क्षेत्र की कुछ सड़कों की मांग मैं लिखित रूप से माननीय मंत्री जी को दे रहा हूं और एक मांग जो सरकार से हमारी है कि ग्रामीण कार्य विभाग की एक सड़क, जो सफियाबाद से रामनगर होते हुए जमालपुर शहर की तरफ जाती है, उस सड़क को आर0सी0डी0 में दे दिया जाए ताकि उस सड़क को चौड़ा करते हुए, रेलवे लाइन के ऊपर रेलवे ओवर ब्रिज बनाते हुए जमालपुर शहर के लिए एक और पैरेलल रास्ता बन सके। यह मेरा आग्रह सरकार से है कि इसको स्वीकार करेंगे। मैं एक बार पुनः आप सब से आग्रह करता हूं कि अपने कटौती प्रस्ताव को वापस लें और सरकार का सहयोग करें। जय नीतीश कुमार, जय जनता दल यूनायटेड धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मो0 आबिदुर रहमान जी। चार मिनट का वक्त है आपके पास।

मो0 आबिदुर रहमान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूं। सहकारिता विभाग, जो पूरे बिहार को आज से नहीं, 70 साल से लेकर अब तक हम लोग देख रहे हैं, यह धान खरीद बिक्री जो भी पैसा दिया जाता है और उतना ही पैसा उस पब्लिक के द्वारा, ताकि जो धान पैदा करता है।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय मंत्री जी खड़े हैं।

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : महोदय, यह कह रहे हैं कि 70 साल से हम देख रहे हैं, तो 60 साल से अधिक तो यही राज किए हैं।

मो0 आबिदुर रहमान : हुजूर, आप क्या कर रहे हैं ? आप भी तो वही कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष : आप अपना भाषण जारी रखें।

(व्यवधान)

कृपया शांति बनाए, माननीय सदस्य को बोलने दिया जाए।

मो0 आबिदुर रहमान : आप भी तो वही कर रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : अभी शुरू किया है सुधार।

मो0 आबिदुर रहमान : जो किसान के द्वारा धान खरीद होता है और वह धान उस वक्त खरीद कर बिचौलियों के द्वारा दिया जाता है, पैक्स के द्वारा, वह मूल्य उस किसान को नहीं मिलता है और बाद में उसको काफी परेशान किया जाता है। पैक्स मैनेजर के द्वारा जहां भी धान खरीद हुआ है, यह इसी तरह से होता है और यह धान को खरीद करके, उतना ही नहीं, ताकि जिसको देना है, मिल के

द्वारा भी लेने से इनकार कर दिया जाता है। उसको चूहा और दो पैर वाला चूहा दोनों मिलकर उसको नष्ट कर देता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है और किसान को समय पर उसका मूल्य नहीं मिलता है।

महोदय, पशुपालन का ही बजट आज है, उसके विरोध में भी मैं बोलना चाहता हूं। हमारे यहां अररिया फारबिसगंज में और तमाम पूरे हिंदुस्तान का, चार–पांच मीट फैक्ट्री वहां बना दी गई हैं। तारा मीट फैक्ट्री, वह सारा विदेश सप्लाई होता है। इसका लाइसेंस भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ये हत्या हो रही है और वहां पर चोरी, डकैती बढ़ रही है। वहां पर अच्छी–अच्छी नस्ल के मवेशी लाकर रात भर में काट कर मिल के द्वारा पैक करके गल्फ एरिया भेज दिये जाते है। लोग त्राहिमाम करते रहते हैं, किसान परेशान रहते हैं कि मेरा मवेशी कहां गया ? इतना ही नहीं, उस मवेशी के खून के कारण, जो भी पानी हम लोग पीते हैं, 20 फीट की दूरी पर पानी पीते हैं, ताकि हम लोग उसके खून को पीते हैं, तो इससे हम लोगों को निजात दिलायी जाए। जो भी बिरादरी के लोग वहां हैं, इससे आम लोगों को नुकसान हो रहा है। इस लाइसेंस के लिए हम लोग भारत सरकार को लिखें, मंत्रीजी को कहें, ताकि वहां की मीट फैक्ट्री को हटाया जाए। वहां की आवाम को इससे कुछ नहीं मिलता है, इससे विदेश के लोगों को मुद्रा मिलती है। भारत सरकार को इससे काफी कमाई है और हम लोगों को दुष्ट किया जाता है। आज कोई कम्यूनल राइट होगा, सबसे पहले हमारी कौम, हमारा बिरादर फंसेगा, जबकि हमें उससे कुछ लेना–देना नहीं है। हमारा दुष्ट किया जा रहा है। उस जमीन को खत्म किया जा रहा है। हमारे यहां 20 फीट पर पानी है। जब चापाकल चलाते हैं, उससे खून ही खून निकलता है। लोगों के धर्म को नष्ट किया जा रहा है। हमारी इस असेंबली के द्वारा, विधान सभा द्वारा, भारत सरकार को लिखा जाए, ताकि इस लाइसेंस को कैंसिल किया जाए, ताकि आम लोगों को इस दुष्ट से निजात मिल सके और यह बात जो हम कह रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। यह एविडेविट करके भी हम दे सकते हैं। आप आकर देखिए, गल्फ कंट्री के सारे लोग आकर बैठे रहते हैं। फारबिसगंज, अररिया, पूर्णिया, इससे प्रभावित हो रहे हैं। इससे लोगों को बचाया जाए। सहकारिता से लोग, जो अपने ख्वाब की ताबीर सोचते थे, वो ताबीर खत्म हो चुकी है। उसको फिर से जांच कर देखा जाए, ताकि जो सच्चाई है, उस सच्चाई को आप लोग देखिए।

महोदय, हमारे यहां अररिया जिला में बिजली की प्रॉब्लम है, ताकि हमारे यहां मदनपुर फीटर पर पूरा तार कट–कट कर गिर रहा है और कई बार हम कह चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई ट्रांसफॉर्मर बैठा हुआ है। उसी तरह से अररिया में भी कई जगह गैरहा, फरोटा, संदलपुर, बोची और पिड़वा खुड़ी, सब जगह तार कट–कट के गिर रहा है। लोग परेशान हैं, कहा जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय पूरा हो रहा है।

मो0 आबिदुर रहमान : इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय बिहार।

टर्न–18 / संगीता / 18.02.2026

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी जी, 5 मिनट का समय है आपके पास ।

श्री राजू तिवारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, ग्रामीण कार्य विभाग के अनुदान के मांग के पक्ष में । महोदय, यह बजट केवल बजट नहीं है बल्कि बिहार के गांवों का भविष्य है, सड़क केवल मिट्टी, गिट्टी और डामर का ढांचा नहीं होता, सड़क विकास और स्वास्थ्य और समृद्धि का रास्ता होता है । महोदय, पूरे बिहार में जिस तरह से एन0डी0ए0 के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर गांव में कोई ऐसा पंचायत नहीं है, जहां ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा, सभी ग्राम को मुख्यालय से जोड़ने के लिए काम किया गया हो और लगातार काम हो रहा है, थोड़ा–बहुत काम तो पहले कुछ था नहीं, अभी माननीय सदस्य ने बताया कि कितना काम पहले हुआ था लेकिन आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी के कार्यकाल में लगातार काम हो रहा है । महोदय, मेरे विधान सभा में बहुत सारा कुछ काम हुआ है इसलिए मैं सरकार का अभिवादन भी करता हूं लेकिन मेरी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि गोपालगंज में तटबंधों पर कालीकरण का काम हो रहा है । मेरे तरफ चंपारण तटबंध, जिसके दोनों तरफ आबादी है, पहले तो शायद जल संसाधन विभाग में उसका कालीकरण करने का प्रावधान था, लेकिन कुछ कारणवश वहां नहीं हुआ है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसको चंपारण तटबंध, पूरा बहुत बड़ा एरिया है, मेरे एरिया में तो पुछरिया से लेकर भरवलिया टोक तक, दोनों तरफ आबादी है, अगर उसका कालीकरण करा देंगे तो बहुत सारे लोगों का समस्या का निदान हो जाएगा । एक मटयरवा चौक पहाड़पुर में है, वहां से लेकर गहिरी तक वह जुड़ जाएगा तो दो जिला से उसका संपर्क पथ हो जाएगा । एक पी0डब्ल्यू0डी0, पकड़िया में एक रोड है, जहां पर चुनाव के दरम्यान गांव वालों ने वोट का बहिष्कार किया, फिर गए लोग एन0डी0ए0 के पक्ष में मतदान भी किए, वहां एक अनिल पान की दुकान, उससे लेकर नोनिया पोखरा तक, तो महोदय बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं, मैं सरकार के काम से समर्थन करता हूं और बाकी जो काम हैं हमको पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एन0डी0ए0 के नेतृत्व में, मंत्री जी पूरा करेंगे।

महोदय, पिछले दिन सदन में मैं लगातार देख रहा हूं कि नेता, अभी एक सदस्य हैं, जो मेरे नेता संस्थापक श्रद्धेय पद्मभूषण रामविलास पासवान जी के बारे में लगातार बेचारा, बेचारा, बेचारा शब्द, इन लोगों को जंगलराज के नाम से मिर्ची लग जाती है । जंगलराज...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बजट पर अपना महत्वपूर्ण सुझाव दें ।

श्री राजू तिवारी : महोदय, यह जरूरी विषय है महोदय । बार–बार, सुनिए...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आप शांति बनाएं ।

श्री राजू तिवारी : जंगलराज का उपाधि ये माननीय न्यायालय के द्वारा दिया हुआ है...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांति बनाएं ।

श्री राजू तिवारी : ये जंगलराज का उपाधि कोई आम जनता, कोई दल नहीं दिया है महोदय । हमलोग तो श्रद्धेय पद्मभूषण रामविलास पासवान जी के विचारों पर, उनके विचार पर हमलोग राजनीति करने वाले लोग हैं । ये लोग तो मान लीजिए जात–पात, मजहब आपस में टकराहट है...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपने क्षेत्र की समस्या रखें ।

श्री राजू तिवारी : हमारे चिराग पासवान जी कहते हैं कि सीधे एम0वाई0 का मतलब, मेरे नेता बोलते हैं, ये लोग क्या हैं हम नहीं बोलना चाहते हैं लेकिन मेरा नेता स्पष्ट कहते हैं, महिला और युवा की बात करते हैं...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या शांति बनाएं ।

श्री राजू तिवारी : हमारे नेता श्रद्धेय पद्मभूषण रामविलास पासवान जी स्पष्ट बोलते थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं, जहां सदियों से अंधेरा था तो हमलोग समाज के सबसे अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है, उसकी बात करते हैं । महोदय, ये लोग लगातार, इनके दल के नेता, एक तो विपक्ष का आईना गायब है...

उपाध्यक्ष : आपका समय बीतता जा रहा है, माननीय सदस्य । बहुमूल्य सुझाव दीजिए, अपने क्षेत्र की समस्या रखें ।

श्री राजू तिवारी : महोदय, क्षेत्र की समस्या रख दिए । ये लोग लगातार बेशर्मी की इंतहा पार करके बेचारे, बेचारे शब्द के लिए और माफी नहीं मांगे, और तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदल दिए और मूर्ति लगवाने की बात हमलोग करते हैं...

(व्यवधान)

नहीं, हमको बोलने दीजिए । आपका टाईम आएगा तो बोलिएगा ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बोलने दिया जाए उनको ।

(व्यवधान)

श्री राजू तिवारी : महोदय, सर्वजीत जी के पिताजी की जो हत्या हुई, किसके शासनकाल में हुई, ये बता दें...

उपाध्यक्ष : देखवा लेंगे, देखवा लेंगे माननीय सदस्य ।

श्री राजू तिवारी : उसी जंगलराज के शासनकाल में हुई है...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : उनको बोलने दिया जाए, मैं दिखवा लूंगा ।

श्री राजू तिवारी : महोदय, यही इन लोगों की संस्कृति है, यही बोलने पर इन लोगों को बुरा लगता है । सर्वजीत जी के पिताजी की हत्या के बाद हमारे नेता वहां पहुंचे थे...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : टोका–टोकी नहीं करें ।

श्री राजू तिवारी : किसके कार्यकाल में हुई ? 2001 में किसके कार्यकाल में हुई ? महोदय, यह घमंडिया गठबंधन है, यहीं बगल में...

(व्यवधान)

महोदय, इन लोगों का घमंडिया गठबंधन है ...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को बोलने दिया जाए ।

श्री राजू तिवारी : हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं महोदय, मेरा समय जोड़ लिया जाए, मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, हम इनको भी बोलने नहीं देंगे...

(व्यवधान)

हमारे समय को महोदय, नोट करके इनके समय से कटौती किया जाए...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाएं ।

श्री राजू तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, इनको तो...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बगैर आसन के आदेश के नहीं बोलें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठ जाएं ।

श्री राजू तिवारी : महोदय, ये पहली बार सदन में किसके आशीर्वाद से आए हैं ? ये पहली बार श्रद्धेय पद्मभूषण रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद से सदन में मुंह देखे हैं । ये थोड़ा सा इन लोगों को, किसी के प्रति सम्मान रहे तब न महोदय । हमारे बगल में बैठते हैं...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति बनाएं माननीय सदस्य ।

श्री राजू तिवारी : हमारे बगल में ए0आई0एम0आई0एम0 के नेता श्री अखतरूल ईमान साहब बैठकर बोलते हैं । ये घमंडिया, वे तो ढोल लेकर गए और इन लोगों का पोल खोल दिए कि क्या इन लोगों की नीति है, किसी समाज को ये लोग वोट का अपना जरिया मानते हैं, काम तो करते नहीं हैं । मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज के बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कितना काम हुआ है...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बजट पर बोलें ।

श्री राजू तिवारी : ये लोग वोट का जरिया समझते हैं । महोदय, मैं कहता हूं, इन लोगों को पहले हमारे नेता के प्रति जो बयान दिए हैं इनके नेता...

उपाध्यक्ष : आप कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री राजू तिवारी : वे आयें और इसी बहाने सदन में आकर माफी मांगें ।

उपाध्यक्ष : कृपया आप आसन ग्रहण करें ।

श्री राजू तिवारी : इनलोगों को माफी मांगना चाहिए ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मो0 सरवर आलम ।

श्री राजू तिवारी : और मैं आग्रह करूंगा...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : मो0 सरवर आलम, आपके पास में 4 मिनट का वक्त है ।

(व्यवधान)

डिस्कशन नहीं...

श्री मो0 सरवर आलम : सर, इसको बंद कराया जाय । कृपया उपाध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है इस सदन में ।

(व्यवधान)

सदन का समय...

(व्यवधान)

आप बैठ जाएं ।

श्री कुमार सर्वजीत : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा बेचारा शब्द, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, बस ये रामविलास जी का एक मूर्ति सदन के प्रांगण में लगवा दें, हम सदन से माफी मांगते हैं ।

उपाध्यक्ष : आप सरवर आलम जी, अपना भाषण जारी रखें ।

(व्यवधान)

आपका समय बीतता जा रहा है ।

(व्यवधान)

मो0 सरवर आलम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, ग्रामीण कार्य विभाग के बजट पर बहस हो रहा है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य बैठ जाएं । आप अपना भाषण जारी रखें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य शांति बनाएं ।

मो0 सरवर आलम : शुक्रिया महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं ।

मो0 सरवर आलम : सर, हम ऐसी पार्टी से विधायक हैं, जिसे न ही सरकार समझती है और न ही विपक्ष...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाएं । महत्वपूर्ण विभाग पर बात चल रही है ।

मो0 सरवर आलम : सबसे पहले सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज मुझे बोलने का मौका दिया है और मैं उससे पहले, सबसे पहले...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं । आप अपना भाषण जारी रखें ।

मो0 सरवर आलम : अपनी पार्टी सदस्य असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ अपने नेता बिहार सदर अखतरूल ईमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हम जैसे नौजवानों को टिकट दिया और विधान सभा और उसके साथ में अपनी कोचाधामन की तमाम जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे चुनकर विधान सभा भेजा और अपनी बातों को रखने का मौका दिया । सर, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि किशनगंज जिला जो कि बिहार का अंतिम जिला है, जिसे अगर देखा जाए तो एक तरफ से नेपाल और दूसरी तरफ से बंगलादेश ने घेर रखा है और जहां की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और सबसे कम अगर बिहार, हमने सुना है कि बिहार का विकास अगर करना है तो उसमें हर डिस्ट्रिक्ट का विकास होना चाहिए लेकिन किशनगंज एक अत्यंत ही पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जहां का विकास अभी काफी हद तक रूकी हुई है । मैं चाहता हूं कि ग्रामीण विकास कार्य के द्वारा...

उपाध्यक्ष : ग्रामीण कार्य है माननीय सदस्य, ग्रामीण विकास नहीं ।

मो0 सरवर आलम : ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा काफी काम हुआ है बिहार में । मैं उससे संतुष्ट हूं कि काम हुआ है लेकिन सर, हमारे क्षेत्र में, मैं अपने क्षेत्र की अगर बात करूं तो किशनगंज में काफी कामों को अभी होना बाकी है । ...क्रमशः..

.

टर्न–19 / यानपति / 18.02.2026

(क्रमशः)

मो0 सरवर आलम : अध्यक्ष महोदय, 2017 में एक आपदा आई थी किशनगंज में, 2017 की आपदा में काफी पुल–पुलिया रोड ऐसे हैं जो ध्वस्त हुए लेकिन आजतक नहीं बना ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांति बनाएं ।

मो0 सरवर आलम : 2017 के बाढ़ में काफी पुल जिसमें अगर हम जिक्र करें, मजकुरी में एक लायतौर मदरसा के पास एक पुल है, एक मजकुरी में बाबुल टोला जानेवाली सड़क का पुल है । इसी तरह से एक बोहिता का पुल है, एक मौधोहाट का पुल है और सीमांचल के अगर जोकी और अररिया की बात करें तो वहां पर भी काफी ऐसे पुल हैं जो 2017 में ध्वस्त हुए लेकिन अभीतक नहीं बने । उसी तरह बायसी में एक सिमलवाड़ी पुल है जो अब तक नहीं बना है । ग्रामीण सड़क की अगर बात करें तो ग्रामीण सड़क जब बनती है तो उसके साथ साथ एक मेंटेनेंस वर्क भी होता है । एक तो सर बनने में काफी लेट हो रहा है मैं देख रहा हूं कि हमारे क्षेत्र से आये दिन फोन हमारे पास आता है कि कई सड़क जो है, टेंडर हो गया है, काम स्टार्ट हो गया है लेकिन सड़कों को खोदकर के छोड़ दिया गया है । पी0सी0सी0 वर्क हुआ है लेकिन उसमें कालीकरण अब तक नहीं हुआ है, उसको लेकर के आये दिन घटनाएं हो रही हैं, लोग वहां एक्सिडेंट हो रहे हैं, उसमें त्वरित काम कराने की जरूरत है और महोदय, मैं ग्लोबल टेंडर के भी खिलाफ हूं, इसलिए कि ग्लोबल टेंडर की वजह से वहां हमारे क्षेत्र में एक पार्टिकुलर आदमी को 50–60 काम मिल जाता है और वो समय पर उस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं । उससे वहां के हमारे रोजगार में भी फर्क पड़ता है । छोटा–छोटा यूनिट में जब टेंडर हुआ करता था तो हमारे वहां एक रोजगार के भी सृजन की व्यवस्था थी । नौजवानों को रोजगार भी मिलता था और इसको दुबारा लागू करने की जरूरत है । मेंटेनेंस की अगर बात करूं कि पांच साल का जो मेंटेनेंस होता है, वह दो साल में ही रोड की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसमें आप चल नहीं सकते हैं, उसमें ऐसा गड्ढा हो जाता है । उसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है । अगर मैं उसके साथ सबूत अगर मांग रहे हैं तो एक ब्लॉक चौक से हमारे क्षेत्र में ही आता है किशनगंज में, ब्लॉक चौक से गाछपाड़ा जानेवाली सड़क है, उसमें सर अभी पांच साल का मेंटेनेंस बाकी है लेकिन उस रोड की स्थिति ऐसी है कि उसमें आप चल नहीं सकते हैं । अभी माननीय विधायक बोल रहे थे कि क्षमता से अधिक भार वाली गाड़ी के जाने की वजह से, यही कारण ज्यादातर सड़कों की है कि क्षमता से अधिक भार वाली गाड़ी चली जाती है

जिसकी वजह से सड़कों की स्थिति और भी खराब हो रही है । मैं ऐसे ही अगर कन्हैयाबाड़ी से बड़ीजान होते हुए डी0बी0 50 तक एक रोड है, जिसकी स्थिति काफी खराब है । ऐसी ही बहुत सारी सड़कें हैं ।

उपाध्यक्ष : अब आप अपना भाषण संक्षिप्त करें । आपका समय हो गया है । अपने क्षेत्र की समस्या रखें ।

मो0 सरवर आलम : महोदय, अपने क्षेत्र की ही समस्या को कह रहा हूं । सहकारिता विभाग में, खा़द्य आपूर्ति को लेकर के हमारे वहां कई ऐसे ये हैं, जैसे कोचाधामन को अगर लें पिछले वित्तीय वर्ष 20406 मी0ट0 धान के आवंटन का प्रावधान था लेकिन इस बार घटा दिया गया । 13435 मी0ट0 कर दिया गया । 6971 मी0ट0...

उपाध्यक्ष : कृपया आप आसन ग्रहण करें ।

मो0 सरवर आलम : कम करा दिया गया सर । इसीलिए मैं मांग करता हूं कि इसको बढ़ाया जाय ।

उपाध्यक्ष : कृपया आप आसन ग्रहण करें ।

मो0 सरवर आलम : मैं सर भाषण नहीं, मैं मांग कर रहा हूं...

उपाध्यक्ष : आपका समय हो गया ।

मो0 सरवर आलम : गन्ना उद्योग के मामले में किशनगंज की जो जमीन है वो उपयोगजनक है, मैं मांग करता हूं कि वहां पर फैक्ट्री खोली जाय और गुड़ का प्रोसेसिंग यूनिट भी दी जाय । गुड़ हमारे यहां अच्छा बनता है...

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जायं । माननीय सदस्य, श्री अरूण बाबू ।

मो0 सरवर आलम : डेयरी एवं मत्स्य विभाग से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जीविकाओं को 10–10 हजार रुपया...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं कृपया, अरूण बाबू बोल रहे हैं ।

मो0 सरवर आलम : सर, एक मिनट ।

उपाध्यक्ष : नहीं, आपका समय हो गया । आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

मो0 सरवर आलम : ठीक है सर । धन्यवाद ।

श्री अरूण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । समय कम है इसलिए मैं प्वाइंट में अपनी बात रखना चाहता हूं । हम ग्लोबल टेंडर के खिलाफ में हैं चूंकि जो ग्लोबल टेंडर हुआ है उसका परिणाम आना इलाके में शुरू हो गया है । वह जिस उद्देश्य के लिए बना हो लेकिन वह उद्देश्य पूर्ति नहीं कर रहा है । हो सकता है कि एकाध उद्देश्य उसमें पूर्ति होता हो लेकिन काम की गुणवत्ता, समय पर काम, इसकी कहीं भी वह पूरा नहीं करता है । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो बिलो वाली सीमा जो अनलिमिट कर दिया गया है, उससे भी काम की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है । इसलिए बिलो की एक सीमा तय किया जाना चाहिए कि उससे नीचे बिलो नहीं जायेंगे हम । अगर जा रहे हैं तो इसके

बाद क्या होता है । ये अभियंता प्रमुख और प्रमुख जो लोग भी हैं, ये ठेकेदार को बुलाते हैं और कहते हैं कि क्यों इतना बिलो आप डाल दिए, बना कैसे दीजिएगा । तो क्यों यह तरीका अपनाया गया है कि बिलो डालिये, इसका मतलब समझ में नहीं आता है । इसलिए इस बात को, हम यह कहना चाहते हैं कि दलित टोले की जो संपर्कता है इसपर जोर दिया जाना चाहिए । अभी भी दलित टोले एकल संपर्कता पथ से नहीं जुड़ पाये हैं, सुलभ संपर्कता पर पैसे इंवेस्ट होना चाहिए चूंकि यह सुलभ संपर्कता जो पथ है, इससे गांव का और हमारे इलाके का, अपने इलाके का, हर जगह का इससे उस सड़क की उद्देश्य पूर्ति होती है । इसलिए सुलभ संपर्कता पर पैसे इंवेस्ट हों ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अरूण बाबू, आपका समय हो गया ।

श्री अरूण सिंह : बस महोदय, एक मिनट । तीन–चार–पांच क्रमांक सूची जो जिला का है, हमारे यहां पूर्व चयनित किया गया था लेकिन वह नहीं बन रहा है । तीन–चार–पांच पर है जिले की सूची पर । विक्रमगंज ब्लॉक की एक जगह है और वहां नहीं बन रहा है । हम मंत्री जी से चाहेंगे कि इसको करें और एक पॉलिसी और बनवायें कि जो हम हर गांव को सड़क से जोड़ रहे हैं, पंचायत मुख्यालय से पंचायत के हर गांव को जोड़ा जाय...

उपाध्यक्ष : अब आप आसन ग्रहण करें ।

श्री अरूण सिंह : तो गांव के पथ को सुलभ बनाया जा सकता है, गांवों के आवागमन को सुलभ बनाया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष : आपका समय हो गया है । आप कृपया बैठ जायं ।

श्री अरूण सिंह : इसे लिया जाना चाहिए । पांच वर्ष, सात वर्ष, यह जो कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं, हम गए थे निर्माण के काम को देखने के लिए निरंजनपुर अपने गांव में, इलाके में गए थे । टेंडर, जो ठेकेदार है नीचे बिना चमकी डाले हुए ढलाई कर रहा है । हम गए एक दिन सोहदा में तो अभी काम चल रहा है, पूरा सड़क ही वह उघड़ गया...

उपाध्यक्ष : कृपया आप बैठ जायं ।

श्री अरूण सिंह : इसको आप ठीक कीजिए और पांच साल वाला जो था वह ठीक था ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अजय बाबू, एक मिनट का वक्त है ।

श्री अजय कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हूं । यह सही है कि तीन हजार कि0मी0 जिसकी चर्चा बराबर माननीय मंत्री जी करते हैं लेकिन उसकी गुणवत्ता की भी चर्चा होनी चाहिए । मैं आपको बताना चाहता हूं कि नई कालीकरण रोड जो बनाते हैं उसमें कालीकरण का जो है वह सिर्फ 20 एम0एम0 है और एम0आर0 का जो है सिर्फ 25 एम0एम0 है और जब 25 एम0एम0, 20 एम0एम0 का होगा वह रोड कितने दिन चलेगी । सात वर्ष का आप दे दिए

हैं उसको ठीक है कि सात वर्ष तक वह करते रहेगा, मरम्मत करते रहेगा और फिर पी0सी0सी0 जो है इनका सिर्फ 5 इंच का है । जिला परिषद् से जो रोड बनता है वह 8 इंच का बनता है और बिहार सरकार जो बना रही है वह पांच इंच का । यह मेरी समझ में नहीं आता है कि इनका एस्टीमेट क्या बिहार सरकार जो बना रही है वह कैसा एस्टीमेट बना रही है । दलित बस्ती को संपर्क पथ के लिए 13814 इन्होंने चिन्हित किया है और स्वीकृत ये कितना किए हैं, 3494 मतलब अभी इनको पांच साल में अगर इतना किए हैं तो 15 साल लगेगा पूरा दलित बस्ती को संपर्क पथ से जोड़ने में और दूसरी एक बात हम कहना चाहते हैं दलित बस्ती के लिए संपर्क पथ बनाने के लिए जमीन के लिए दो चीजें हैं इनके साथ, सतत् लीज या अधिग्रहण का, सतत् लीज का मतलब है कि कोई किसान अपनी स्वेच्छा से जमीन देगा तब उसपर सड़क बना सकते हैं ये और किसी दलित को कोई स्वेच्छा से जमीन देता है सड़क बनाने के लिए, नहीं देता है, इसलिए इसपर अधिग्रहण नीति लायें, स्टैंडिंग ऑर्डर में लाना चाहिए तभी आप दलित को सड़क दे सकते हैं ।

म्होदय, सहकारिता विभाग के बारे में हम कहना चाहते हैं धान के लिए जो आपने लक्ष्य रखा था, 50 से 60 प्रतिशत ही धान खरीदे गए हैं, एफ0आर0के0 का अभीतक एक बड़ा प्रॉब्लम है । माननीय मंत्री जी दौड़कर गई थीं कि दिल्ली जाकर हम बात करके इसको करेंगे । हमारा कहना है कि इसमें...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री अजय कुमार : हम 30 सेकंड ले रहे हैं । मेरा कहना है कि किसानों के हित को देखते हुए आप सहकारिता से जो खरीदते हैं धान, उसको टाइम बढ़ाइये और वास्तविक किसानों के धान खरीदे जायं, ये व्यवस्था करनी चाहिए । डेयरी के लिए भी हम कहना चाहते हैं कि डेयरी में, डेयरी दूध उत्पादक जो किसान हैं लागत खर्च बढ़ गया है, उत्पादित दूध जो है उसकी कीमत नहीं मिल रही है। नतीजा होता है कि उसकी जिंदगी खराब हो रही है इसलिए दूध की कीमत का निर्धारण जो है आपको ठीक से करना चाहिए...

उपाध्यक्ष : कृपया बैठ जायं ।

श्री अजय कुमार : ताकि दुग्ध उत्पादक किसानों की स्थिति अच्छी हो सके । धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : अजय बाबू, कृपया आसन ग्रहण करें । माननीय सदस्य, श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता जी । एक मिनट ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : सर, आज करूआ तेल लगाकर नहीं आए हैं, एक मिनट थोड़ा और दे दीजिएगा हमको । अभी मैं माननीय सदस्यों को सुन रहा था, सारे सदन के माध्यम से I want to wish Mr. Minister who has become a Professor, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सर आपको ।

(क्रमशः)

टर्न–20 / मुकुल / 18.02.2026

क्रमशः

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : लेकिन जिस चीज को आपलोग ग्लोबल टेंडर बोल रहे हैं, बेसिकली वह क्लबिंग ऑफ टेंडर्स हैं और उसकी वजह से भाजपा, जदयू के कार्यकर्ता लोग खासे नारा हैं इनको ज्यादा घाटा है, क्योंकि इनके जो लोग हैं, जो ठेकेदार थे छोटे–छोटे, बेचारे काम करते थे वे बेरोजगार हो गए और मंत्री जी मैं सीरियसली बता रहा हूं कि This is leading to migration यह बढ़ रहा है, माइग्रेशन बढ़ रहा है इससे, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो छोटे–छोटे ठेकेदार थे, कार्यकर्ता थे वे बेरोजगार हो गये हुजूर, इस क्लबिंग ऑफ टेंडर को हटाइये । दूसरा मैं कहना चाहता था कि Standard bid documents और सी0वी0सी0 की गाइडलाइन है कि Abnormally Highly Quoted Price, Abnormally below Quoted Price आप उसे नहीं अलाउ कर सकते, लेकिन आपने इन दोनों प्रॉविजन को एस0बी0डी0 और सी0वी0सी0 के प्रॉविजन को कैबिनेट के डिसीजन से डायलूट कर दिया है, इसके दो मतलब होते हैं अगर Highly below Quoted price को अलाउ कर रहे हैं 25 परसेंट तक, इसका मतलब यह है कि आप किसी न किसी रूप में एस्टीमेट को इन्फीलिएट करने की कोशिश करते हैं कि एज्यूमिंग कि 25 परसेंट बिलो जायेगा, इसका मतलब यह हुआ कि आपके जो इंजीनियर एस्टीमेट बना रहे हैं, 25 परसेंट हाइक करके बना रहे हैं इसका मतलब यह है कि राजस्व को घाटा दे रहे हैं । मैं चाहता हूं कि आप इसको ऐसा कीजिए, अब 25 परसेंट बिलो हुआ और 40 परसेंट कम्परमाइज फॉर्मल सिस्टम भी होता है यानी 65 परसेंट हो गया हुजूर और 30 परसेंट में कैसे क्वालिटी वर्क आप करेंगे । इसको जो मैं कहता हूं, कैबिनेट से अगर डिसीजन लिया गया तो इसको रोल–बैक होना चाहिए और मैक्सिमम बिलो 10 परसेंट पर लाना चाहिए, This is a very serious concern. दूसरा जो ग्लोबल टेंडर की बात कर रहे हैं, जब आप ग्लोबल टेंडर की बात कर रहे थे ।

उपाध्यक्ष : इंद्रजीत बाबू, आपका समय हो गया ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : बेसिकली ये ग्रुपिंग टेंडर करते हैं, बड़ा–बड़ा, छोटा–छोटा टेंडर को कर दिया, एक आदमी को दे दिया ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाएं ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : लेकिन जो ग्लोबल टेंडर है उसमें क्या करता है कि बिहार की ही कम्पनी, भारत की ही कम्पनी एल0एल0पी0 बनाकर....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, एल0एल0पी0 बनाकर ग्लोबल टेंडर का नाम दे देते हैं और घूमा–फिराकर 65 परसेंट पैसा यहां, 35 परसेंट विदेश चला जाता है, क्यों पैसा विदेश जायेगा ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप बैठ जाएं ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, मेरी एक आखिरी मांग है, मैं तो जानता हूं कि आप मुझे समय नहीं दीजिएगा ।

उपाध्यक्ष : आप ढाई मिनट बोले हैं, ढाई मिनट से ज्यादा बोले हैं ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, मंत्री जी से एक मांग है, यह जमुई जाते हैं, वहां एन0एच0 बनने वाला था एक्यूजिशन ऑफ लैंड के प्राइस हाइक होने की वजह से वह कैंसिल हो गया । मैं चाहता हूं कि पतनेश्वरनाथ से दौलतपुर जो मेरे गांव होकर ब्रिज जाता है उसको बनवा दीजिए, उससे सैकड़ों जमीन उपजाऊ हो जायेगा और आपका पैसा बन जायेगा । बहुत–बहुत धन्यवाद । Thank You very much.

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सतीश कुमार सिंह यादव जी । आपके पास 1 मिनट का वक्त है ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय । मैं ग्रामीण कार्य विभाग में नीचे के अधिकारी और संवेदकों द्वारा मिलीभगत से भ्रष्टाचार की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । महोदय, प्रखंड नुआव के टी–03 से गोरियारी तक का सड़क का निर्माण डेढ़ महीना पहले स्टार्ट हुआ था । महोदय, ग्रामीणों ने हमें सूचना दी कि सड़क का निर्माण बहुत खराब हो रहा है, मैंने खुद जाकर वहां निरीक्षण किया और निरीक्षण में हमने पाया कि कालीकरण हाथ से उखाड़ने पर उखड़ जा रहा था । हमने वहां से कार्यपालक अभियंता को फोन किया और जानकारी दी कि इसकी जांच की जाए, आज तक उसकी जांच नहीं की गयी, कई बार कार्यपालक अभियंता को हमने जानकारी दी । इसके बाद जब नहीं जांच हुई तो मैंने माननीय मंत्री महोदय के कार्यालय में 10 जनवरी को लेटर दिया, लेकिन आज तक उस सड़क की जांच नहीं हुई । वैसे ही हमारे यहां खजुरीघाट से कैरम गांव का रोड और नाला का निर्माण बहुत घटिया क्वालिटी का हुआ है । महोदय, अग्नि मुस्लिम टोला की सड़क और नाला निर्माण, कस्तरी पथ से मटिहारी गांव का सड़क निर्माण । महोदय, संवेदक और कार्यपालक अभियंता मिलकर ग्रामीण कार्य विभाग के सड़कों का बंटाधार कर रहे हैं महोदय, इसकी जांच जो है पटना की टीम से करायी जाए, जिले की टीम से न करायी जाए । साथ ही महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से अपने इलाके की कुछ मांगों को रखना चाहता हूं, हमारे यहां रामगढ़ बरौरा पथ से जोरार दलित टोला है, जो एक हजार की बस्ती है लेकिन जमीन जो है निजी जमीन होने के कारण महोदय आज तक उस सड़क का निर्माण नहीं

हुआ । उसी तरह कल्याणपुर गजनपुरा टोला, दलित टोला है आबादी 500 है लेकिन निजी जमीन के चलते निर्माण नहीं हो पाता है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय हो गया है ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि भूमि अधिग्रहण करके उस जगह निर्माण कराया जाए ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, 10 सेकंड । साथ ही, चंडेस के बगल में गोरियारी नदी पर पुल का निर्माण और सोतवा में धर्मावती नदी पर पुल का निर्माण, नरहन में दुर्गावती नदी पर पुल का निर्माण कराया जाए और विप्रान गांव के सामने बाढ़ के समय वह गांव घिर जाता है, वहां पुल का निर्माण कराया जाए । धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी जी । आपके पास 4 मिनट का वक्त है ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : बहुत–बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय । आज ग्रामीण कार्य विभाग का बजट है हम इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुए हैं और कहेंगे कि हमलोगों का क्षेत्र जो सिकंदरा विधान सभा है कालांतर में वह उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था इस कारण से वहां पिछड़ा हुआ अभी भी है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करेंगे कि वहां कई ऐसे आदिवासी गांव हैं जहां तक पहुंच पथ नहीं बनी है या तो पहुंच पथ नहीं बनी है या वहां अगर पहुंच पथ गयी है तो पुल के कारण वे लोग अभी भी नदी और जोहरी से टपकर जाते हैं जिससे काफी परेशानी होती है, इसलिए हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि पंचायत गोली, ग्राम–मुड़बरो के दक्षिण तरफ पिपरा खाड़ नदी पर पुल का निर्माण अगर करा दिया जाए तो उस पार के जो लोग हैं उनको आने–जाने में काफी सुविधा होगी, आर्थिक विकास होगा, शिक्षा की दीप जलेगी और युवाओं को काम मिलेगा । इसी प्रकार से हम कहना चाहेंगे पंचायत–फतेहपुर विशनपुर के ग्राम–फतेहपुर से बड़ा बांध के बीच कियुल नदी पर अगर पुल बनाया जाए, वे लोग अभी 13 कि0मी0 घूमकर आते हैं, अगर पुल बनता है तो वह दूरी घटकर 2 कि0मी0 में परिणत हो जायेगा । इसी प्रकार से हम कहेंगे केरबातरी गांव है जो प्रखंड–खैरा में है, आदिवासियों का गांव है, बीच में कियुल नदी पड़ता है उसके बाद जथर गांव पड़ता है वह भी आदिवासियों का गांव है, अगर वहां केरबातरी और जथर गांव के बीच, आदिवासी का जो गांव है कियुल नदी पर अगर पुल बना दिया जाए तो उससे उन लोगों को काफी सुविधा होगी । इसी प्रकार से हम कहना चाहेगे, हाड़ोडीह से अमकोली तक जो आदिवासियों का गांव है बीच में वन विभाग की कुछ जमीन है, वहां पर अभी तक पक्की रोड का

निर्माण नहीं किया गया है, आज वन एवं पर्यावरण का भी बजट है उसमें हम कहेंगे चूंकि मेरा क्षेत्र पहाड़ी और पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है वहां बहुत सारा ऐसा स्पॉट है अगर उसका विकास किया जाए, अगर उसे पर्यटक स्थल के रूप में परिणत किया जायेगा तो उससे युवाओं को काम मिलेगा, वह क्षेत्र समृद्ध होगा और सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी । उसी में हम कहना चाहेंगे उड्डुआ पहाड़ जिस पर औलिया पीर का एक मजार है, वहां सप्ताह में तीन दिन मेला लगता है, हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, राजस्व भी वहां खूब होता है । अगर उसको पर्यटन का क्षेत्र बना दिया जाए, उसी के बगल में कैलाश डैम है तीन तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, सौंदर्य से परिपूर्ण है, अगर उसे वन विभाग की ओर से पर्यटक क्षेत्र बनाया जाए तो निश्चित रूप से राजस्व की प्राप्ति होगी युवाओं को काम मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा । ठीक उसी प्रकार से हम कहना चाहेंगे कुंड डैम का निर्माण किया गया है, कुंड डैम और भगवान महावीर की जन्मस्थली सात पहाड़ के पार है, कुंड घाट और भगवान महावीर की जन्मस्थली के बीच 11 कि0मी0 का जंगली क्षेत्र है जहां पी0डब्ल्यू0डी0 का निर्माण किया गया है, बहुत सारे ऐसे जगहें हैं, अगर उनको पर्यटक क्षेत्र बनाया जाए तो वहां खासा विकास होगा, युवाओं को काम मिलेगा लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ सरकार को हजारों की राजस्व की प्राप्ति होगी । महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि निश्चित रूप से अगर कुंड घाट और भगवान महावीर की जन्मस्थली के बीच इस तरह का काम किया जाए, पर्यटक क्षेत्र बनाया जाए तो वहां से राजस्व अधिक मात्रा में आयेगा और साथ ही साथ हम माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करेंगे कि ग्लोबल टेंडर की बातें हो रही हैं, ग्लोबल टेंडर में सिकंदरा बाजार है हमलोगों का, सिकंदरा बाजार से मिसन चौक तक.....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय हो गया है ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : उपाध्यक्ष महोदय, बस 1 मिनट । हम कुछ ही बात करेंगे कि सिकंदरा बाजार का जो रोड जर्जर है ग्लोबल टेंडर में आया हुआ है पिछले 7 जून को ही उसका बोर्ड लगा है, अभी तक नहीं बनाया गया है । महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि उसको अगर दिखवा लिया जाए, बनवा लिया जाए तो बहुत कृपा होगी । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

टर्न–21 / सुरज / 18.02.2026

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार सिंह । आपके पास तीन मिनट का वक्त है।

श्री आलोक कुमार सिंह : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय । मैं ग्रामीण कार्य विभाग की अनुदान मांगों पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि ग्रामीण कार्य विभाग पर बुनियादी जरूरत सड़क, पुल, संपर्क और विकास को प्राथमिकता दी है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमलोग 2005 के पहले वह दृश्य देखें हैं । हम कैमूर जिला के मोहनिया प्रखंड के बगडीह पंचायत से आते हैं जहां से हमलोग विधान सभा और विधान परिषद में एक संगीता देवी जी, एक मैं और संतोष कुमार सिंह निर्वाचित हुये थे । 2005 के पहले हमलोग पैदल हॉफ पैंट पहनकर जाते थे बस पकड़ने के लिये और आज धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कि वहीं मेरे गांव में आज स्कूल खुला है । बोर्डिंग स्कूल, प्राईवेट स्कूल से बस आती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की केवल योजनाएं नहीं देखी, बिहार ने एक युग के परिवर्तन को देखा है ।

कभी बिहार की शामें डर से सिमट जाती थी
आज बिहार के सुबह विकास के विश्वास से खुलती है
जहां पहले लोगों की चिंता थी कि घर से सुरक्षित रहें
आज लोगों की आकांक्षा है कि गांव आगे बढ़े ।

यह परिवर्तन केवल शब्दों में नहीं, यह बिहार की सड़कों, पुलों और गांवों की तस्वीर में साफ दिखाई देता है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिनारा विधान सभा से निर्वाचित हुआ हूं और ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव से मैंने बात किया । जहां तक सड़क मेंटेनेंस की बात आती है । कुल दिनारा विधान सभा में 82 रोड का निर्माण हुआ है जिसकी अवधि कहीं 26, 28, 30 तक है । जैसे ही मैंने उन्हें पत्र लिखा उन्होंने सारा विवरण दिया और धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री महोदय को कि समय पर, उन्होंने कहा कि माननीय विधायक जी कहीं भी ऐसा अगर आपको शिकायत आये, रोड खराब हो तो जरूर बतायेंगे । एक इसके बाद इसमें मैंने देखा कि आज सहकारिता भी है । तो सबसे पहले रोहतास और कैमूर शाहाबाद के होने के नाते संयोग ऐसा है कि जब मुझे बोलने का मौका मिला माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हुये हैं, माननीय सहकारिता मंत्री जी भी बैठे हुये हैं, माननीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री जी भी बैठे हुये हैं । रोहतास, कैमूर में धान का कटोरा कहे जाने वाले दो एफ0आर0के0 एजेंसी वहां नियुक्त हुई है । माननीय मंत्री जी का आज हमने अखबार में भी देखा कि गृह मंत्री जी से उन्होंने दिल्ली में मुलाकात की । लेकिन अब 25 तारीख को धान की खरीदारी का अंतिम डेट है और एफ0आर0के0 खुलेआम दो एजेंसी 50 रुपए क्विंटल प्रति पैक्स से डिमांड कर रहा है । जिसको पैसा मिलता है, उसको ही एफ0आर0के0 देता है । ऐसी जहां माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में, जहां

मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि न हम किसी को फंसाते हैं, न बचाते हैं । आज तीनों माननीय मंत्री जी बैठे हुये हैं । किसान से धान खरीदारी होती है । पैक्स से किसान धान बेचते हैं, पैक्स से धान की खरीदारी होती है और चावल के रूप में माननीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री जी को एस0एफ0सी0 प्राप्त होता है । इसके बाद एफ0आर0के0 जैसे आज रोहतास, कैमूर में 80 परसेंट का लक्ष्य, 100 परसेंट का लक्ष्य मात्र 40 परसेंट है । किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है, चावल नहीं गिरने के कारण । यह इतना ज्वलंत मुद्दा है और हमलोग एन0डी0ए0 सरकार में हैं । माननीय मंत्री जी का प्रयास है, माननीय तीनों मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि इसको जितना जल्दी हो, इस ज्वलंत मुद्दा को अगर हमलोग निष्पादन नहीं करायेंगे...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका समय हो गया है ।

श्री आलोक कुमार सिंह : महोदय, लास्ट में एक चीज अपने दिनारा विधान सभा में ग्रामीण कार्य विभाग के माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि दिनारा विधान सभा में कुंजग्राम में एक पुल नहीं बनने की वजह से दो हजार बीघा जमीन में पानी जमा होता है । माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वहां पुल का निर्माण करा दें ताकि किसान का...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब आसन ग्रहण करें ।

श्री आलोक कुमार सिंह : अंत में ग्रामीण कार्य विभाग पर माननीय मंत्री जी को मैं बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरे गांव का रोड भी बना और...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : बिना आसन के आदेश के न बोलें । इनको बोलने दिया जाए ।

श्री आलोक कुमार सिंह : बात हुआ ग्लोबल टेंडर का तो सब चीज में एजेंसी है । आज सरकार जिस तरह से रोड का निर्माण कर रही है...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री आलोक कुमार सिंह : आज हमलोग पटना से जाते हैं ढ़ाई घंटे में अपने गांव पहुंच जाते हैं । पुनः...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठ जाएं ।

श्री आलोक कुमार सिंह : ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि मैंने अपने विधान सभा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात किया, एक रोड खराब था तत्काल उन्होंने 24 घंटे के अंदर उस पर काम लगाया । इन्हीं शब्दों के साथ पुनः माननीय ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जी आप इसी तरह से बढ़ते रहें और बिहार के विकास की गाथा लिखते रहें जहां बसावट के टोले की बात होती है.. .

उपाध्यक्ष : बैठ जाएं माननीय सदस्य ।

श्री आलोक कुमार सिंह : तो निश्चित तौर पर आज कोई भी विधान सभा में मैंने देखा कि हर विकास के टोले में रोड बन रहा है और...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आसन ग्रहण करें ।

श्री आलोक कुमार सिंह : बाकी अनुशंसा मांगी गयी है हमलोगों से पुनः मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से ग्रामीण कार्य विभाग के अनुदान मांगों पर समर्थन करता हूं । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य की जानकारी में कि आज पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, गन्ना उद्योग महत्वपूर्ण विभाग है । आपके बहुमूल्य सुझाव सरकार को मिलना चाहिये । अब माननीय सदस्य श्री संजय कुमार पाण्डेय जी । आपके पास आठ मिनट का वक्त है ।

श्री संजय कुमार पाण्डेय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मुझे मौका देने के लिये आपको बहुत–बहुत धन्यवाद । मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी एवं श्री विजय कुमार सिन्हा जी सहित सदन के सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं । मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की महान देवतुल्य जनता को भी नमन करता हूं जिनके भरोसे के कारण मैं इस सदन में इतने महान विभूतियों के बीच खड़ा हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष जी इस हेतु मुझे आपके संरक्षण की भी आवश्यकता होगी ।

महोदय, वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना एवं अर्थव्यवस्था के विकास हेतु ग्रामीण कार्य विभाग के प्रस्तावित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना सहित अन्य योजनाओं के माध्यम से सभी गांव, पंचायत में सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन की गति को और बढ़ाने का लक्ष्य रखा है ।

महोदय, जब 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधार नीतियों के तहत आर्थिक उदारीकरण प्रारंभ हुआ । इससे हमारा आर्थिक विकास दर तो बढ़ गया परंतु इसका मुख्य रूप से लाभ शहर तक ही सीमित रहा और इसका लाभ हमारे भारत के गांव के किसान, गरीब, पिछड़ा तक कम पहुंचा । अतएव एक नई चर्चा छिड़ गई । भारत और इंडिया के बीच बढ़ती दूरी । अमीर और अमीर हो रहा था, गरीब और गरीब ।

महोदय, उसी अवधि में सत्ता में बैठे कुछ लोग बिहार में खुलेआम बेशर्मी से नारे लगा रहे थे कि रोड बनी त एक्सीडेंट बढ़ी और हमार वोटर साईकल से चले ला, ओकरा का कौनो गाड़ी बा, जे रोड के जरूरत बा । श्रीमान इनलोगों की गरीबों को गरीब रखने की इस साजिश को तोड़ने एवं गांव एवं शहर के बीच की दूरी को कम करने धूमकेतु की तरह आई हमारे श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क येाजना ।

महोदय, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 25 दिसंबर, 2000 को ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क रहित बस्तियों को एक ही ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड

अर्थात बारहमासी सड़क के जरिए पूरे साल सड़क संपर्क देने के मकसद से शुरू किया गया था ताकि ग्रामीण आबादी की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके ।

महोदय, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एन0डी0ए0 की सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–I के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 53594.09 कि0मी0 लंबाई का पथ एवं 1163 पुल का निर्माण ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना– II अंतर्गत 2456.47 कि0मी0 ग्रामीण पथों के उन्नयन एवं 102 पुलों का निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना– III के अंतर्गत 6162.71 कि0मी0 ग्रामीण पथों के उन्नयन एवं 709 पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है । शेष सड़कें एवं पुलों का कार्य प्रगति में है । यह हमारे मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का दिन है ।

महोदय, इस योजना से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं तक पहुंच में खासा सुधार हुआ है । कृषि और गैर कृषि दोनों क्षेत्रों में रोजगार पैदा हुए हैं और किसानों को अपनी उपज के बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाया है।

महोदय, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना से ना सिर्फ वामपंथी उग्रवाद में भारी कमी आई है, बल्कि बाजारों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच से इन दूरस्थ और संवेदनशील इलाकों में सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है ।

...क्रमशः....

टर्न–22 / धिरेन्द्र / 18.02.2026

...क्रमशः....

श्री संजय कुमार पाण्डेय : उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष) से राज्य के सभी जिलों में छूटे हुए 13,815 बसावट में अब तक 6,083 बसावट के संपर्कता हेतु कुल लंबाई 8,095 किलोमीटर पथ की स्वीकृति प्रदान करते हुए 1,885 पथ कुल लंबाई 1,993 किलोमीटर के निर्माण का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है । शेष पथ निर्माण के विभिन्न चरणों में है । महोदय, वित्तीय वर्ष 2026–27 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस योजना अंतर्गत कुल 3,000 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों के निर्माण का लक्ष्य सरकार ने रखा है । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एन॰डी॰ए॰ की सरकार द्वारा ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत अब तक कुल 18,115 ग्रामीण पथ जिनकी लंबाई 30,964 किलोमीटर है, कुल राशि 27360.35 करोड़ रुपये के पुनर्निर्माण / उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के द्वारा प्रदान की गयी है। शेष

वित्तीय वर्ष 2026–27 में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है । महोदय, इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एन॰डी॰ए॰ की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के अंतर्गत अबतक कुल 909 पुल की स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है । महोदय, सुलभ संपर्कता योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में निर्बाध यातायात हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 72 योजनाओं का चयन किया गया है, जिसमें 65 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति कुल राशि 356.43 करोड़ प्रदान की गई है । महोदय, अब मैं वित्तीय वर्ष 2025–26 के कार्यक्रमों की प्रगति का उल्लेख करना चाहता हूँ । मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना के अंतर्गत कुल 616 किलोमीटर पथ एवं 181 पुलों का निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कुल 983.83 किलोमीटर पथों का निर्माण, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम के तहत कुल 2,351 किलोमीटर पथ का निर्माण, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अंतर्गत कुल 1,250 किलोमीटर के पथ का उन्नयन, ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 8,441 किलोमीटर के पथ का पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण किया गया है । शेष का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है । उपाध्यक्ष महोदय, ये सारी उपलब्धियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी के नेतृत्व में एन॰डी॰ए॰ की सरकार के द्वारा किया जा रहा है ।

महोदय, ग्रामीण पथ जो एस॰एच॰/एन॰एच॰/एम॰डी॰आर॰ को सीधे तौर पर जोड़ते हों, उन ग्रामीण पथों को चिन्हित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर intermediate/double lane में परिवर्तित किया जा सकेगा । पर्यावरण की स्वच्छता एवं हरियाली हेतु प्राक्कलन में पथ के किनारे वृक्षारोपण का प्रावधान तथा पथ में कालीकरण किए जाने हेतु वेस्ट प्लास्टिक 7–8 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है । महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से जीत कर आता हूँ वहां की कुछ समस्याएं हैं, इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि बेलवनीया ग्राम के मनीयारी नदी पर बने उच्चस्तरीय पुल से गोपालपुर–हैसवा मुख्य सड़क तक जाने वाली सड़क कच्ची है, जिसका निर्माण अत्यावश्यक है, उसकी लंबाई 2.25 किलोमीटर है। इस तरह से तीन–चार ऐसे काम हैं, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत–बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामानन्द मंडल जी । आपके पास दस मिनट का वक्त है।

श्री रामानन्द मंडल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और साथ ही गरीबों के मसीहा और हम सबों के नेता और बिहार के विश्वकर्मा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ । साथ ही हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय जी का, श्री विजय बाबू जी का, हमारे ग्रामीण कार्य मंत्री महोदय का और सभी माननीय मंत्री महोदय का भी आभार प्रकट करता हूँ

और साथ–ही–साथ सदन में उपस्थित हमारे सभी माननीय सदस्यगण का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ । साथ–ही–साथ हम सूर्यगढ़ा विधान सभा के देवतुल्य जनता का भी सदन के माध्यम से उनका भी आभार प्रकट करता हूँ क्योंकि उनके आशीर्वाद से आज इस सदन में मैं उपस्थित हुआ हूँ । आज हमें ग्रामीण कार्य विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का जो मौका मिला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं पूरे विश्वास और दृढ़निश्चय के साथ ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ । यह दस्तावेज केवल योजनाओं का संकलन नहीं है बल्कि बिहार के गांवों की तकदीर बदलने का रोड मैप है । यह विकास की वह तस्वीर है जिसे कच्चे रास्तों की जगह सुदृढ़ मार्ग है, टूटी पुलियों की जगह मजबूत सेतु है और अलग–थलग बस्तियों की जगह सतत संपर्क सूत्र है । अभी तो सब हैं नहीं, एक हमारे बहुत, हम जानते थे शायद वे चली गईं, सदस्य महोदया थीं, वे वर्ष 2024 में मुंगेर लोकसभा चुनाव लड़ने गई थीं वहां जातिवाद का भेद–भाव का इतना जहर बो दी थी लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो विकास हुआ है, वहां उससे प्रभावित हो कर माननीय मुख्यमंत्री जी के समर्थन में समर्पण हो कर वहां के हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय को जिताने का काम किया और उनको नकार कर वहां से भगाने का काम किया, यह है माननीय मुख्यमंत्री जी की देन । पूरे बिहार में जो विकास हो रहा है..

(व्यवधान)

क्या बात करते हैं, आप थोड़ा–सा...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया टोका–टोकी नहीं करें । बैठे–बैठे नहीं बोलें, टोका–टोकी नहीं करें ।

श्री रामानन्द मंडल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के माध्यम से हजारों बसावटों को जोड़ा गया है । सैंकड़ों किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका है और शेष कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं । वर्ष 2026–27 में भी 3,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण पथ निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है । यह संकल्प बताता है कि सरकार गांव को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है । प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गई हैं । 53 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण हो चुका है । हजारों पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है तथा शेष कार्य विभिन्न चरणों में जारी है । यह केवल आंकड़ा नहीं बल्कि लाखों ग्रामीण परिवारों के जीवन में आयी सहूलियत का प्रमाण है । मुख्यमंत्री पथ अनुरक्षण कार्यक्रम के तहत हजारों किलोमीटर मार्गों का पुनर्निर्माण और उन्नयन किया गया है । 18 हजार से अधिक पथों के रख–रखाव और सुदृढ़ीकरण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है । इससे यह स्पष्ट है कि सरकार केवल नयी सड़कें नहीं बना रही है बल्कि पूर्व में निर्मित मार्गों को भी बेहतर स्थिति में

बनाये रखने के लिए संकल्पित है । मुख्यमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत अब तक 900 से अधिक पुलों की स्वीकृति दी जा चुकी है, अनेक सेतु निर्माणाधीन हैं । जिन क्षेत्रों में कभी बरसात के दिनों में आवागमन ठप हो जाता था वहां अब स्थायी पुलों से यातायात संभव हो रहा है । यह बदलाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दे रहा है । मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अंतर्गत हजारों किलोमीटर पथों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया गया है । आगामी वित्तीय वर्ष में भी व्यापक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं । दो लेन चौड़ीकरण की पहल यह दर्शाती है कि सरकार भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आधारभूत ढांचे को आधुनिक स्वरूप दे रही है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपने क्षेत्र की समस्या रखें ।

श्री रामानन्द मंडल : महोदय, सुलभ संपर्कता योजना में कई काम हो रहे हैं....

(व्यवधान)

समस्या है, बतायेंगे । आप धैर्य रखिये । आपलोग तो पुराने हैं, हम नये आये हैं।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, टोका–टोकी नहीं करें ।

टर्न–23 / अंजली / 18.02.2026

श्री रामानन्द मंडल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के कुछ साथी अक्सर यह कहकर शंका प्रकट करते हैं कि विकास कागजों तक सीमित है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे–वे गांव जाकर देखें जहां पहले धूल और कीचड़ था, वहां अब पक्की सड़क है । जहां पहले नाव ही सहारा थी वहां अब मजबूत पुल हैं, जहां पहले अलगाव था वहां अब संपर्क है । ग्रामीण अवसंरचना की किसी भी राज्य की प्रगति की रीढ़ होती है सड़क और पुल, केवल निर्माण कार्य नहीं बल्कि आर्थिक उन्नति, सामाजिक समावेशन और शिक्षा, स्वास्थ्य तक पहुंच का माध्यम होता है । जब किसान अपनी उपज समय पर बाजार तक पहुंचाता है, जब छात्र सुरक्षित विद्यालय पहुंचते हैं, जब मरीज शीघ्र अस्पताल पहुंचते हैं, तभी विकास का वास्तविक अर्थ सामने आता है । अतः मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि...

उपाध्यक्ष : अपना भाषण समाप्त करें माननीय सदस्य । माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

श्री रामानन्द मंडल : एक मिनट दिया जाए महोदय । यह प्रतिवेदन बिहार के ग्रामीण भविष्य का सशक्त नींव है और यह दूरगामी सोच मजबूत इच्छा शक्ति के निरर्थक प्रयास का परिणाम है ।

उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइए, आपका समय हो गया है । माननीय सदस्य, श्री बाबुलाल शौर्य। श्री बाबुलाल शौर्य जी ।

श्री बाबुलाल शौर्य : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे ग्रामीण कार्य विभाग एवं पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं अन्य जैसे गंभीर अति संवेदनशील मामले पर बोलने का समय दिया है, जो बिहार के सभी निवासियों को प्रभावित करता है । इसके साथ ही मैं अपनी पार्टी लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी पार्टी का विचार सदन में रखने और सदन के माध्यम से समस्त बिहार तक पहुंचाने के लिए मुझे चुना है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं एन0डी0ए0 घटक दल के सदस्य की भूमिका में मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के समर्थन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका और सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं–

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

''जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का,
फिर देखना फिजूल है कद आसमान का,
डरना नहीं यहां तू किसी भी चुनौती से,
बस तू ही सिकंदर है सारे जहान का,
सिर्फ तू ही सिंकदर है सारे जहान का ।''

अध्यक्ष महोदय, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, जिसके हौसलों की प्रशंसा हमारे विरोधी भी करते रहते हैं । हमारी सरकार नई चुनौतियों से डरती नहीं है, बल्कि उन चुनौतियों को पार करने के लिए जरूरी संसाधन जुटाती है और हर बार एक नया इतिहास रचती है और इसलिए जनता हमारी सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही एन0डी0ए0 सरकार को बारंबार आशीर्वाद देकर हमारे हौसलों को नई ऊंचाई देती है और इसी हौसले से हमारी सरकार बिहार में विकास के लिए नई योजनाओं के इतर सुधार का भी कार्य करती है ।

(व्यवधान)

चुरचुरो और मुरमुरो की राजनीति छोड़िए न जनाब । आपलोग...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया आपस में बात न करें । शौर्य जी, आसन की ओर देखकर बोलिए ।

श्री बाबुलाल शौर्य : ऐसे महामानव के बारे में बेचारा शब्द का प्रयोग करते हैं, आप अगर इस तरह से करते रहिएगा हमारे सप्तनदी पुत्र, सात नदियों से घिरे हुए उस जगह पर हमारे जो संस्थापक हैं, जहां सात नदी बहती हैं, खगड़िया में, उस फरकिया से उस जगह पर जन्म लिया, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, पद्म श्री और उनके बारे में आप इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, तभी तो 25 में, अभी तो 25 में सिमट गये हैं । अगर इस तरह हमारे नेता के बारे में, हमारे संस्थापक के बारे में, सप्तनदी के बीच में पैदा लेकर पूरे फरकिया को, पूरे

भारत के मानचित्र में खड़ा करने वाले ऐसे नेता के बारे में अगर उल्टा बोलिएगा, तो आप जीरो पर सिमट जाइएगा । इसी तरह आप महिलाओं के बारे में भी बोलते रहते हैं, आपलोग चुरचुरो और मुरमुरो की जो राजनीति करते हैं...

अध्यक्ष : एक मिनट में समाप्त करें बाबुलाल जी ।

श्री बाबुलाल शौर्य : आपलोग चुरचुरो और मुरमुरो की राजनीति करते हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो जनता आपको सबक सिखा देगी आने वाले चुनाव में । महोदय, आज ग्रामीण कार्य विभाग का कार्य बोलता है । आप देखेंगे सात नदियों से मेरा फरकिया है जिसको राजा टोडरमल ने फर्क कर दिया, वहां के कर्मपुत्र हमारे उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और हमारे संस्थापक सदस्य स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और चिराग पासवान जी का दिया हुआ खगड़िया पुल और पुलिया के जाल में बिछ गया । नीतीश जी का काम बोलता है, आप जाएंगे उस फरकिया में जहां सात नदी बहती हैं, उन सात नदियों के बीच में एक नहीं, सैकड़ों पुल बना और फरकिया का फर्क मिट गया, एक आंदोलन में, अध्यक्ष महोदय, आप भी गए थे, देखे होंगे उस रात में 50 हजार लोग सुगरकोल पुल से लेकर डेंगराही पुल पर खड़े थे और आप देखे होंगे आज वह पुल बन रहा है, डेंगराही पुल बन रहा है । सुगरकोल पुल बन कर तैयार हो गया और सर्किल नंबर–1, माननीय सम्राट चौधरी जी हमारे उप डिप्टी सी0एम0 साहब, इनका कर्मक्षेत्र परबत्ता है और फरकिया की दूरी मिटाने का काम किया और नीतीश जी के नेतृत्व में ग्रामीण कार्य विभाग दिखता है, आज ग्रामीण कार्य विभाग जिस तरह से काम किया है, तो इसी काम के बल पर आप देखेंगे कि जो विपक्ष के भी नेता हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त करिए ।

श्री बाबुलाल शौर्य : विपक्ष के भी नेता हैं, उन्हीं के काम के बल पर आज ये भी चुनकर आए हैं । आप देखेंगे सदन से वॉकआउट करते हैं ये...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रूहेल रंजन ।

श्री बाबुलाल शौर्य : और वॉकआउट करने के बाद अगर क्वेश्चन पूछना होता है, उनको लगता है कि नीतीश कुमार जी पर इनको भी विश्वास है उनको लगता है कि हम क्वेश्चन उठाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जनता...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाएं ।

श्री बाबुलाल शौर्य : हम स्थानीय मांगों पर भी कुछ कहना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : माइक ऑन कर दीजिए ।

श्री बाबुलाल शौर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं कि हमारा फरकिया सात नदियों से घिरा हुआ है, आज क्वेश्चन में भी आया था लेकिन बोलने का मौका नहीं मिला, यहां से लेकर मोजमा, जो सतीश नगर है...

अध्यक्ष : लिखित दे दीजिए ।

श्री बाबुलाल शौर्य : महोदय, सतीश नगर से लेकर कटगहरा तक में अगर पांच–सात पुल–पुलिया बन जाए और रोड की कनेक्टिविटी हो जाए, तो किसानों का उद्धार हो जाएगा । जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री जी से भी यही कहना चाहते हैं कि गौछारी–झंझरा से लेकर भरतखंड और सर्किल नंबर–1 में..

अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें । आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री बाबुलाल शौर्य : नदी का पानी नीचे जाने के बाद भी पानी फंसा रह जाता है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रूहेल रंजन जी ।

श्री बाबुलाल शौर्य : अगर वहां पर नहर जैसी सुविधा हो जाए तो हमारा किसान खुशहाल हो जाएगा और इतना ही काम बचा है । महोदय, हम जल संसाधन मंत्री महोदय को कहेंगे और माननीय विजय सिन्हा जी से भी हम अनुरोध करेंगे...

श्री रूहेल रंजन : माननीय अध्यक्ष महोदय,..

(व्यवधान)

श्री बाबुलाल शौर्य : जय जानकी, जय बिहार।

अध्यक्ष : बैठ जाइए । आप अलग से लिखकर दे दीजिएगा । बाबुलाल जी, आप अलग से मिलकर माननीय मंत्री जी को दे दीजिएगा । कृपया आपका समय समाप्त हुआ, बैठ जाइए । प्लीज बैठिए, बाबुलाल जी । श्री रूहेल रंजन जी बोलिए ।

श्री रूहेल रंजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पहली बात कविता लिखी है उसी से शुरुआत करना चाहूंगा–

''2005 में सड़क था गड्ढो का जाल,
हिलती थी जीप ड्राइवर रहता था बेहाल,
आज सड़कें ऐसी, सफर बने कमाल,
सीधे घर तक पहुंचे एंबुलेंस, गांव खुशहाल,
तब लोग पूछते थे बदलेगा कब हाल,
आज सब कहते हैं वाह बिहार कमाल ।''

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे मार्गदर्शक और राज्य के विकास पुरुष, हमारे अभिभावक श्री नीतीश कुमार जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं । उनके नेतृत्व में बिहार ने जो परिवर्तन देखा है मैंने कभी बचपन में उसकी कल्पना भी नहीं की थी और मैं अपने क्षेत्र इस्लामपुर के भाई–बहनों का नमन करता हूं, उन माताओं को जिन्होंने आशीर्वाद दिया, उन युवाओं को जिन्होंने विश्वास किया, उन किसानों को जिन्होंने उम्मीद के साथ मुझे यहां भेजा । मैं आज यहां अकेले नहीं खड़ा हूं, मेरे साथ मेरे क्षेत्र की हर उम्मीद, हर सपना, हर संघर्ष खड़ा है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक समय था जब बिहार का नाम लेते ही लोग निराशा की बातें करते थे, आज वही बिहार विकास, आत्मसम्मान और प्रगति का मिसाल बन चुका है । आज गांव से शहर तक सड़क बनी है, अंधेरे

गांवों में बिजली पहुंची है, जल का नल हर घर पहुंचा है, बच्चियां स्कूल जा रही हैं, किसान बाजार तक आसानी से पहुंच रहे हैं, आज बिहार का आम आदमी यह महसूस करता है कि सरकार उसके साथ खड़ी है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते थे कि वर्ष 2005 से पहले बिहार किस दौर से गुजर रहा था, सड़कें टूटी हुई थीं, पुल जर्जर थे, शाम होते ही डर का माहौल रहता था, आज स्थिति बदल चुकी है, आज लोग रात में भी सुरक्षित यात्रा करते हैं, आज निवेशक बिहार आने की सोचते हैं, यह परिवर्तन अपने आप नहीं आया, यह मजबूत इच्छा–शक्ति और ईमानदार नेतृत्व परिणाम है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं जिस विषय पर बोल रहा हूं वह मेरे दिल के बहुत करीब है, ग्रामीण कार्य विभाग का बजट, यह विभाग केवल सड़क नहीं बनाता, यह उम्मीद बनाता है, यह विश्वास बनाता है, यह सपनों को रास्ता देता है, गांव की आत्मा उसकी सड़क से जुड़ी होती है, जब सड़क बनती है तो गांव दुनिया से जुड़ता है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सड़क को केवल डांबर और गिट्टी के रूप में नहीं देख सकते, जब सड़क बनती है किसान की फसल समय पर मंडी पहुंचती है, छात्र समय पर स्कूल पहुंचता है, गर्भवती महिला समय पर अस्पताल पहुंचती है, मजदूर को काम मिलता है, छोटा दुकानदार अपना समान बेच पाता है, एक सड़क पूरे गांव की जिंदगी बदल देती है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया अब संक्षिप्त करें ।

टर्न–24 / पुलकित / 18.02.2026

श्री रूहेल रंजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट केवल पैसों का हिसाब नहीं है । यह गाँव के भविष्य का दस्तावेज है । यह बजट किसान की ताकत बढ़ाएगा, युवाओं को काम देगा, छोटे उद्योगों को सहारा देगा, गरीब परिवारों को सुविधा देगा । जब गाँव मजबूत होंगे, तभी बिहार मजबूत होगा । आज मैं पूरे विश्वास और गर्व के साथ इस बजट का समर्थन करता हूँ । मुझे विश्वास है कि यह बजट बिहार के हर गाँव तक विकास की रोशनी पहुँचाएगा । आखिर में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह गुजारिश करूँगा कि जितने भी बड़े–बड़े ग्लोबल टेंडर हैं, अगर उसको अलग–अलग करके वह छोटे–छोटे करेंगे, तो जितने भी छोटे गाँव के लोग हैं उनको भी एक चांस मिलेगा । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग ।

सरकार का उत्तर

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से बिहार के विकास में, उनके संकल्प में, एक गिलहरी प्रयास के रूप में भागीदारी निभाने का मौका दिया है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आज आपने विभाग की ओर से मांग रखने का मौका दिया है ।

बिहार की धरती ने विश्व को ज्ञान दिया । हम चाणक्य, गौतम बुद्ध और प्राचीन नालंदा की परंपरा के ध्वजवाहक हैं । लेकिन जिस भूमि ने शासन, नीति और ज्ञान की आधारशिला रखी, वही प्रचुर प्राकृतिक संसाधन रहने के बावजूद बीमारू राज्य के रूप में मजाक का पर्याय बन गया ।

हमारे बहुत से साथियों ने आज, लगभग 17–18 साथियों ने अपने सुझाव दिए हैं । बहुत साथी कटौती प्रस्ताव पर आए । अमरेन्द्र जी यहाँ बैठे हैं, हम इनको बताना चाहते हैं कि आपके यहाँ पिछले वित्तीय वर्ष में माननीय नेता नीतीश कुमार ने सिर्फ आपकी विधान सभा में 144 सड़क, 302 किलोमीटर और 350 करोड़ रुपया एक विधान सभा में आपके क्षेत्र में खर्च करने का काम किया है ।

प्रमोद जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन जब भाषण दे रहे थे तो लग रहा था कि अपोजिशन के हैं । उनको भी बताना चाहते हैं कि उनके यहाँ 106 सड़क, 168 किलोमीटर और 168 करोड़ की राशि माननीय नेता ने उनके यहाँ दी है और सात ब्रिज भी देने का काम किया है ।

दूसरे हमारे साथी सरवर साहब कह रहे थे कोचाधामन के, इनके यहाँ 133 किलोमीटर और 146 करोड़ रुपया आपकी विधान सभा में दिया गया है । आप अंतिम पायदान पर हैं और आपके यहाँ बाढ़ की विभीषिका हर बार आती है, इसीलिए माननीय नेता ने विशेष रूप से आपके ऊपर ध्यान दिया है ।

श्री अरुण सिंह जी हम लोगों के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहे थे । उनके यहाँ माननीय नेता ने 164 किलोमीटर, 173 लाख रुपया इनके विधान सभा क्षेत्र में देने का काम किया है ।

विभूतिपुर के भाई अजय जी बैठे हुए हैं, ये भी थोड़ा–थोड़ा मिर्च–मसाला लगा रहे थे । इनके यहाँ 158 किलोमीटर और 137 करोड़ की राशि देने का काम किया गया है ।

इंद्रजीत भाई अभी बीच–बीच में बोल रहे थे इसलिए इनके बारे में नहीं बोलेंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो हमारे माननीय विपक्ष के साथी हैं, बार–बार सरकार के ऊपर आक्षेप करते हैं, सरकार को और नेता को घेरने का काम करते हैं । हम इनको एक शेर से इनकी तारीफ करना चाहते हैं –

''लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं,
जिनके खुद के हिसाब–किताब बिगड़े हुए हैं,
वह हमारा हिसाब लिए फिरते हैं ।।''

महोदय, बिहार का इतिहास साक्षी है कि जब शासन का केंद्र–जन होता है, तब सड़कों से समृद्धि बहती है । शिक्षा के अवसर जन्म लेते हैं और न्याय से विश्वास नवनिर्मित होता है । बिहार में हर युग में लोक कल्याणकारी शासकों ने आधारभूत संरचना को मजबूत बनाकर समाज को नई दिशा देने का काम किया है । यदि मात्र आधारभूत संरचना की चर्चा करें तो सम्राट अशोक ने सैकड़ों वृक्षारोपण एवं विश्राम गृहों का निर्माण कराया, जिससे जन–कल्याण एवं मध्यकालीन युग में शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कर प्रशासन और व्यापार को गति दी । परंतु जब शासन का केंद्र परिवार या स्वार्थ हो जाता है, सब संस्थाएं क्षीण हो जाती हैं । विकास ठहर जाता है और जनता का विश्वास टूट जाता है ।

हम शर्मसार होते थे जब, वर्ष 2005 से पूर्व बिहार, सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क के रूप में हास्य का पर्याय बनता था और यह विषय पूरे देश में बिहार के बारे में लेने का काम होता था ।

"Infrastructure is not merely about target achieved or kilometers completed. It is about "trust" delivered."

ग्रामीण सड़क केवल मार्ग नहीं, विश्वास की रेखा है ।

महोदय, वह विश्वास जो बिहार की महान जनता ने कुशासन, पिछड़ापन, हताशा और निराशा से त्राहिमाम करते हुए युग पुरुष, कालजयी व्यक्तित्व के धनी हमारे नेता नीतीश कुमार पर पिछले 20 वर्षों पर जताती आ रही है ।

नीतीश कुमार पूरे देश में विकास और विश्वास के प्रतीक बन गए हैं।

महोदय,

संविधान हमें अधिकार देता है,
संस्थाएं हमें ढांचा देती हैं ।

परंतु शासन को वैधता और नैतिकता बल, जन–विश्वास देता है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सुशासन, न्याय के साथ विधि का शासन, समान अवसर, सुदृढ़ अवसर रचना और सबसे ऊपर जन–विश्वास के साथ के सबसे सशक्त हस्ताक्षर हैं ।

आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एन0डी0ए0 सरकार सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास की भावना के साथ पूरे बिहार में, पूरे देश के विकास के हेतु प्रतिबद्ध है ।

महोदय, मैं पॉलिटिकल साइंस का छात्र रहा हूँ । पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट को समझने का प्रयास किया है कि राजनीति में संरचना, राज्य

की प्रकृति, सत्ता संबंध और संस्थाएं किसी राज्य की आर्थिक और सामाजिक विकास को कैसे प्रभावित करती है । अभी की प्रचलित थ्योरिज, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी, स्टेट–लेड प्रिंसिपल, इंस्टिट्यूशनल, निओ–लिबरल और मार्कसिस्ट प्रिंसिपल आदि में राज्य की भूमिका कहीं सहायक के रूप में, कहीं थ्योरी में सीमित है, कहीं केंद्रीय भूमिका में है, लेकिन कहीं न्यूनतम उत्तरदायित्व की क्रांति भी होती है । मुझे ग्रामीण कार्य विभाग में रहते हुए नीतीश थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट को समझने का मौका मिला है ।

एक सड़क भी केवल मार्ग नहीं, अपितु राष्ट्र निर्माण का साधन हो सकता है । जहाँ मजबूत अवसंरचना, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और सामाजिक समावेशन का संयोजन ही सतत विकास का मार्ग प्रशस्त करता है । चाणक्य ने अर्थशास्त्र में वर्णित किया है–

''प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम् ।
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम् ।।''

यानी, राजा का सुख प्रजा के सुख में है । जो राजा प्रजा को प्रिय और हितकर है, वही राजा के लिए हितमय है । यही नीतीश कुमार के लोकतंत्र के शासन का सार है ।

महोदय, पं0 दीन दयाल उपाध्याय ने समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान को लोकतांत्रिक शासन की कसौटी मानते हुए अंत्योदय का सिद्धांत दिया । यदि विकास का लाभ समाज के कमजोर वर्ग तक नहीं पहुँचता है, तो वह विकास अधूरा है । माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने शासन का मूल मंत्र अंत्योदय बना लिया । उन्होंने सुनिश्चित किया कि सुशासन के कार्यक्रम, न्याय के साथ विकास एवं परिणामोन्मुखी प्रशासन के रूप में सात निश्चय के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और सहभागिता से बिहार जैसे राज्य में, जहाँ ऐतिहासिक रूप से सामाजिक–आर्थिक चुनौतियां थीं, वहां पर हमने पारदर्शिता पूर्वक इस लोकतंत्र का शासन करने का काम किया है ।

महोदय, यदि शासन शरीर है तो आधारभूत संरचना उसकी रीढ़ है। राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना के विकास के लिए उन्नत कोटि की बारहमासी सड़कों का निर्माण होना अति आवश्यक है । इसी के लिए राज्य के सभी अनजुड़े टोलों/बसावटों/ग्रामों को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु नए पथों एवं पुलों के निर्माण के साथ–साथ पूर्व निर्मित ग्रामीण पथों के सुदृढ़ीकरण एवं अनुरक्षण कार्य हेतु राज्य सरकार कृत–संकल्पित है ।

इस क्रम में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा राज्य प्रायोजित मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना, ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना, राज्य योजना (नाबार्ड ऋण सम्पोषित), मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना, ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना, सुलभ सम्पर्कता

योजना एवं केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा माह जनवरी, 2026 तक पूर्णतया अपने संसाधन से, राज्य सरकार अपने संसाधनों से, राज्य योजना द्वारा लगभग 38,505.69 करोड़ (अड़तीस हजार पांच सौ पांच करोड़ उनहत्तर लाख) रुपये व्यय करकर 66,206 किलोमीटर पथों एवं 1,176 पुलों के निर्माण/पुनर्निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया है ।

(क्रमशः)

टर्न–25/हेमन्त/18.02.2026

(क्रमशः)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से 29,529.26 करोड़ रूपये व्यय कर 53,594 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों एवं 1658 पुलों का निर्माण पूरा किया गया है। इस प्रकार राज्य में कुल 119,800 किलोमीटर ग्रामीण पथ एवं 2,834 पुलों का निर्माण/पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। राज्य में विभिन्न योजनाओं के तहत 7,133 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

महोदय, ग्रामीण सड़कों के स्वरूप का एक महत्वपूर्ण अवयव महिलाओं एवं कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण में नजर आता है। ग्रामीण सड़कें केवल भौतिक संपर्क नहीं बनाती, वे सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करती हैं। जब बारहमासी सड़कें बिहार के सुदूर कोनों में बसी किसी आबादी को जोड़ती हैं, तो उसका प्रभाव महिलाओं और बालिकाओं के जीवन में दिखता है। आज हमारी छात्राएं बड़ी संख्या में बिना किसी बाधा के विद्यालय पहुंचती हैं, गर्भवती माताएं समय पर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचती हैं एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने उत्पाद बाजारों तक ले जाने का काम करती हैं। महोदय, सड़कें केवल दूरी नहीं घटाती, वह अवसरों की खाई पाटती हैं और हमारे नेता ने इसी चीज को ध्यान में रखकर विशेष रूप से अपने शासनकाल में ग्रामीण कार्य विभाग को सशक्त और मजबूत करने का काम किया। माननीय नेता के आने के पहले इस बिहार में मात्र प्रधानमंत्री सड़क योजना से काम होता था और केंद्रीय एजेंसियां इस बिहार में सड़कों का निर्माण का काम करती थीं। बिहार में सिर्फ और सिर्फ 8000 किलोमीटर सड़क पूरे बिहार में थी। आज, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और मुख्यमंत्री अवशेष योजना के तहत, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस प्रदेश में 500 की आबादी पर अपनी योजना देने का काम किया था कि अवशेष को हम 500 टालों पर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने संसाधन पर उसे 250 किया और अब जाकर 100 की बसावटों को भी संपर्क देने का काम शुरू किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमेशा कहते हैं, "I measure the progress of a

community by the degree of progress which women have achieved." ''समाज की प्रगति का मानक महिलाओं की प्रगति है'' और इसका आदर्श उदाहरण जीविका दीदिओं का हैं। आज 11 लाख स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1 करोड़ 40 लाख से अधिक परिवार की महिलाएं आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में पूरे देश में नजीर बन गई हैं। ग्रामीण सड़कें आज 9.76 लाख परिवार मुर्गी पालन एवं बकरी पालन, 143 रूरल रिटेल मार्ट का संचालन, 1,18,782 परिवार माइक्रो इंटरप्राइज, 6,459 बैंक सखी के माध्यम से 19,955 करोड़ की जमा निकासी करने में एवं 520 कस्टम हायरिंग केंद्रों के संचालन में सहयोग प्रदान कर रही है।

महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क को समृद्धि का मार्ग मानते हैं और उन्होंने 100 से ज्यादा आबादी की बसावटों को बारहमासी सड़क से जोड़ने का लक्ष्य बनाया, जो सामाजिक समानता, आर्थिक अवसर और सैद्धांतिक आदर्शों की स्थापना को समाहित करते हुए समावेशी विकास का आदर्श मॉडल बन गया है। "Infrastructre is not just about roads and bridges; it's about building a foundation for shared prosperity." उनके लिए सड़क मात्र परिवहन का प्रश्न नहीं होता है, वह पूरी आबादी के लिए अवसर, समानता, और गरिमा का प्रश्न होता है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं की भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों की भी मैं चर्चा करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से ग्रामीण इलाकों में कृषि उत्पादनों को, जीविका दीदियों को और हमारे पशुपालन और फिशरी के क्षेत्र में जो लोग हैं, जिनको माननीय नेता ने कृषि रोड मैप–1, कृषि रोड मैप–2 और कृषि रोड मैप–3 के माध्यम से सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। उनको भी यह सड़क आने वाली आर्थिक संपन्नता को अवसर प्रदान करने का काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अवशेष, जिसको महात्मा गांधी मानते थे कि ''भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है, एवं लोकतंत्र का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक उत्थान है'' और इसी को ध्यान में रखकर माननीय नेता ने 500 की आबादी से घटाकर 250 की आबादी और 250 की आबादी को घटाकर 100 पर लाने का काम किया है कि जो भी अंतिम पायदान पर महादलित, अति पिछड़े के लोग रहते हैं, जिनकी आबादी 100 की है, उनको भी हम बारहमासी सड़कों से जोड़ने का काम करेंगे, और माननीय नेता की इस योजना को बिहार सरकार अपने संसाधनों के माध्यम से करने का काम कर रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना, इसके माध्यम से हम लोगों ने हमारे नेता के शासनकाल में आधारभूत संरचना के निर्माण में, सुदृढ़ीकरण के क्षेत्र में, बिहार पुनर्जागरण का स्वर्णिम काल खंड

है। राज्य के शासकीय प्रक्षेत्र में निर्मित आइकॉनिक भवनों के साथ सड़क, बिजली आदि सभी आवश्यक सुविधाएं जनसाधारण को सुलभ हैं। माननीय मुख्यमंत्री नव निर्माण के साथ–साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के महत्व को समझते हुए अनुरक्षण एवं संधारण को भी इक्वल फुटिंग पर रखते हैं। इसी के अनुरूप इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में चिन्हित ग्रामीण सड़कों के पुनर्निर्माण/उन्नयन द्वारा ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत किए जाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं से निर्मित पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर हुए वैसे पथ जिनकी निरूपण अवधि पूर्ण हो चुकी है अथवा निरूपण अवधि के पूर्व ही निरूपित यातायात को प्राप्त किया जाना है, के उन्नयनार्थ पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण/ चौड़ीकरण किए जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत कुल 856 पथ, जिसकी कुल लंबाई 3034 किलोमीटर है, को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए अब तक 751 पथों के पुनर्निर्माण का काम पूर्ण करा लिया गया है। ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण में माननीय नेता ने निर्णय लिया कि अब हम 7 साल तक इन सड़कों को, डिफेक्ट लायबिलिटी से जो बाहर होंगे, उनको हम बनाने का काम करेंगे और इसके लिए माननीय नेता ने पिछली बार एक नया घटक ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम नवंबर 2024 को लागू किया और हम एक शेर से, माननीय नेता के इस निर्णय को राहत इंदोरी के इस शेर से, ''आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, हम परो से नहीं, हौसलों से उड़ते हैं।'' इसीलिए, जो विपक्ष के साथी बार–बार कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा, लेकिन जब इन्होंने माननीय नेता को बिहार दिया था..

(व्यवधान)

एक मिनट, एक मिनट।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप बोलिये न।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : बैठिए न, बैठिए न। आपको तो अभी हम बताए न।

अध्यक्ष : बोलिए, माननीय मंत्री।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय नेता को यह बिहार मिला, तो यह बिहार मात्र 26 हजार करोड़ के बजट का बिहार था। 15 साल इनका शासन काल था और आपके, हमारे पूर्व के सदस्यों ने बताया कि ग्रामीण कार्य विभाग का क्या बजट था, अनुसूचित जाति जनजाति का क्या बजट था, अल्पसंख्यक कल्याण का क्या बजट था, जो बड़ी आबादी इस प्रदेश में, 70 प्रतिशत आबादी हाशिये पर पड़ी रहती थी। इनके पास बजट नहीं था कि उस आबादी को हम बढ़ाने का काम करें और आज नेता ने लगभग 3 लाख 27 हजार करोड़ का बजट इस वित्तीय वर्ष में, इसी सदन में पेश करने का काम किया है। लोग कहते हैं कि 20 साल में नीतीश जी ने किया क्या है। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं कि गिलास में आधा पानी खाली दिखता है और एक तरह के

लोगों को आधा गिलास भरा दिखता है। तो ये खाली वाले लोग हैं, क्योंकि इनका लेवल कभी ऊपर गया ही नहीं है और कुछ को दिखता ही नहीं है।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बर्हिगमन कर गये)

अध्यक्ष : आप बोलते रहिये।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कोई आइयेगा नहीं पुल–पुलिया मांगने, क्योंकि सुन ही नहीं रहे हैं आप लोग। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना, "Every bridge shortens a distance - between markets, minds and opportunities". पुल–पुलिया केवल यातायात को सुगम नहीं बनाते, वह अवसरों और संभावनाओं के सेतु होते हैं। जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश में मुख्यमंत्री सेतु योजना की शुरुआत की, हमारे नेता के आने के पहले बिहार में इस योजना का नाम–ओ–निशान नहीं था।

(क्रमशः)

टर्न–26 / संगीता / 18.02.2026

(क्रमशः)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने अपने संसाधन से इस प्रदेश में सेतु योजना की शुरूआत की और इस प्रदेश में वैसे सेतुओं को, वैसे बसावटों को, जो 70 साल की आजादी के बाद भी जिनको, उनके मां–पिता को, बाप–बेटे को साड़ी और धोती उठाकर चलना पड़ता था, उसको माननीय नेता ने सम्मान का जीवन जीने का नाम दिया और आज हमलोगों ने इस योजना के अंतर्गत अभी इस पिछले वित्तीय वर्ष 909 पुलों को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें 660 पुलों का एग्रीमेंट हो गया है और हमलोगों ने विशेष रूप से इस बार ध्यान दिया है कि हमारे जो डी0पी0आर0 बने हैं, उसके बाद भी हम आई0आई0टी0, एम0आई0टी0 के पुल निर्माण निगम के जो एक्सपर्ट इंजीनियर हैं, उनसे हमने डी0पी0आर0 को वेट्ट करवाया है कि डी0पी0आर0 ठीक है कि नहीं है, डबलक्रॉस करके हम पुल का निर्माण कर रहे हैं, जिससे भविष्य में हमारे पुलों को कोई नुकसान नहीं होगा।

ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना –

"Good governance is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and promoting development."

डॉ0 भीम राव अम्बेडकर कहते थे ''मनुष्य का जीवन स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित होना चाहिए । ग्रामीण सड़कें इन तीनों मूल्यों को व्यावहारिक रूप देती हैं । स्वतंत्रता आवागमन की, समानता अवसर की और बंधुत्व समाज से जुड़ाव की । जब सड़क गांव तक पहुंचती है तो सबसे अधिक

लाभ महिलाओं और वंचित वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ों को मिलती है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चाणक्य अर्थनीति में राजा के कर्तव्य के बारे में बताते हैं–

"The king shall construct roads, causeways, bridges, reservoirs and ensure their protection." राजा का कर्तव्य है वह मार्ग, सेतु, जलाशय और व्यापार और सुविधाएं विकसित करे तथा उनका संरक्षण सुनिश्चित करे ।

महोदय, हमारे दूरदर्शी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में इसी प्रकार सर्वांगीण और आधारभूत संरचना के विकास के नये स्वर्णिम अध्याय को लिखने का काम किया है । उनके नेतृत्व में बिहार में GSDP का विकास दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है एवं बिहार सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में शामिल है । मैंने उनके सान्निध्य में यह पाया है कि यह प्रार्थना उनके मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कायम है ।

''सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ।''

यह केवल आध्यात्मिक वाक्य नहीं है बल्कि नीति–निर्माण का नैतिक आधार है और अन्त में, हमारे विपक्ष के साथी भाग गए, हम उनसे कहना चाहते हैं –

''वसुधा का नेता कौन हुआ,
भूखंड–विजेता कौन हुआ,
अतुलित यश क्रेता कौन हुआ,
जिसने न कभी आराम किया
विघ्नों में रहकर काम किया ।''

और हमारे नेता, आप जैसे जितने लोग हैं क्योंकि बारह महादेव के बारात में रीछ, भालू, जितने लोग होते थे, भूत–पिशाच सब लोग बाबा के दरबार में जाते थे तो हमारे नेता भी मानते हैं कि पूरे बिहार में सब लोग है, पूरा बिहार मेरा परिवार है और आपके कितने भी विघ्न करने के बाद भी बिहार की ताकत को बढ़ाने के लिए, बिहार को आगे ले जाने के लिए, बिहार को अग्रिम राज्यों में शामिल करने के लिए कृतसंकल्पित हैं और ग्रामीण कार्य विभाग उनके साथ, उनके संकल्प में साथ–साथ खड़ा रहेगा । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2026–27 जिसका समापन 31.03.2027 को होना है, विभाग की योजनाओं के व्यय की पूर्ति हेतु 11,312.1799 करोड़ रुपये (ग्यारह हजार तीन सौ बारह करोड़ सत्रह लाख निन्यानबे हजार) रुपये मात्र की योजना का सदन के समक्ष प्रस्ताव रखता हूं तथा माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि बिहार के विकास को ताकत देने के लिए,

नीतीश कुमार के सपनों को साकार करने के लिए, इसको अनुमति प्रदान की जाए और हम माननीय सदस्यों से आग्रह करते हैं कि अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेने का काम करें । XXX

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ ।

क्या माननीय सदस्य, राहुल कुमार अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की मांग 10/–रुपये से घटायी जाए।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 11312,17,99,000/– (ग्यारह हजार तीन सौ बारह करोड़ सत्रह लाख निन्यानवे हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–18 फरवरी, 2026 के लिए स्वीकृत निवेदनों की संख्या–53 है । अगर सदन की सहमति हो, तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाए ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की कार्यवाही वृहस्पतिवार, दिनांक–19 फरवरी, 2026 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

———————————————————————————————

XXX- अंश को माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार (दिनांक–19.02.2026) विलोपित किया गया ।

———————————————————————————————

परिशिष्ट

बजट भाषण

अध्यक्ष महोदय,

मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभारी हूँ उन्होंने मुझे ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से बिहार के विकास के उनके संकल्प में, एक गिलहरी प्रयास के रूप में भागीदारी निभाने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ आज आपने विभाग की ओर से माँग रखने का मौका दिया।

बिहार की धरती ने विश्व को ज्ञान दिया। हमें चाणक्य, गौतम बुद्ध और प्राचीन नालंदा की परंपरा का ध्वजवाहक होना था। लेकिन जिस भूमि ने शासन, नीति और ज्ञान की आधारशिला रखी, वही प्रचुर प्राकृतिक संसाधन मौजूद रहने के बावजूद बीमारू राज्य के रूप में मजाक का पर्याय बन गयी थी।

महोदय,

बिहार का तो इतिहास साक्षी है कि जब शासन का केंद्र 'जन' होता है, तब सड़कों से समृद्धि बहती है, शिक्षा के अवसर जन्म लेते हैं और न्याय से विश्वास निर्मित होता है। बिहार में हर युग में लोक कल्याणकारी शासकों ने आधारभूत संरचना को मजबूत बनाकर समाज को नई दिशा दी है।

यदि मात्र आधारभूत संरचना की चर्चा करें तो सम्राट अशोक ने सड़कों वृक्षारोपण एवं विश्रामगृहों का निर्माण कराया जिससे जन कल्याण एवं मध्यकालीन युग में शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण कर प्रशासन और व्यापार को गति दी।

परंतु जब शासन का केन्द्र 'परिवार' या 'स्वार्थ' हो जाता है, तब संस्थाएँ क्षीण होती हैं, विकास ठहर जाता है और जनता का विश्वास टूट जाता है। हम शर्मसार होते थे जब, वर्ष 2005 से पूर्व बिहार, सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क के रूप में हास परिहास का विषय बन गया था।

महोदय,

Infrastructure is not merely about target achieved or kilometers completed. It is about "trust" delivered

"ग्रामीण सड़क केवल मार्ग नहीं, विश्वास की रेखा है"

महोदय,

वह विश्वास जो बिहार की महान जनता ने कुशासन, पिछड़ापन, हताशा और निराशा से त्राहिमाम करते हुए युगपुरूष, कालजयी व्यक्तिव्य के धनी हमारे नेता नीतीश कुमार पर पिछले बीस सालों से जताती आ रही है।

"नीतीश कुमार पूरे देश में विकास और विश्वास के प्रतीक बन गये हैं।"

महोदय,

संविधान हमें अधिकार देता है,
संस्थाएँ हमें ढाँचा देती हैं,

परंतु शासन को वैधता और नैतिक बल देता है– जनविश्वास।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुशासन, न्याय के साथ विधि का शासन, समान अवसर, सुदृढ़ अवसंरचना, और सबसे ऊपर–जनविश्वास के सबसे सशक्त हस्ताक्षर हैं।

आज (माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में) **NDA** सरकार सबका साथ सबका विकास एवं सबका विश्वास की भावना के साथ बिहार एवं पूरे देश के विकास हेतु प्रतिबद्ध है।

महोदय,

मैं **Political science** का छात्र रहा हूँ। मैंने **Political theories of development** को समझने का प्रयास किया है कि राजनीतिक संरचना राज्य की प्रकृति, सत्ता संबंध और संस्थाएँ, किसी राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक विकास को कैसे प्रभावित करती है ?

अभी की प्रचलित **theories, Modernization theory, Dependency theory, State-led principle, Institutional, Neo-liberal or Marxist principle** आदि में राज्य की भूमिका कहीं सहायक के रूप में, कहीं थोड़ी सीमित, कहीं केन्द्रीय भूमिका, कहीं न्यूनतम उत्तरदायी या क्रांतिकारी भी होती है।

मुझे ग्रामीण कार्य विभाग में **Nitish theory of development** को समझने का मौका मिला कि एक सड़क भी केवल मार्ग नहीं अपितु राष्ट्र निर्माण का साधन हो सकता है– जहाँ मजबूत अवसंरचना, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और सामाजिक समावेशन का संयोजन ही सतत् विकास का मार्ग प्रशस्त करता है।

चाणक्य ने अर्थशास्त्र में वर्णित किया है कि:–

प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्।
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्।।

राजा का सुख प्रजा के सुख में है, जो प्रजा को प्रिय और हितकर है वही राजा के लिए भी हित में है। यही नीतीश कुमार के लोकतांत्रिक शासन का सार है।

महोदय,

महात्मा गांधी ने समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान को लोकतांत्रिक शासन की कसौटी मानते हुए 'अंत्योदय' का सिद्धांत दिया। यदि विकास का लाभ समाज के कमजोर वर्ग तक नहीं पहुँचता, तो वह विकास अधूरा है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसे अपने शासन का मूल मंत्र बना लिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सुशासन के कार्यक्रमों, न्याय के साथ विकास एवं परिणामोन्मुखी प्रशासन के रूप में सात निश्चयों के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही, और सहभागिता से बिहार जैसे राज्य में, जहाँ ऐतिहासिक रूप से सामाजिक–आर्थिक चुनौतियाँ रही थीं, वहाँ शासन का

महोदय,

यदि शासन शरीर है तो आधारभूत संरचना उसकी रीढ़ है।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना के विकास के लिए उन्नत कोटि की बारहमासी सड़कों का निर्माण होना अतिआवश्यक है। इसके लिए राज्य के सभी अनजुड़े टोलों/बसावटों/ग्रामों को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु नये पथों एवं पुलों के निर्माण के साथ–साथ पूर्व निर्मित ग्रामीण पथों के सुदृढ़ीकरण एवं अनुरक्षण कार्य हेतु राज्य सरकार कृत–संकल्पित है। इस क्रम में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा राज्य प्रायोजित मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना, ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना, राज्य योजना (नाबार्ड ऋण सम्पोषित), मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना, ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना, सुलभ संपर्कता योजना एवं केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा माह जनवरी, 2026 तक पूर्णतया अपने संसाधनों से राज्य योजनाओं द्वारा लगभग 38,505.69 करोड़ (अड़तीस हजार पाँच सौ पाँच करोड़ उनहत्तर लाख) रूपये व्यय कर 66,206 किलोमीटर (छियासठ हजार दो सौ छह किलोमीटर) पथों एवं 1176 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 29,529.26 करोड़ (उनतीस हजार पाँच सौ उनतीस करोड़ छब्बीस लाख) रूपये व्यय कर 53,594 किलोमीटर (तिरेपन हजार पाँच सौ चौरानबें किलोमीटर) ग्रामीण सड़कों एवं 1658 पुलों का निर्माण पूरा किया गया है। इस प्रकार राज्य में कुल 1,19,800 किलोमीटर (एक लाख उन्नीस हजार आठ सौ किलोमीटर) ग्रामीण पथों एवं 2834 पुलों का निर्माण/पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।

सम्प्रति राज्य में विभिन्न योजनाओं के तहत 7,133 किलोमीटर (सात हजार एक सौ तैंतीस किलोमीटर) सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

महोदय,

ग्रामीण सड़कों के स्वरूप का एक महत्वपूर्ण अवयव महिलाओं व कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण में नजर आता है।

ग्रामीण सड़कें केवल भौतिक संपर्क नहीं बनाती हैं वे सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करती हैं। जब बारहमासी सड़क बिहार के सुदूर कोने में बसे किसी आबादी तक को जोड़ती है, तो उसका प्रभाव महिलाओं और बालिकाओं के जीवन में दिखता है।

आज हमारी छात्राएं बड़ी संख्या में बिना किसी बाधा के विद्यालय पहुँचती हैं,

गर्भवती माताएँ समय पर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पाती हैं

एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने उत्पाद बाजार तक ले जा पाती हैं।

महोदय,

<u>सड़कें केवल दूरी नहीं घटाती– वे अवसरों की खाई पाटती हैं।</u>

बाबा साहब हमेशा कहते थे – **"I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved."**

"समाज की प्रगति का मानक महिलाओं की प्रगति है।"

इसका आदर्श उदाहरण जीविका दीदीओं का है। आज 11 लाख स्वयं सहायता समूह से जुड़ी एक करोड़ 40 लाख से अधिक परिवार की महिलाएं आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में पूरे देश में नजीर बन चुकी हैं।

ग्रामीण सड़कें आज 9.76 लाख परिवार मुर्गी पालन एवं बकरी पालन, 143 **Rural retail mart** का संचालन 1,18,782 परिवार **Micro Enterprise, 6,459** बैंक सखी के माध्यम से 19 हजार 09 सौ पचपन करोड़ रूपये की जमा निकासी करने में एवं 520 **Custom Hiring** केंद्रों के संचालन में सहयोग प्रदान कर रही है।

महोदय,

हमारी 2005 के पूर्व सीमित कार्यबल एवं क्षमता के कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन हेतु 05 सेंट्रल एजेंसी **CPWD, IRCON, NBCC** आदि का सहारा लेना पड़ता था।

माननीय नेता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अभियंताओं की बहाली एवं क्षमता संवर्द्धन के बाद वर्ष 2016–17 में पूरे देश में सबसे ज्यादा बसावटों यानि 4173 बसावटों को संपर्कता प्रदान करने हेतु एवं हमारी एजेंसी **BRRDA** को 6601 कि0मी0 सड़कों के निर्माण हेतु भारत सरकार से प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।

महोदय,

बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना तथा ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत निर्मित एवं पंचवर्शीय अनुरक्षण/त्रुटि निवारण अवधि से बाहर हुए अब तक कुल 49,390 किलोमीटर (उनचास हजार तीन सौ नब्बे किलोमीटर) लंबाई के ग्रामीण पथों की अनुरक्षण/नवीनीकरण/ उन्नयन/ पुनर्निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया है।

महोदय,

माननीय मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़कों को समृद्धि का मार्ग मानते हैं। उन्होंने 100 से ज्यादा आबादी की सभी बसावटों को बारहमासी सड़क से जोड़ने का लक्ष्य बनाया जो सामाजिक समानता, आर्थिक अवसर और संवैधानिक आदर्शों की स्थापना को समाहित करते हुए समावेशी विकास का आदर्श मॉडल बन गया।

"Infrastructure is not just about roads and bridges; it's about building a foundation for shared prosperity."

उनके लिए सड़क मात्र परिवहन का प्रश्न नहीं होता है वह पूरी आबादी के लिए अवसर, समानता और गरिमा का प्रश्न होता है।

अब मैं माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं की भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों की चर्चा करना चाहता हूँ।

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना – यह राज्य सरकार की एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना रही है। इस योजना ने ग्रामीण सड़कों की सम्पर्कता में सुधार के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों के वाणिज्यिक विकास एवं कृषि उत्पादों के बेहतर उत्पादन एवं परिवहन व्यवस्था को सुचारू करने में

महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य के सभी जिलों में 250 से अधिक की जनसंख्या वाले सभी टोलों/बसावटों/ग्रामों को बारहमासी एकल सड़क सम्पर्कता प्रदान करने के लक्ष्य के साथ लक्षित टोलों/बसावटों/ग्रामों को सम्पर्कता प्रदान करने के लिए 29,997 करोड़ (उनतीस हजार नौ सौ सत्तानबें करोड़) रूपये के लागत से 35,531 किलोमीटर (पैंतीस हजार पाँच सौ इकतीस किलोमीटर) की लंबाई के पथों एवं 328 पुलों की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके विरूद्ध अबतक 32,468 किलोमीटर (बत्तीस हजार चार सौ अड़सठ किलोमीटर) पथों एवं 192 पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष कार्य निर्माण की विभिन्न चरणों में है।

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष)–

महोदय,

महात्मा गांधी मानते थे कि "भारत की आत्मा उसके गाँवों में बसती है एवं लोकतंत्र का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति का उत्थान है।"

हमारे मुख्यमंत्री सुशासन को प्रशासनिक दक्षता के साथ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए सरकार की संवेदनशीलता और जवाबदेही मानते हैं।

उसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इस योजना अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में 100 या इससे अधिक की आबादी के छूटे हुए बसावटों का ऐप के माध्यम से किये गये सर्वेक्षण के आधार पर कुल अनजुड़े 13,814 बसावटों (कुल लम्बाई 16,652 किलोमीटर) में से अबतक कुल 10,208 करोड़ रूपये की लागत से 6,079 बसावटों को संपर्कता प्रदान करने के लिए कुल 8,036 कि0मी0 पथों एवं 119 पुलों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए अब तक कुल 2,018 कि0मी0 पथों एवं 01 पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष कार्य निर्माण के विभिन्न चरणों में है।

इस वित्तीय वर्ष में 5,940 करोड़ की लागत से 4,500 बसावटों को संपर्कता प्रदान करने के लिए कुल 4,500 कि0मी0 पथों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करने का लक्ष्य है तथा शेष 3,235 बसावटों (कुल लम्बाई 4,116 किलोमीटर) को संपर्कता प्रदान करने हेतु आने वाले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किये जाने का लक्ष्य है।

इसके अतिरिक्त राज्य अंतर्गत अन्य राज्य योजनाओं के द्वारा 27,751 किलोमीटर (सताईस हजार सात सौ इक्यावन किलोमीटर) पथों एवं 983 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 6,000 किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 1,728 किलोमीटर (एक हजार सात सौ अट्ठाईस किलोमीटर) पथों एवं 196 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है एवं शेष पथों/पुलों का कार्य निर्माण की विभिन्न चरणों में है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजनाः–

महोदय,

हमारे नेता का शासनकाल, आधारभूत संरचना के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के क्षेत्र में बिहार के पुनर्जागरण का स्वर्णिम काल खण्ड है। राज्य के शासकीय प्रक्षेत्र में निर्मित **Iconic** भवनों के साथ सड़क, बिजली आदि सभी आवश्यक सुविधाएँ जनसाधारण को सुलभ हैं। माननीय मुख्यमंत्री नवनिर्माण के साथ **Sustainable development** के महत्व को समझते हुए अनुरक्षण एवं संधारण को भी **Equal footing** पर रखते हैं।

उसी के अनुरूप इस योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में चिन्हित ग्रामीण सड़कों के पुनर्निर्माण/उन्नयन द्वारा ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत किये जाने के उद्देश्य से विभिन्न योजना से निर्मित एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर हुए वैसे पथ जिनकी निरूपण अवधि पूर्ण हो चुकी है अथवा निरूपण अवधि के पूर्व ही निरूपित यातायात को प्राप्त कर लिया गया है के उन्नयनार्थ पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण किये जाने का प्रावधान है। इस योजना अंतर्गत कुल 856 पथों (कुल लम्बाई 3,034 किलोमीटर) का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए अबतक 751 पथों (कुल लम्बाई 2,786 किलोमीटर) का पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष कार्य निर्माण की विभिन्न चरणों में है।

<u>ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रमः–</u>

महोदय,

ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभिन्न मदों से निर्मित सभी ग्रामीण पथ जो पंचवर्षीय रूटिन अनुरक्षण अवधि/**Defect Liability** अवधि से बाहर हो चुके है उन सभी ग्रामीण पथों के रूप में सृजित परिसम्पतियों को क्षरण से बचाने हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना का नया घटक "ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" नवंबर, 2024 को लागू किया गया।

महोदय,

राहत इंदौरी कहते थे,

"आँधियों से कह दो अपनी औकात में रहें,
हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं।"

इसी बिहार में वर्ष 2005–06 में मात्र 8 सौ 35 कि0मी0 सड़कों के निर्माण हेतु योजनाएँ स्वीकृत की गई। आज मात्र इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2024–25 में 21 हजार 733 करोड़ रूपये के लागत से कुल 14,087 पथों (कुल लम्बाई 24,481 कि0मी0) तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 में 5 हजार 627 करोड़ रूपये के लागत से कुल 4,079 पथ (कुल लम्बाई 6,484 कि0मी0) की स्वीकृति प्रदान की गयी। इस प्रकार इस कार्यक्रम के अंतर्गत अबतक विगत मात्र दो सालों में कुल 27 हजार 360 करोड़ रूपये की लागत से कुल 18,166 पथों (कुल लम्बाई 30,966 कि0मी0) की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त कार्यो का निविदा निष्पादन पैकेज के माध्यम से करते हुए क्रियान्वयन कराया जा रहा है। वर्तमान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल स्वीकृत पथों में से 470 पथों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 9,176 कि0मी0 **Surface** का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। स्वीकृत

सभी पथों का **Initial Rectification, Minor Improvement** एवं **Surface Renewal** का कार्य अगले वित्तीय वर्ष 2026–27 में पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजनाः–

महोदय,

Every bridge shortens a distance - between markets, minds and opportunities.

पुल–पुलिया केवल यातायात को सुगम ही नहीं बनाते हैं, वो अवसर और संभावनाओं के सेतु होते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध सम्पर्कता हेतु छुटे हुए महत्त्वपूर्ण एवं जनोपयोगी पुल/पथ/पहुँच पथ का निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य कराने हेतु 'मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना' लागू किया गया है। इस योजना अंतर्गत पूर्व से निर्मित कई जर्जर पुल की जगह नए पुल का निर्माण, पूर्व से निर्मित पथ में **Missing Bridge** का निर्माण, बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुल की जगह नये पुल का निर्माण, निर्मित पुलों के पहुँच पथ का निर्माण, अद्यतन असम्पर्कित अवशेष टोलों/बसावटों को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु पुल–पुलियों का निर्माण, "जनता के दरबार में मुख्यमंत्री" कार्यक्रम से अच्छादित योजना एवं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक सभा में की गयी घोषणा से संबंधित पथों/पुलों का निर्माण करने का प्रावधान रखा गया।

इस योजना अंतर्गत अबतक कुल 909 पुलों का स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसमें से 660 पुलों का एकरारनामा किया गया है। पुलों के निर्माण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा पुलों के डिजाइन की तकनीकी **Vetting** राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर द्वारा करायी गयी है साथ ही मुख्यालय स्तर पर 6 तकनीकी विशेषज्ञों जिसमें मुख्यतः पथ निर्माण विभाग, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार से पुल निर्माण में निपुण वरीय अभियंताओं की सेवा लेते हुए सभी डी0पी0आर0 की गहन जाँच करते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ करने की दिशा में विभाग कार्य कर रहा है।

विभाग द्वारा निर्मित पुल संरचना के निरूपित लाईफ स्पैन के पूर्ण उपयोगिता हेतु ससमय रख–रखाव एवं प्रबंधन हेतु पथ निर्माण विभाग, बिहार द्वारा लागू की गयी बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति 2025 को अंगीकृत किया गया है। जिसका अनुपालन करने की दिशा में विभाग कार्य कर रहा है।

➢ ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजनाः–

महोदय,

"Good governance is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and promoting development."

डॉ0 भीम राव अम्बेडकर ने कहा था–

"मनुष्य का जीवन स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित होना चाहिए।"

ग्रामीण सड़कें इन तीनों मूल्यों को व्यवहारिक रूप देती हैं–

स्वतंत्रता (आवागमन की), समानता (अवसर की) और बंधुत्व (समाज से जुड़ाव की)। जब सड़क गाँव तक पहुँचती है, तो सबसे अधिक लाभ महिलाओं और वंचित वर्गों को मिलता है एवं अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग समाजिक मुख्यधारा से जुड़ते हैं।

विभाग द्वारा इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उपग्रह मानचित्र के विश्लेषण एवं स्थानीय सूचनाओं के आधार पर अनजुड़े टोलों/बसावटों की पहचान कर बसावटों का भौतिक सत्यापन तथा सर्वेक्षण कराया गया तथा प्रत्येक टोलों/बसावटों के संबंध में वर्तमान तथा प्रस्तावित सम्पर्कता, जनसंख्या, सम्र्कता के लिए आवश्यक पथ की लम्बाई तथा उपलब्ध सरकारी एवं रैयती भूमि के संबंध में वास्तविक सूचनाएँ संकलित की गयी।

ये टोलें अधिकांश रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अत्यंत पिछले वर्गों की बहुलता वाले थे, जिनको सम्पर्कता प्राप्त होने से उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास सुनिश्चित होगा। ऐसे सभी सर्वेक्षित अनजुड़े बसावटों को बारहमासी सड़कों के माध्यम से चरणबद्ध रूप में एकल सम्पर्कता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के "सात निश्चय" के तहत वित्तीय वर्ष 2016–17 में "ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना" प्रारंभ की गयी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के 100 से 249 तक की आबादी वाले अनजुड़े सर्वेक्षित टोलों को बारहमासी सड़कों के माध्यम से चरणबद्ध रुप में एकल सम्पर्कता प्रदान करना है। इस योजना अंतर्गत राज्य के कुल लक्षित 4,643 बसावटों/टोलों (कुल लम्बाई 3,977 कि0मी0) को सम्पर्कता प्रदान करते हुए 4,618 बसावटों/टोलों (कुल लम्बाई 3,968.41 कि0मी0) पथों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

<u>प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना</u>–

महोदय,

जॉन एफ. कैनेडी ने कहा था– **American roads are not good because America is rich; America is rich because American roads are good.** यह वाक्य हमें यह स्मरण कराता है कि अवसंरचना विलासिता नहीं, बल्कि विकास की पूर्वशर्त है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसी दिशा में, ग्रामीण पथों को संपर्कता प्रदान करने हेतु भारत सरकार का **Flagship scheme** रहा है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–**I** का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के 27 **Non-IAP** जिलों में 500 या उससे अधिक एवं 11 **IAP** जिलों में 250 या उससे अधिक एवं 47 चिह्नित प्रखंडों में 100 या उससे अधिक की आबादी वाले अनजुड़े गाँवों और बसावटों को बारहमासी सड़कों के माध्यम से चरणबद्ध रुप से एकल सम्पर्कता प्रदान करना है। अब तक कुल 31,280 पात्र बसावटों को संपर्कता प्रदान करते हुए 53,290 कि0मी0 पथों एवं 1,163 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है तथा 57 पथ एवं 34 पुल का कार्य निर्माण के विभिन्न चरणों में है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–**II** अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 2,456.47 कि0मी0 ग्रामीण पथों एवं 102 पुलों के विरूद्ध अब तक 2,442.33 कि0मी0 ग्रामीण पथों एवं 98 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है तथा शेष पथों एवं पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (चरण–**III**) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2024–25 तक 733 पथों, जिनकी लम्बाई–6162.17 कि0मी0 के उन्नयन एवं 709 पुलों (राशि 7,120.91 करोड़) की स्वीकृति ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है। इनमें से 5,224.31 करोड़ व्यय करते हुए 631 पथों, लम्बाई–5,410.70 कि0मी0 एवं 397 पुलों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 101 पथों, लम्बाई–593.21 कि0मी0 एवं 305 पुलों का कार्य निर्माण के विभिन्न चरणों में है।

महोदय,

ग्रामीण सड़कों/पुलों के रख–रखाव एवं मरम्मत हेतु गैर योजना मदः–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्राथमिकता के अनुरूप विभाग के अधीन निर्मित एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के पश्चात् पथों के नियमित एवं व्यवस्थित सुधार, मरम्मत एवं रख–रखाव हेतु "बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018 **(Bihar Rural Roads Maintenance Policy-2018** लागू की गई।

"A cubic millimeter of negligence can destroy kilometers of credibility."

उसी क्रम में यह नीति **Output & Performance** आधारित है, जिसके अंतर्गत राज्य में ग्रामीण सड़कों के निरीक्षण के लिए पहली बार **Bump Integrator Machine** द्वारा पथों के सतह की जाँच की जा रही है। इसमें पथों में **International Roughness Index (IRI)** मानक आधारित **4000 mm** प्रति कि0मी0 से कम पाये जाने पर ही भुगतान का प्रावधान किया गया है।

"सरकार मानती है कि जो सड़क गुणवत्ता से बनती है वही पीढ़ियों को जोड़ती है।"

अनुरक्षणाधीन पथों के मासिक एवं त्रैमासिक निरीक्षण एवं समयबद्ध सुधार एवं प्रतिक्रिया का तंत्र विकसित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा माह जनवरी 2026 तक 18,964.42 करोड़ (अठारह हजार नौ सौ चौंसठ करोड़ बयालीस लाख) रूपये की लागत से 16,166 पथों जिसकी लंबाई 40,245 किलोमीटर (चालीस हजार दो सौ पैंतालीस किलोमीटर) की मरम्मत, सुधार एवं नवीकरण के साथ पंचवर्षीय रखरखाव की स्वीकृति दी गयी है।

इसके विरूद्ध अबतक 15,521 पथों जिसकी लंबाई 37,583 किलोमीटर (सैंतीस हजार पाँच सौ तिरासी किलोमीटर) पथों का मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्य कराया गया है, शेष मरम्मति कार्य निर्माण के विभिन्न चरणों में है।

महोदय,

"उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथैः।"
कार्य केवल इच्छाओं से नहीं, परिश्रम और नीतिपूर्ण प्रशासन से सिद्ध होते हैं।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चार घंटे में राज्य के किसी कोने से पटना पहुँचने का संकल्प फलीभूत हो रहा है। ग्रामीण सड़कों को भी बढ़ते **Traffic** एवं आवागमन हेतु समुचित रूप से तैयार रखने हेतु सात निश्चय–3 के अधीन ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सुलभ सम्पर्कता के विस्तार के तहत ग्रामीण पथों को चरणबद्ध तरीके से चौड़ीकरण **(Intermediate Lane-5.5m)** किया जाना है। जिसके तहत प्रखंड/ अनुमंडल/जिला मुख्यालय तथा **SH/NH/MDR** को जोड़ने वाली महत्त्वपूर्ण सड़कों का सर्वेक्षण उपरांत चिन्हित कर निर्माण कराया जाना है।

इस दिशा में अतिशीघ्र अग्रेतर कार्रवाई करते हुए विभाग द्वारा एक **Mobile APP** विकसित किया गया, जिससे सर्वे कार्य पूरा करा लिया गया है। सरकारी भूमि की उपलब्धता के आधार पर कुल–595 पथ जिसकी लंबाई– 1887.86 कि0मी0 है, का भौतिक सत्यापन **Mobile APP** से कराये जाने के उपरांत निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर पथों की सूची संबंधित जिलाधिकारी से प्राप्त कर योजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा में अग्रेतर कार्य किया जायेगा।

<u>वित्तीय वर्ष 2025–26 की योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक स्थिति</u>

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2025–26 की योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक स्थिति से अवगत कराने की अनुमति चाहता हूँ।

<u>मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना</u> (अन्य राज्य योजना सहित) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 2,816 करोड़ रूपये का बजटीय उपबंध प्राप्त हुआ। अबतक कुल 1765.66 करोड़ रूपये व्यय करते हुए 1,728 कि0मी0 पथ एवं 196 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है, शेष राशि इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक व्यय कर लिया जायेगा।

<u>ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजनाः</u>– इस योजना के तहत अबतक कुल लक्षित 4618 बसावटों/टोलों को सम्पर्कता प्रदान करते हुए 3,968.41 कि0मी0 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

<u>प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना</u> :– इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 538.60 करोड़ रूपये व्यय कर 521.93 कि0मी0 पथ एवं 212 पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

<u>मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रमः</u>– इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 2,500 करोड़ रूपये का बजटीय उपबंध प्राप्त हुआ है। इसके विरूद्ध अब तक 1,758.13 करोड़ रूपये व्यय करते हुए लगभग 7,000 कि0मी0 ग्रामीण पथों का नवीनीकरण कार्य किए

जाने के लक्ष्य के विरूद्ध अबतक कुल 2,438 पथों जिनकी कुल लम्बाई 4,609 किलोमीटर है, का नवीनीकरण एवं अनुरक्षण कार्य कराया गया है, शेष नवीनीकरण कार्य निर्माण के विभिन्न चरणों में है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत 856 पथों जिनकी कुल लम्बाई 3,034 किलोमीटर है, का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए अबतक 751 पथों जिनकी कुल लम्बाई 2,786 किलोमीटर है, का पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण कार्य किया गया है तथा शेष पथों का उन्नयन कार्य कराया जा रहा है।

ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रमः– इस कार्यक्रम के अंतर्गत अबतक कुल 27,360 करोड़ रूपये के लागत से कुल 18,166 पथों (कुल लम्बाई 30,966 कि0मी0) की स्वीकृति प्रदान करते हुए 470 पथों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 9,176 कि0मी0 **Surface** का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष पथों का कार्य कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजनाः– इस योजना अंतर्गत अबतक कुल 909 पुलों का स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसमें से 660 पुलों का एकरारनामा किया गया है। पुलों के निर्माण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा पुलो के डिजाइन की तकनीकी **Vetting** राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर द्वारा करायी गयी है साथ ही मुख्यालय स्तर पर 6 तकनीकी विशेषज्ञों जिसमें मुख्यतः पथ निर्माण विभाग, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार से पुल निर्माण में निपुण वरीय अभियंताओं की सेवा लेते हुए सभी डी0पी0आर0 की गहन जाँच करते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ करने की दिशा में विभाग कार्य कर रहा है।

सुलभ संपर्कता योजना– ग्रामीण क्षेत्र में निर्बाध यातायात हेतु पंचायतों/प्रखंडों/अनुमंडलों/जिला के महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक संस्थान तथा विभिन्न महत्त्वपूर्ण सुविधाएँ यथा अस्पताल, शिक्षण संस्थान, बाजार, बैंक, पर्यटन स्थल को महत्त्वपूर्ण उच्च स्तर के पथों यथा राष्ट्रीय उच्च पथ/राज्य उच्च पथ/वृहद जिला पथ **(NH/SH/MDR)** से जोड़ने के क्रम में सुलभ मार्ग/वैकल्पिक मार्ग (थ्रू रूट/बाईपास) का नवनिर्माण /पुननिर्माण किया जाना है।

इसके तहत वित्तीय वर्श 2025–26 में पथों/पुलों के निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा अनुशंसा किए जाने के उपरांत विभाग द्वारा कुल 74 योजनाओं का चयन किया गया हैं जिसमें 65 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति (कुल राशि 356.43138 करोड़ रू0) प्रदान की गई है एवं 09 योजनाएँ प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया में है। इसके अन्तर्गत अब तक कुल 16 योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

ग्रामीण कार्य विभाग ग्रामीण सड़कों एवं पुलों के निर्माण के साथ–साथ गुणवत्ता निर्धारण करने के लिए भी गंभीर है।

महोदय,

सरकार का मानना है कि

Quality control is the insurance policy of public infrastructure."

ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत विभिन्न राज्य योजनाओं द्वारा निर्मित ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता निर्धारित मानक विशिष्टियों के अनुसार बनाए रखने के लिए त्रिस्तरीय निरीक्षण प्रणाली लागू की गई है। जिसमें त्रिस्तरीय गुणवत्ता निरीक्षण का कार्य क्रमबद्ध रूप से क्षेत्रीय अभियंताओं एवं स्वतंत्र अभियंताओं द्वारा किया जा रहा है, जिसमें योजनाओं में निर्माण के अवधि में पायी गयी त्रुटियों का आवश्यक सुधार कराया जा रहा है।

Bihar Rural Road Routine Maintenance System (BRRMS):-

महोदय,

राज्य योजना अन्तर्गत निर्मित पंचवर्शीय अनुरक्षणाधीन पथों के निरीक्षण हेतु विभाग के द्वारा **BRRMS Mobile App** विकसित किया गया है जिसके माध्यम से पथ के लम्बाई 2.00 कि0मी0 तक होने पर 200 मी0 तथा 2.00 कि0मी0 से ज्यादा लम्बाई वाले पथों में 500 मी0 पर **Random Chainage** पर पथों का निरीक्षण किया जा रहा है जिसमें निरीक्षण के क्रम मे पथ आरेखन के विभिन्न अवयवों का **Geo tagged** फोटोग्राफ अपलोड किया जा रहा है, जिसके आधार पर पथों में नियमित अनुरक्षण किया जा रहा है। इस नये तकनीक के आरंभ से अभी तक की कालावधि में पंचवर्षीय अनुरक्षणाधीन पथों के 109831 निरीक्षण किये जा चुके हैं।

महोदय,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय लोक सेवाओं एवं शिकायत निवारण को कानूनी जामा पहनाकर एवं अपनी यात्राओं में बिहार वासियों से सीधा संवाद स्थापित कर शासन में जन भागीदारी और **Feedback** को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा भी उसी क्रम में पंचवर्षीय अनुरक्षणाधीन ग्रामीण पथों/पुलों के अनुरक्षण के संबंध में आमजनों से शिकायत प्राप्त करने एवं इसका समाधान हेतु विभाग के द्वारा **Hamara Bihar Hamari Sadak (HBHS) App** विकसित किया गया है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता द्वारा स्थानीय स्तर पर ग्रामीण सड़कों/पुलों का चयन कर अद्यतन भौतिक स्थिति, यथा गड्ढों या अन्य समस्याओं की संक्षिप्त विवरण एवं जहाँ पथ खराब है उस स्थान का फोटोग्राफ **APP** के माध्यम से अपलोड कर शिकायत दर्ज किया जाता है। उस शिकायत को संबंधित प्रमण्डल द्वारा ठीक कराने के उपरांत पुनः उस स्थल का फोटोग्राफ सहित प्रतिवेदन अपलोड किया जाता है। जिसे शिकायतकर्ता द्वारा अपने लॉग इन आई0डी0 पर देखा जाता है। इस नये तकनीक के आरंभ से अभी तक की कालावधि में पंचवर्षीय अनुरक्षणाधीन ग्रामीण पथों/पुलों की अनुरक्षण के संबंध में आमजनों से अबतक कुल प्राप्त 2,185 शिकायतों में से 2,073 शिकायत का निवारण कर दिया गया है एवं शेष शिकायतों को सीमित समय सीमा के अंदर निवारण करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

महोदय,

सरकार का मानना है कि **"An organization grows only as fast as its people grow."** उसी क्रम में विभाग अन्तर्गत कार्यरत नवनियुक्त 480 सहायक अभियंताओं (असैनिक) को अपने क्षेत्राधीन क्रियान्वित की जा रही पथों एवं पुलों के निर्माण में तकनीकी

मानकों के अनुरूप कार्य करने, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं नये तकनीकों का उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु **IIT, Patna** में चरणबद्ध रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिसमे अबतक 120 सहायक अभियंताओं को प्रशिक्षण दिया गया है तथा शेष 360 सहायक अभियंताओं को प्रशिक्षण जुलाई, 2026 तक दिये जाने का लक्ष्य है।

"Training is not an expense; it is an investment in human potential."

विभाग अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य में ग्रामीण सड़कों का एक विशाल नेटवर्क तैयार किया है। सृजित सड़क सम्पत्तियों के लिए निरंतर रख–रखाव की आवश्यकता होती है, जिसे पूरा करना बहुत बड़ा कार्य है। ग्रामीण सड़कों की फेसलेस स्वशासी निगरानी एवं रख–रखाव के लिए नये तकनीक विकसित कर रहा है।

"The best infrastructure in the world fails without trained hands to sustain it." ग्रामीण पथों के पचंवर्षीय अनुरक्षण को सुदृढ़ करने हेतु मानव हस्तक्षेप रहित आधुनिक तकनीक को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए विभाग अग्रेतर कार्रवाई कर रहा है।

महोदय,

आज दुनिया में भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत से बड़ी **GPP** वाले तीनों देशों में अमेरिका, चीन एवं जर्मनी शामिल है।

मैंने तीनों में अन्य मापदंडो के अलावा विकास का एक समान **Pattern** देखा।

अमेरिका ने 19 वीं शताब्दी में **Rural Electrification** पर जोर दिया एवं 1950 के दशक में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर, ने **Interstate Highway System** का निर्माण कर पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा दिया। चीन ने पिछले तीन दशकों में अपने ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक सड़क निर्माण कार्यक्रम चलाया। जर्मनी ने 50 के दशक में **Autobahn** एवं **Rural connectivity expansion** कार्यक्रम अपनाया।

इसी प्रकार दक्षिण कोरिया ने सेमाउल आंदोलन चलाकर ग्रामीण अवसंरचना के विकास, विशेषकर सड़कों, पुलों एवं सामुदायिक सुविधाओं का निर्माण कर ग्रामीण पुनर्जागरण की नींव रख दी।

चाणक्य अर्थशास्त्र में राजा के कर्तव्य के बारे में बताते हैं कि

"The king shall construct roads, causeways, bridges, reservoirs and ensure their protection."

राजा का कर्तव्य है कि वह मार्ग, सेतु जलाशय और व्यापार–सुविधाएँ विकसित करे तथा उनका संरक्षण सुनिश्चित करे।

महोदय,

हमारे दूरदर्शी माननीय मुख्यमंत्री बिहार में इसी प्रकार सर्वांगीण और आधारभूत संरचना के विकास के नये स्वर्णिम अध्याय को लिख रहे हैं। उनके नेतृत्व में बिहार में **GSDP** का विकास दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है एवं बिहार सबसे तेजी से विकास करनेवाले राज्यों में शामिल है।

मैंने उनके सानिध्य में यह पाया है कि यह प्रार्थना उनके मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कायम है

"सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्।।"

यह केवल आध्यात्मिक वाक्य नहीं, बल्कि उनके नीति–निर्माण का नैतिक आधार है।

(५)

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2026–27 जिसका समापन 31.03.2027 को होना है, विभाग की योजनाओं के व्यय की पूर्ति हेतु 11,312.1799 करोड़ रूपये (ग्यारह हजार तीन सौ बारह करोड़ सत्रह लाख निन्यानबे हजार) रुपये मात्र की योजना (परिशिष्ट–'क', एवं 'ख' संलग्न) का सदन के समक्ष प्रस्ताव रखता हूँ तथा माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि इसकी अनुमति प्रदान करें।

परिशिष्ट 'क'

मांग संख्या–37

ग्रामीण कार्य विभाग

क्रम सं0	योजना का नाम	2026–27 में प्रावधानित राशि (लाख रुपये में)
1	2	3
1	मुआवजा एवं अदायगी **(Compensation)**	**3000.00**
2	बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण **(BRRDA)**	**4000.00**
3	पी0एम0जी0एस0वाई (केन्द्रांश)	**50000.00**
4	पी0एम0जी0एस0वाई (राज्यांश)	**13333.00**
5	ग्राम विकास की परियोजनाए (नाबार्ड सम्पोषित योजना)	**50000.00**
6	मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना **(MMGSY)**	**1000.00**
7	ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना	**10000.00**
8	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना **(MMGSY SCSP (MMGSY))**	**500.00**
9	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना)	**71955.00**
10	जनजातीय क्षेत्र उप योजना (मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना)	**100.00**
11	मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (एन0डी0बी0 ब्रिक्स बैक सम्पोशित)	**60000.00**
12	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना	**507981.00**
13	जनजातीय क्षेत्र उप योजना (मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना)	**0.00**
14	मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष)	**10000.00**
15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष)	**70000.00**
16	मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना	**10000.00**
17	जन जातियों क्षेत्र उप योजना (मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष)	**11474.00**
18	अतिरिक्त सम्पर्कता (सुलभ संपर्कता निश्चय–2)	**17000.00**

	कुल	**890343.0000**

परिशिष्ट 'ख'
स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय

क्रम सं0	शीर्ष/उप शीर्ष	2026–27 में प्रावधानित राशि (लाख रुपये में)
1	2	3
1	2515 –वेतनादि (अभियंत्रण स्थापना)	**39248.08**
2	3054–सड़क तथा सेतु रख–रखाव	**200000.00**
3	3451 वेतनादि (सचिवालय सेवाएं)	**1626.91**
	कुल	**240874.9900**

कुल (राज्य स्कीम + स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय) = **(890343.00+240874.99)**

= **11,312,17.9900** लाख रूपये मात्र।

= **11,312.1799** करोड़ रूपये मात्र।

(ग्यारह हजार तीन सौ बारह करोड़ सत्रह लाख निन्यानबे हजार) रुपये मात्र।